

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली

iipa.org.in



गाँधीजी का तिलिस्म

“मैं तुम्हें एक तिलिस्म दूँगा। जब भी तुम्हें संदेह हो अथवा तुम्हारा अहम् प्रबल होता दिखाई दे, तो यह कसौटी आजमा कर देखो:

तब उस सबसे गरीब और निर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा है और फिर अपने आप से पूछो कि तुम जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो क्या वह उस आदमी के लिए उपयोगी होगा? क्या उससे उसको कुछ लाभ होगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण रख सकेगा? दूसरे शब्दों में, क्या उससे उन करोड़ों भूखे और अतृप्त लोगों को स्वराज्य मिलेगा?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त हो रहा है।”



M.K. Gandhi

मोहनदास
करमचंद गाँधी

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002



69वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2022-2023

रिपोर्ट को 31 अक्टूबर, 2023 को साधारण निकाय की संपन्न
वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया गया।

केंद्र और राज्य स्तर पर शासन के कार्यों के प्रबंधन हेतु अपेक्षित ज्ञान, कौशल और व्यवहार के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से लोक सेवकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए) की स्थापना की गई थी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यकारी के नेतृत्व, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के अपने प्रयासों में, संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। संस्थान के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम इसकी विशाल सूचना प्रबंधन और अनुभव-साझाकरण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

आई.आई.पी.ए का उद्देश्य अपने जनकों के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए लोक प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर विचार और प्रभाव से विश्व के अग्रणी शैक्षणिक केंद्रों में से एक बनना है ताकि शासन प्रणालियों को नागरिकों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी और एक लोकतांत्रिक समाज में मानवीय मूल्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

कार्यकारी परिषद्
(01.4.2022 से 31.03.2023 तक)

सभापति
श्री जगदीप धनखड़
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति
6, मौलाना आज़ाद रोड
नई दिल्ली- 110011

अध्यक्ष
डॉ. जितेंद्र सिंह
माननीय राज्य मंत्री
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

कार्यकारी परिषद् के सदस्य

श्री शेखर दत्त
(छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल)
फ्लैट सं. सी-805, 8वीं मंज़िल, कीनवुड टॉवर,
चार्मवुड विलेज,
सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद- 121009 (हरियाणा)

श्री एस. एस. क्षत्रिय, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
(पूर्व महाराष्ट्र के प्रधान सचिव)
भू-तल, मंत्रालय मेन,
हुतात्मा राजगुरु चौक
मैडम कामा रोड, मुंबई-400032

श्री श्रीनिवास आर. कटिकिथला
निदेशक
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी-248179 (उत्तराखंड)

प्रो. रेनु विज
कुलपति
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़-160014

श्री बी.आर. शर्मा, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष,
जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रीय शाखा
3/6, चन्नी हिम्मत कॉलोनी,
पीएनबी के निकट जम्मू-180015
(जम्मू एवं कश्मीर)

श्री टी.एम. विजय भास्कर, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष,
कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा
कमरा नंबर 4, भूतल, 5वां स्टेच,
एम.एस. बिल्डिंग, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विधि,
बेंगलुरु-560001

श्री विजय प्रकाश, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष,
बिहार क्षेत्रीय शाखा बिहार विद्यापीठ पटना-800010

श्री के.के. सेठी, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा,
सी/ओ प्रशासन अकादमी
चैंबर नंबर जी-3, आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन
अकादमी, 1100 क्वार्टर, भोपाल-462016

श्री पी.सी. लॉमकुंगा, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष, मिजोरम क्षेत्रीय शाखा
मकान नंबर 2/1-8, मिसडियन वेंगथलांग
हमिंगलियानी बेकरी के निकट
आइज़ोल -796001 (मिजोरम)

डॉ. टी. वी. सोमनाथन
सचिव, व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
कक्ष संख्या-129-अ,
नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001

प्रो. के.के. पाण्डेय
भा.लो.प्र.सं.
नई दिल्ली- 110002

सुश्री एस. राधा चौहान
सचिव (कार्मिक)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा नंबर 112, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नीति आयोग,
भारत सरकार
नीति भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

सदस्य सचिव

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
महानिदेशक
भारतीय लोक प्रस्थान संस्थान,
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली- 110002

डॉ. जितेन्द्र सिंह

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय,
राज्यमंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
राज्यमंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग
भारत सरकार



संदेश

Dr. JITENDRA SINGH

Minister of State (Independent Charge)
of the Ministry of Science and Technology;
Minister of State in the Prime Minister's Office;
Minister of State in the Ministry of Personnel,
Public Grievances and Pensions;
Minister of State in the Department of Atomic Energy and
Department of Space
Government of India

मुझे भा.लो.प्र.सं. के 69 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित प्रकाशन की वार्षिक रिपोर्ट के लिए यह संदेश लिखते हुए खुशी महसूस हो रही है, जो वर्ष 2022-23 लिए संस्थान की पूरे वर्ष की गतिविधियों का सारांशित संस्करण है।

वर्ष 2022-23 में भा.लो.प्र.सं. को कई चीजें पहली बार हासिल होंगी। कोविड-19 महामारी के सदमे को पूरी तरह झेलने के बाद, भा.लो.प्र.सं. ने खुद को कई नवोन्मेषी क्षेत्रों में फिर से स्थापित किया है। एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, भा.लो.प्र.सं. ने उत्तर प्रदेश के जिला सुशासन सूचकांक परियोजना, डीजीजीआई-यूपी की शुरुआत की है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के दृष्टिबाधित न्यायाधीशों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है और न केवल 'चयनित' अधिकारियों बल्कि शहरी स्थानीय निकायों के 'निर्वाचित' जन प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये।

मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि भा.लो.प्र.सं. ने अपनी आउटरीच और सहयोगात्मक गतिविधियों में वृद्धि की है और विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी में, यह अब राज्य सरकारों जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के परिवीक्षाधीन, मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और निर्देश के साथ, सरकार ने सिविल सेवाओं की क्षमता निर्माण में पूर्ण परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) शुरू किया है। हम नियम-आधारित प्रणाली से भूमिका-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। आई.आई.पी.ए ने तुरंत तर्क दिया कि यह भविष्य के लिए अवसर है और उसने खुद को मिशन कर्मयोगी के साथ एकीकृत कर लिया। भा.लो.प्र.सं. अब डिजिटल प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है जिसने आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम अपलोड किये हैं। इसके अलावा, भा.लो.प्र.सं. भविष्य के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपने स्वयं के एलएमएस के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। यह सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि लम्बे प्रतिबंध के बाद 1 जनवरी, 2021 को फिर से खुलने के बाद से भा.लो.प्र.सं. की सदस्यता में शानदार वृद्धि हो रही है। भा.लो.प्र.सं. ने वर्ष 2022-23 में 275 आजीवन सदस्यों को शामिल किया है और उनमें से अधिकांश सिविल सेवक और शिक्षाविद हैं, यह जानकर खुशी हो रही है। भा.लो.प्र.सं. ने क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं के साथ सक्रिय रूप से सदस्यता अभियान भी शुरू किया है जो इसके आधार को अधिक मजबूत करेगा। राज्यों में भा.लो.प्र.सं. शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार के कारण, कई राज्य सिविल सेवक भी भा.लो.प्र.सं. सदस्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं जो हमारे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भा.लो.प्र.सं. की पहुंच और प्रतिष्ठा को अधिक मजबूत करेगा।

कई नवीन गतिविधियों के बीच, क्षेत्रीय शाखाएँ अपने क्षेत्र में एक जिले का चयन करके जिला स्तरीय शासन का दस्तावेजीकरण कर रही हैं। यह गतिविधि न केवल जिला प्रशासन और शासन को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू करेगी बल्कि क्षेत्रीय शाखाओं को भी मजबूत करेगी।

मैं भा.लो.प्र.सं. टीम को बधाई देता हूँ और वैश्विक संकट के इस समय में भा.लो.प्र.सं. की सच्ची भावना को बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों की हार्दिक सराहना करता हूँ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह

एमबीबीएस (स्टैनले, चेन्नई)

एमडीमेडिसिन, फैलोशिप (अ.भा.आ.सं., एनडीएल)

एमएनएमएस (मधुमेह एवं अंतः स्रावी विज्ञान)

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग

नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23316766, 23714230

फैक्स: 011-23316745

साउथ ब्लॉक नई दिल्ली-110011

दूरभाष: 011-23010191 फैक्स: 011-23017931

नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली-110001

दूरभाष: 011-23092475 फैक्स: 011-23092716

महानिदेशक की ओर से

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. श्री जगदीप धनखड़ जी और माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद डॉ. जितेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में, भा.लो.प्र.सं. वर्ष 2022-23 में गर्व से आगे बढ़ चुका है।

वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. ने 17 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं और 127 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। भा.लो.प्र.सं. द्वारा वर्ष 2022-23 में भारत सरकार, राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों के कुल 11313 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। भा.लो.प्र.सं. ने पेशेवर सहायता, पंचायत चुनावों पर नीति अनुसंधान, पंचायत और विवाद समाधान पर नीति अध्ययन, डीएमआरसी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आंकलन इत्यादि प्रदान करके भारत में एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय नीति में सहभागिता की। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक सुधार विभाग और लोक शिकायत (डीएआरपीजी) के सहयोग से भा.लो.प्र.सं. ने उत्तर प्रदेश राज्य (डीजीजीआई-यूपी) के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया। वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से भारत सरकार के 2020 बैच के सहायक सचिवों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का सौभाग्य मिला। भा.लो.प्र.सं. ने मुख्य रूप से राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के सहयोग से राज्य सरकारों के परिवीक्षाधीनों और अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. ने राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

डीओपीटी द्वारा भा.लो.प्र.सं. को सौंपे गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक आईएस इंटेक स्टडी है। रिपोर्ट डीओपीटी को सौंप दी गई है।

लोक प्रशासन में 48वां उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीपीए) 1 जुलाई, 2022 को शुरू हुआ, जिसका माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी एपीपीपीए प्रतिभागियों को भारतीय रक्षा बलों के तीन सेवा प्रमुखों, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी और नौसेना स्टाफ के प्रमुख, एडमिरल आर हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी को सुनने का मौका मिला।

भा.लो.प्र.सं. ने 'रिपोजिशनिंग इंडिया @2047: राष्ट्र निर्माण के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर दोबारा गौर करना' विषय पर उद्घाटन डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय कूटनीति @75, कृषि में आत्मनिर्भर भारत, नागरिक-सैन्य संबंध, ब्लॉकचेन, वाइब्रेंट इंडिया @75, और यूक्रेन में युद्ध इत्यादि जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बहुत प्रासंगिक विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

भा.लो.प्र.सं. ने माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की सलाह पर भा.लो.प्र.सं. की पहुंच का विस्तार करने और अन्य प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए विशेष पहल की है। वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. ने उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी), पांडिचेरी विश्वविद्यालय,

आईआईटी रूड़की, अमेजन इत्यादि के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इन सहयोगों के परिणामस्वरूप भविष्य में क्षमता निर्माण और अनुसंधान परियोजनाओं में अधिक अवसर मिलेंगे।

भा.लो.प्र.सं. ने अपनी आजीवन सदस्यता भी 17 जनवरी, 2019 से शुरू की। पूरे भारत में क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं और इच्छुक सदस्यों के कई अनुरोधों के मद्देनजर एक लंबी रोक के बाद भा.लो.प्र.सं. ने 1 जनवरी, 2021 से अपनी आजीवन सदस्यता भी खोल दी। तब से, भा.लो.प्र.सं. ने सभी लंबित आवेदनों की जांच की है और पात्र आवेदकों को सदस्यता प्रदान की है। भा.लो.प्र.सं. ने सदस्यता अभियान भी शुरू किया है और सभी क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. ने 275 आजीवन सदस्य, चार सहयोगी सदस्य और 36 विद्यार्थी सदस्य शामिल किए।

ज्ञान प्रसार के मोर्चे पर, दूरदराज के स्थानों से भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय के डिजिटल रिपॉजिटरी के संचालन ने भा.लो.प्र.सं. को अब अकादमिक दुनिया के कोने-कोने तक अपने पंख फैलाने में मदद की है। भा.लो.प्र.सं. वर्ष 2022-23 में कई प्रकाशन लेकर आया है।

अपने प्रमुख जर्नल आईजेपीए और लोक प्रशासन, नगरलोक, डीपीए और आईआईपीए डाइजेस्ट जैसे अन्य जर्नलों के साथ, भा.लो.प्र.सं. ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पर एक पुस्तक 'भारत रत्न : राजेंद्र प्रसाद के प्रेरक कार्य', भा.लो.प्र.सं. कॉफी टेबल पुस्तक, 'चित्रों में भा.लो.प्र.सं. की अब तक की यात्रा और 'आत्मनिर्भर भारत के चालक' प्रकाशित की।

यादगार घटनाओं में से, भा.लो.प्र.सं. ने 31 अक्टूबर, 2022 को आमसभा की अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. श्री जगदीप धनखड़ जी मुख्य अतिथि ने की और जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद् डॉ. जीतेन्द्र सिंह जी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित दर्ज की। भा.लो.प्र.सं. ने 29 मार्च 2023 को अपना 69वां संस्थापक दिवस मनाया, जिसमें किसी और ने नहीं बल्कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने 'शासन : शक्तियों का पृथक्करण' विषय पर मुख्य भाषण दिया।

भा.लो.प्र.सं. पूरे भारत में सुशासन और ई-गवर्नेंस पर आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में डीएआरपीजी, सरकार का एक सक्रिय भागीदार रहा है।

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भा.लो.प्र.सं. में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) परियोजना को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अल्पवधि में अनुसंधान परियोजनाओं से आईआईपीए की आय प्रभावित हुई है। हालाँकि, हमें विश्वास है कि भा.लो.प्र.सं. दीर्घावधि में अन्य परियोजनाओं के साथ मिलकर काम करेगा।

संस्थान केंद्र और राज्यों में डीओपीटी एवं अन्य मंत्रालयों और भा.लो.प्र.सं. में प्रशिक्षण, अनुसंधान, कार्यशालाओं और सेमिनारों तथा अन्य गतिविधियों के लिए उनके समर्थन के लिए ज्ञान आधार को लगातार उन्नत करने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने के सरकारी प्रयासों में सहायता

के लिए अन्य सभी एजेंसियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं., माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. इसी और कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए निरंतर समर्थन के लिए अपना आभार और सराहना दर्ज करते हैं।

संस्थान के समग्र विकास में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं के सभी पदाधिकारियों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी संस्थान धन्यवाद देता है। हम भा.लो.प्र.सं. के भीतर और बाहर उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने हमारी सहायता की है और वर्ष के दौरान हमारी गतिविधियों और प्रयासों की सफलता में योगदान दिया है और आगे भी ऐसा करने की आशा करते हैं।



(सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

महानिदेशक

विषय सूची

	पृष्ठ
माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद का संदेश	v
महानिदेशक की कलम से-	vii
एक अवलोकन	1
प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम	1
सूचना प्रबंधन	5
प्रकाशन	5
पुस्तकालय	6
सहयोगी गतिविधियां	8
आम निकाय की अड़सठवीं वार्षिक बैठक	8
छियासठवें सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन	9
कार्यकारी परिषद	9
सदस्यता	9
भा.लो.प्र.सं. के विशिष्ट सदस्यों को पॉल एच. एपल द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया	9
वर्ष 2022 हेतु इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आई.जे.पी.ए) में सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए श्री टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार	10
क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाएँ और सदस्यों की गतिविधियाँ	10
आगे बढ़ाने संबंधी (आउटरीच) गतिविधियाँ	11
निबंध प्रतियोगिता	14
केस अध्ययन प्रोग्राम	14
ढांचागत सुधार	15
संस्थान के वित्त	15
महत्वपूर्ण घटनाएं	15
सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/व्याख्यान	15
शैक्षणिक केंद्र/चेयर्स	22
प्रशासकीय एवं कार्मिक मामले	25
वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए टी.ए/डी.ए और मानदेय का विवरण	26
दिनांक 01-4-2022 से दिनांक 31-3-2023 तक ई.सी और अन्य समिति की बैठकों/शाखाओं के पदाधिकारियों में टी.ए/डी.ए का विवरण	26
वर्ष 2022-2023 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय और वेतन का विवरण	26
आभार	26

वित्त एवं लेखा	27
अनुलग्नक	30
एफ.1 (ए) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं	30
एफ.1 (बी) अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक चल रही अनुसंधान परियोजनाएं	32
एफ.2 अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	33
एफ.3 शाखाओं की गतिविधियाँ (वर्ष 2022-2023)	45
एफ.3.1 क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं के अध्यक्ष एवं मानद सचिवों की सूची (दिनांक 31-03-2023 तक)	53
एफ.3.2 दिनांक 31-03-2023 को क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं से जुड़े सदस्यों की सूची	54
एफ.4 शैक्षणिक केंद्र 2022-23	57
एफ.5 भा.लो.प्र.सं. संकाय और अन्य के अकादमिक योगदान (प्रशिक्षण और अनुसंधान अध्ययन के अलावा)	58
एफ.6 वर्ष 2022-2023 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण	105
एफ.7 दिनांक 31.03.2023 तक भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखाओं से जुड़े संकाय सदस्य	108
एफ.8 संकाय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी (दिनांक 31-03-2023 तक)	109
एफ.9 शहरी अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ	111
एफ.10 वर्ष 2021-23 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय और वेतन का विवरण	116
वर्ष 2022-23 के लिए तुलन-पत्र और खातों के लेखा परीक्षित विवरण	117

संस्थान की गतिविधियों की रिपोर्ट

(2022-2023)

एक अवलोकन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की यह रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 से संबंधित है। संस्थान मौलिक और समकालीन मुद्दों के साथ-साथ सरकारों, राष्ट्रीय संगठनों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करता है। यह सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को परिचालन क्षेत्रों में सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करता है। यह लोक प्रशासन और प्रबंधन के अध्ययन और प्रैक्टिस के विभिन्न स्वरूपों और पहलुओं पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और भारत और विदेशों से प्रत्येक वर्ष 10000 से अधिक अधिकारियों और सिविल सोसायटी के सदस्यों को प्रशिक्षित करता है। यह विशेष प्रकाशनों और जर्नलों के माध्यम से लोक प्रशासन पर साहित्य का प्रकाशन और प्रसार भी करता है।

रिपोर्ट निम्नलिखित चार प्रमुख शीर्षों के तहत संस्थान की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है :

- प्रशिक्षण
- अनुसंधान गतिविधियाँ
- सूचना प्रबंधन
- सहयोगी और आउटरीच गतिविधियाँ

रिपोर्ट में निम्नलिखित के बारे में जानकारी शामिल है :

- संस्थान के वित्त
- अकादमिक कार्यक्रम जैसे सेमिनार, सम्मेलन व्याख्यान, दौरे, पुस्तक विमोचन इत्यादि।
- भा.लो.प्र.सं. की विभिन्न समितियों और केंद्रों की गतिविधि रिपोर्ट
- संकाय की शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रशासनिक और कार्मिक मामले

प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रम

संस्थान ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

1. **दीर्घकालिक कार्यक्रम:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी), भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (ए.पी.पी.पी.ए) शामिल हैं।
2. **प्रायोजित कार्यक्रम:** मुख्य रूप से (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, (ख) शहरी विकास मंत्रालय, (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, (घ) उपभोक्ता मामले विभाग, और (ड.) अन्य मंत्रालयों/विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि द्वारा प्रायोजित।
3. **शुल्क-आधारित कार्यक्रम:** उपयोगकर्ता संगठन के साथ-साथ अपनी पहल पर संस्थान द्वारा डिजाइन प्रस्तुत किया गया।

लोक प्रशासन पर 48वां उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (2022-2023)

संक्षिप्त रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए) द्वारा सशस्त्र बलों सहित अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 01 जुलाई, 2022 से 28 अप्रैल, 2023 तक लोक प्रशासन में 48वां उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (ए.पी.पी.पी.ए), एक कस्टमाइज्ड दस महीने का पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पाठ्यक्रम में नागरिक और रक्षा सेवाओं के 38 वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने कार्यक्रम को प्रायोजित किया, और पंजाब विश्वविद्यालय ने

विश्वविद्यालय की एम.फिल. डिग्री के लिए इसके संचालन में सहयोग किया।

उद्घाटन सत्र

माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1 जुलाई, 2022 को प्रोग्राम के साथ-साथ नवनिर्मित हॉल (समृद्ध) का उद्घाटन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1 जुलाई 2022 को कार्यक्रम के साथ-साथ नव पुनर्निर्मित एपीपीए हॉल (समृद्ध) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने सामान्य समाधान और बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि भा.लो.प्र.सं. द्वारा अधिक एकीकृत, समग्र और समन्वित दृष्टिकोण इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान है, जिससे प्रतिभागियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिलता है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष जताया कि वर्ष 2022-23 के लिए एपीपीपीए पाठ्यक्रम के संचालन और सामग्री में बदलाव आया है और मिशन कर्मयोगी, आत्मनिर्भर भारत और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पहलों के नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को बेहतर ढंग से समझने और सराहना करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर, भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया और प्रोफेसर वी.एन आलोक, पाठ्यक्रम निदेशक, 48वें एपीपीपीए ने 48वें एपीपीपीए की रूपरेखा प्रस्तुत की और भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया। अपर कार्यक्रम निदेशक डॉ. कुसुम लता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों, भा.लो.प्र.सं. संकाय सदस्यों और भा.लो.प्र.सं. के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम (प्रोग्राम)

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में योगदान करने के

लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य और तालमेल विकसित करने में सक्षम बनाना है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करता है जो नागरिकों के प्रति दक्षता, सेवा अभिविन्यास को बढ़ाता है।

उद्देश्य

पाठ्यक्रम के बताए गए मुख्य उद्देश्य हैं:

- मध्यम और वरिष्ठ स्तर के सिविल सेवकों को अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर प्रदान करना।
- व्यवहार विज्ञान में हाल में हुए विकास और प्रशासन में इसके अनुप्रयोग का ज्ञान आयात करना।
- प्रतिभागियों को प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल में विकास से परिचित कराना; और
- प्रशासनिक प्रणाली के कामकाज पर प्रभाव डालने वाले पर्यावरण और अन्य कारकों के एक महत्वपूर्ण विश्लेषण को सक्षम करना।

क. शैक्षणिक मॉड्यूल

अवधारणाएँ और अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शासन के मुद्दों और अध्ययन के संबंधित क्षेत्रों में हाल के विकास के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर शाखाओं (स्ट्रीम्स) की पहचान की गई है। एक क्रेडिट वाली शाखा (स्ट्रीम) में सोलह व्याख्यान सत्र थे। बारह सत्रों में आधे क्रेडिट स्ट्रीम को कवर किया गया। इन शाखाओं (स्ट्रीम्स) को आगे पाँच भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल हैं :

क.I: सिद्धांत, अवधारणाएँ और व्यवहार

क.II: राज्य और शासन

क.III: नीति परिशिष्ट की खोज

क.IV: समसामयिक चुनौतियाँ, वित्त और प्रबंधन

क.V: सिविल सेवाओं के लिए योग्यता रूपरेखा (मिशन कर्मयोगी)

पहला उप-मॉड्यूल क.I: सिद्धांतों, अवधारणाओं और व्यवहारों पर परिचयात्मक मॉड्यूल जिसमें (ए) लोक प्रशासन की गतिशीलता, (बी) भारतीय अर्थव्यवस्था

और सार्वजनिक वित्त, (सी) प्रशासनिक कानून और नियामक संस्थान, (डी) सार्वजनिक नीति अनुसंधान: कार्यप्रणाली अनुसंधान पद्धति, ई) संचालन और परियोजना प्रबंधन, (एफ) सार्वजनिक नीति और संसदीय प्रक्रिया और कार्यपद्धतियाँ और (जी) मानव संसाधन प्रबंधन जुलाई-अगस्त 2022 के दौरान व्याख्यान और मूल्यांकन के साथ आयोजित किया गया था।

दूसरा उप-मॉड्यूल क.II: राज्य और शासन जिसमें

- ए) आपदा प्रबंधन: नागरिक-रक्षा सहयोग,
- बी) विकास चालक: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र,
- सी) जिला स्तरीय शासन: संरचना और प्रक्रिया,
- डी) विजन इंडिया @2047: गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा भूमि (रेल, सड़क), जल, वायु शक्ति/ऊर्जा,
- ई) जलवायु स्मार्ट प्रशासन,
- एफ) डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन
- जी) आत्मनिर्भर भारत और नेशनल सिंगल विंडो (एनएसडब्ल्यू) के निर्माण खंड और
- एच) शहरी प्रबंधन और शासन पर स्ट्रीम के कुछ हिस्से सितंबर-अक्टूबर 2022 के दौरान वितरित किए गए थे।

तीसरा उप-मॉड्यूल क.III: शाखा (स्ट्रीम) को कवर करने वाले नीति परिदृश्य की खोज (ए) बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संरक्षण: कानून और नीतियाँ, (बी) डेटा एनालिटिक्स और सार्वजनिक नीति के लिए बड़ा डेटा, (सी) विविधता, समानता, समावेशन और अपनापन (डीईआईबी), (डी) भारत की विदेश नीति और वर्तमान भू-राजनीति के निर्धारक (ई) श्रम सुधार और कौशल विकास पहल, भारत डायस्पोरा की गतिशीलता, (एफ) भूमि एवं जल संसाधन प्रबंधन (जी) साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और (एच) शहरी प्रबंधन और शासन पर स्ट्रीम के शेष भाग नवंबर-दिसंबर 2022 के दौरान वितरित किए गए थे।

चौथा उप-मॉड्यूल क.IV: समसामयिक चुनौतियाँ, वित्त और प्रबंधन में शामिल हैं

ए) वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय बाजार,

बी) अंतरसरकारी संबंध,

सी) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य,

डी) मानव संसाधन विकास में प्रगति,

ई) सार्वजनिक सेवा वितरण,

एफ) इंडिया @100- डिजिटल परिवर्तन के लिए नीतियाँ और

जी) सार्वजनिक नीति के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और एआई डेटा साइंस जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान वितरित किया गया था।

पाँचवां उप-मॉड्यूल क.V: सिविल सेवाओं और संस्थागत नवाचार (सीबीसी, एनआरए, लेटरल एंट्री) में अगली पीढ़ी के सुधारों को शामिल करने वाली सिविल सेवा के लिए योग्यता रूपरेखा, मिशन कर्मयोगी-लोकाचार, नैतिकता, समानता और मार्च 2023 के दौरान दक्षता वितरित की गई थी।

ख. अनुभव के माध्यम से सीखना : कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने एक-दूसरे के समृद्ध और विविध पेशेवर अनुभवों के साथ-साथ विभिन्न स्थानों की यात्राओं के माध्यम से सीखा। विभिन्न राज्यों में शासन नवाचारों की जानकारी प्रदान करने के लिए कक्षा में सीखने को ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों और आगे के क्षेत्रों में क्षेत्रीय दौरो द्वारा पूरक बनाया गया। एपीपीपीए के इतिहास में पहली बार, पाठ्यक्रम प्रतिभागियों ने समुद्र में आईएनएस जलाशय पर एक दिन बिताया। उन्होंने विशाखापट्टनम में एक पनडुब्बी, आईएनएस सिंधशास्त्र, नौसेना वास्तुकार अधिकारियों के लिए आईएनएस विश्वकर्मा-प्रशिक्षण स्कूल और भारतीय नौसेना के हल आर्टिफिसर को देखा।

इन दौरो का उद्देश्य उद्योग और चयनित ग्रामीण और शहरी केंद्रों/सुविधाओं में निर्देशित अध्ययन दौरो के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और वितरण से संबंधित जमीनी हकीकतों से अवगत कराना था। 48वें एपीपीपीए के दौरान इनका विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है :

ख.1 अनुभवात्मक प्रस्तुतियाँ: एक सार्थक और मजेदार अभ्यास, अनुभवात्मक प्रस्तुतियाँ प्रतिभागियों के बीच अनुभवों और विशेषज्ञता के पारस्परिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए थीं। प्रत्येक प्रतिभागी ने एक प्रस्तुति तैयार की जो उस विशिष्ट स्थिति पर केंद्रित थी जिसका एक अधिकारी ने अपने कैरियर में किसी समय सामना किया था। इन प्रस्तुतियों का उद्देश्य आंतरिक प्रशासन अथवा क्षेत्र स्थितियों में नवाचारों, संगठनात्मक नेतृत्व में सर्वोत्तम व्यवहारों अथवा परियोजना योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सबक को उजागर करना था।

ख.2 ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन: ग्रामीण विकास और प्रशासन एवं राष्ट्रीय प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन करना। इस घटक का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण जीवन की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विषय-आधारित अध्ययन सौंपा गया था और उनसे वितरण तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने की अपेक्षा की गई थी। प्रतिभागियों के समूहों ने ब्लॉक-भीमुनिपट्टनम, जिला-विशाखापट्टनम (एपी) के अंतर्गत ग्राम पंचायत-डाकामरी के चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और ग्राम स्तर के पदाधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत की। समूहों ने इन दौरों की अपनी क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्ट साझा की जो भविष्य की नीति संदर्भ के लिए उपयोगी हैं।

ख.3 शहरी क्षेत्र अध्ययन: शहरी विकास और प्रशासन का अध्ययन करना। यह प्रतिभागियों को शहरी प्रशासन और प्रबंधन की समस्याओं और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रतिभागियों ने विभिन्न शहरी विकास योजनाओं और लोगों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर उनके प्रभाव

का अध्ययन किया। अध्ययन में नगर पालिकाओं और अन्य विकास एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत शामिल थी। शहरी अध्ययन रिपोर्ट समूहों द्वारा साझा की गई। ये रिपोर्टें अच्छे नीतिगत इनपुट के रूप में काम करती हैं। इस वर्ष निम्नलिखित तीन जिलों का चयन किया गया: 1. चंडीगढ़ 2. देहरादून और 3. ऋषिकेश।

ख 4. प्रायोगिक शिक्षण में फॉरवर्ड एरिया का दौरा शामिल है (ए) श्रीनगर, (बी) सिक्किम और दार्जिलिंग तथा (सी) लेह और लद्दाख। प्रतिभागियों को भारतीय सेना के अग्रिम क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, स्थानीय सरकारी प्रतिष्ठानों और सीमावर्ती राज्यों और जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अन्य संस्थानों के दौरों के माध्यम से जमीनी हकीकत से भी अवगत कराया गया।

शोध प्रबंधन

यह एपीपीपीए कार्यक्रम का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। एक विशेषज्ञ संकाय के मार्गदर्शन में शोध प्रबंधन लिखते समय, प्रतिभागियों ने उनके द्वारा चुनी गई एक विशिष्ट समस्या का उसके सभी प्रभावों सहित गहन विश्लेषण किया। इन शोध प्रबंधनों के माध्यम से, उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही इस प्रक्रिया में अपने विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन भी किया। शोध प्रबंधन लेखन के बाद प्रत्येक प्रतिभागी की मौखिक परीक्षा ली गई। महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. और पाठ्यक्रम निदेशक, अतिरिक्त पाठ्यक्रम निदेशक, विषय विशेषज्ञों ने संबंधित संकाय गाइड के साथ मौखिक परीक्षा का संचालन किया।

दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह 28 अप्रैल 2023 को भा.लो.प्र.सं. के टीएनसी मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था। इस अवसर के दौरान, श्रीमती एस राधा चौहान, सचिव, डीओपीटी, भारत सरकार और श्रीमती रश्मि चौधरी, अपर सचिव, डीओपीटी, भारत सरकार ने 48वें

एपीपीपीए के प्रतिभागियों को लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा प्रदान किया। इस अवसर पर एम.फिल. 47वें एपीपीपीए के प्रतिभागियों को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के माध्यम से डिग्री भी प्रदान की गई। 47वें एपीपीपीए के कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर सुरेश मिश्रा और कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन भी मंच पर उपस्थित थे। इसके अलावा, हॉल में भा.लो.प्र.सं. के संकाय सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर, श्रीमती एस राधा चौहान ने संक्षिप्त दीक्षांत भाषण दिया और एपीपीपीए पर प्रतिभागियों के विचार आमंत्रित किए। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और इसके संचालन पर संतुष्टि दिखाई। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया। अपर सचिव श्रीमती रश्मी चौधरी ने अपने विचार प्रस्तुत किये। प्रोफेसर वीएन आलोक ने 48वें एपीपीपीए की रिपोर्ट प्रस्तुत की और डॉ. कुसुम लता ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

दीर्घकालिक एपीपीपीए कार्यक्रम के अलावा, संस्थान ने वर्ष 2022-23 के दौरान 101 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

ब्रेकअप इस प्रकार है :

पाठ्यक्रम	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित	70	8081
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (एपीपीपीए सहित)	2	238
राज्य सरकार	32	1642
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	5	103
शहरी विकास मंत्रालय	7	35
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईटीईसी)	6	176
पीएसयू (एएलपी)	1	11
अन्य	4	660
कुल	127	11313

इस प्रकार, आयोजित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या एपीपीपीए सहित 127 थी। वर्ष के दौरान एपीपीपीए के 38 प्रतिभागियों सहित कुल 11313 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण एफ. 2 पर दिया गया है।

सूचना प्रबंधन

संस्थान अपने नियमित प्रकाशनों जैसे मासिक डिजिटल संस्करण आईआईपीए न्यूजलेटर, त्रैमासिक संस्करण इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईजेपीए) के माध्यम से मेसर्स सेज के सहयोग से लोक प्रशासन, शासन, नीति और विकास से संबंधित जानकारी, विश्लेषण, दृष्टिकोण और ज्ञान का प्रसार करता है। प्रकाशन, नगरलोक के त्रैमासिक संस्करण, लोक प्रशासन में दस्तावेज (डीपीए) के त्रैमासिक संस्करण, लोक प्रकाशन (हिंदी जर्नल) के द्विवार्षिक संस्करण और आईआईपीए डाइजैस्ट के त्रैमासिक संस्करण।

आईजेपीए को छोड़कर जर्नलों के डिजिटल संस्करणों की ओपेन पहुँच भा.लो.प्र.सं. वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। आईजेपीए के सभी डिजिटल करंट और बैक अंक सेज/आईजेपीए वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नगरलोक और लोक प्रशासन को नए यूजीसी-केयर ग्रुप (I) के तहत मान्यता प्राप्त है।

प्रकाशन

वर्ष 2022-2023 के दौरान निम्नलिखित 29 प्रकाशन प्रकाशित हुए :

1. आईजेपीए (जर्नल) के 04 संस्करण
2. डीपीए (जर्नल) के 04 संस्करण
3. नगरलोक (जर्नल) के 04 संस्करण
4. लोक प्रकाशन (जर्नल) के 02 संस्करण
5. आईआईपीए डाइजैस्ट (पत्रिका) के 04 संस्करण
6. भारत रत्न : सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और साकेत बिहारी द्वारा राजेंद्र प्रसाद की प्रेरक रचनाएँ (पुस्तक)

7. आईआईपीए कॉफी टेबल बुक (पुस्तक)
8. रिसर्जेंट एंड वाइब्रेंट इंडिया @75 री-एनर्जेटिंग कोऑपरेटिव गवर्नेंस जुलाई 2022 पर डॉ. सपना चड्ढा द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार पर रिपोर्ट (रिपोर्ट)
9. डॉ. अमित कुमार सिंह द्वारा विदेशी प्रशिक्षण की घरेलू फंडिंग योजना के मूल्यांकन की रिपोर्ट (रिपोर्ट)
10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, प्रो. के.के. पांडे द्वारा (रिपोर्ट)
11. प्रोफेसर चारु मल्होत्रा द्वारा एसएपी प्रभाव आकलन रिपोर्ट (रिपोर्ट)
12. वी. श्रीनिवास, आईएएस द्वारा शासन में सुधार, (पुस्तिका)
13. वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 (अंग्रेजी)
14. वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022 (हिन्दी)
15. थीम पेपर (पुस्तिका)
16. सदस्य सम्मेलन की कार्यवाही (पुस्तिका)

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार

आईआईपीए अपनी गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आयोजनों और प्रकाशनों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की विशाल क्षमता का लाभ उठाता है। विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर हमारी गतिशील और आकर्षक उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि हमारे हितधारक हमारे नवीनतम प्रयासों से अच्छी तरह से अवगत रहें और जुड़े रहें। हमारे अतीत और आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यापक दृष्टिकोण के लिए, हम नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट (iipa.org.in) पर जानकारी अपडेट करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे ट्विटर हैंडल (@iipa9) को 2028 उपयोगकर्ता फॉलो करते हैं, जबकि हमारे लिंकडइन पेज (@IIPAOOfficial) को 909 फॉलोअर्स मिले हैं। इन प्लेटफॉर्मों को संस्थान के नवीनतम अपडेट और उपलब्धियों के साथ दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है, जिससे हमें विविध दर्शकों तक पहुंचने और

सार्थक बातचीत को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, 2036 ग्राहकों के साथ एक संपन्न यूट्यूब चैनल (@iipaofficial) के साथ, भा.लो.प्र.सं. ने एक विषयों को शामिल करते हुए लगभग 600 वीडियो अपलोड किए हैं। इन वीडियो में भा.लो.प्र.सं. संकाय और कर्मचारियों द्वारा भारत सरकार के सचिवों, नीति निर्माताओं और यूपीएससी टॉपर्स जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ आयोजित व्यावहारिक साक्षात्कार शामिल हैं। इसके अलावा, हमारे चैनल में हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम व्याख्यान, उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम व्याख्यान/एमसीक्यू और सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी योजना के तहत योग्यता-आधारित प्रशिक्षण पर वीडियो की एक समर्पित श्रृंखला शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपनी सक्रिय उपस्थिति के माध्यम से, हमारा लक्ष्य मूल्यवान ज्ञान का प्रसार करना, संवाद को बढ़ावा देना और सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एक जीवंत समुदाय बनाना है।

पुस्तकालय

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं।

संग्रह विकास:

वर्ष 2021-22 के दौरान, पुस्तकालय में 540 पुस्तकें और पत्रिकाओं के 204 जिल्द संस्करण जोड़े गए। इनमें से 300 पुस्तकें खरीदी गईं, 240 निःशुल्क प्राप्त हुईं। सार्वजनिक दस्तावेज अनुभाग में लगभग 82 दस्तावेज जोड़े गए। 31 मार्च, 2022 तक पुस्तकालय में 2.29 लाख पुस्तकें और जिल्द वाली पत्रिकाएँ थीं। वर्ष के दौरान पुस्तकालय को 17 समाचार पत्रों सहित 237 पत्रिकाएँ प्राप्त हुईं।

ऑनलाइन सेवाएं

• ऑनलाइन डेटाबेस सब्सक्राइब्ड

हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, इकोनॉमिस्ट, टाइम, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली इत्यादि सहित 21 से अधिक जर्नल्स की ऑनलाइन पहुंच की सुविधा प्रदान की जा

रही है, जिन तक भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय वेबसाइट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, पुस्तकालय ने एबीआई/इनफॉर्म की सदस्यता जारी रखी, जिससे लगभग 4000 पत्रिकाओं तक पहुंच की सुविधा मिल गई, जिनमें से 3000 पत्रिकाएं पूर्ण पाठ में हैं, इसके अलावा डेटाबेस लगभग 25,000 शोध प्रबंधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। पुस्तकालय ने 'जेएसटीओआर' की भी सदस्यता ली है, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है जो विद्वान समुदाय को एक विश्वसनीय डिजिटल संग्रह में बौद्धिक सामग्री की एक शृंखला की खोज, उपयोग और निर्माण में मदद करने के लिए समर्पित है। यह लगभग 2,600 अकादमिक पत्रिकाओं की पूर्ण-पाठ खोज प्रदान करता है।

• इन-हाउस लाइब्रेरी ऑनलाइन डेटाबेस

कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय डेटाबेस में पुस्तकों और रिपोर्टों से संबंधित 1.36 लाख रिकॉर्ड हैं

1.28 आवधिक लेखों से संबंधित अभिलेख।

पुस्तकालय इन सभी तक दूरस्थ पहुँच प्रदान करती है दुनिया भर में संसाधन 24x7.

डिजिटल ज्ञान भंडार

पुस्तकालय ने संस्थान के अनुसंधान आउटपुट और प्रकाशित संसाधनों को प्रदर्शित करने वाली डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी (डीकेआर) बनाई है। डीकेआर संस्थान की बौद्धिक पूंजी, अनुसंधान आउटपुट और प्रकाशित संसाधनों को सुलभ बनाने में मौलिक भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य संस्थान की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधि से उत्पन्न बौद्धिक कार्यों को संग्रहीत और संरक्षित करना है, ताकि इसे खुली पहुंच के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। संसाधनों को विभिन्न प्रकार जैसे- वार्षिक सामान्य निकाय बैठक-राष्ट्रपति के संबोधन, संकाय प्रकाशन, दुर्लभ पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट, विषयगत पत्र, वर्किंग पेपर और इसी तरह के लिए बनाए गए समुदायों के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें एपीपीपीए प्रतिभागियों द्वारा उनके एम.फिल डिग्री के लिए प्रस्तुत किए गए थीसिस और शोध प्रबंधन भी शामिल हैं। रिपोजिटरी में अब तक

4494 दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं, जिनमें वर्ष 2008-09 से वर्ष 2022-23 तक पूर्ण पाठ शीर्ष दस एपीपीपीए शोध प्रबंधन सहित शामिल हैं।

पुस्तकालय सेवाएँ

31 मार्च, 2023 तक, 1350 दस्तावेज उधार दिए गए थे और 1310 दस्तावेज पुस्तकालय को वापस प्राप्त हुए थे। संस्थान के संकाय सदस्यों, भा.लो.प्र.सं. सदस्यों, लोक प्रशासन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीपीए) सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के अलावा, लगभग 7027 वास्तविक शोधकर्ताओं ने शुल्क-आधारित परामर्श कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया। पुस्तकालय ने सदस्यों को फोटोकॉपी और इंटरनेट सुविधा प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान इसने 12925 पृष्ठों से अधिक फोटोकॉपी उपलब्ध कराई और उपयोगकर्ताओं को ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं प्रदान कीं।

मूल्य संवर्धित सेवाएं

पुस्तकालय वर्तमान जागरूकता, अनुक्रमणिका और सार-संक्षेप सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। पुस्तकालय नियमित रूप से अपने पाठकों को आने वाले दस्तावेजों और नवीनतम सूचनाओं से अवगत कराने के लिए बुक अलर्ट: अतिरिक्त चीजों की एक मासिक सूची, आर्टिकल अलर्ट: महत्वपूर्ण लेखों की एक सूची, साप्ताहिक समाचार अलर्ट और वर्तमान सामग्री प्रकाशित करती है। पुस्तकालय द्वारा 'लोक प्रशासन में दस्तावेजीकरण, (डीआईपीए)' शीर्षक से एक त्रैमासिक अनुक्रमण और सार जर्नल निकाला जा रहा है। इसमें आवधिक लेखों, सार, पुस्तक समीक्षाओं और पुस्तक नोट्स का अनुक्रमण शामिल है। वर्ष के दौरान डीआईपीए में 2075 आवधिक लेख, 155 पुस्तक समीक्षाएं और 90 पुस्तक नोट्स शामिल किए गए। वर्ष 2022 के लिए डीआईपीए के सभी चार अंक समय पर सामने आए गए। इसके अलावा पुस्तकालय अपने सदस्यों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को मांग पर ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क में भागीदारी

पुस्तकालय डेलनेट-डेललपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का एक सक्रिय सदस्य है और अंतर-पुस्तकालय ऋण, ग्रंथ सूची के संकलन और साहित्य खोज के लिए नेटवर्क की सुविधाओं का काफी उपयोग कर रहा है। इस नेटवर्किंग प्रयास के हिस्से के रूप में, भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय अपने समृद्ध संसाधनों का उपयोग अन्य भागीदार नेटवर्क सदस्यों को भी दे रही है। वर्ष के दौरान, भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए अंतर पुस्तकालय ऋण पर 76 दस्तावेज उधार लिए गए थे और अन्य पुस्तकालयों द्वारा डेलनेट सुविधा के माध्यम से 81 दस्तावेज उधार लिए गए थे। हमारी पारस्परिक कुशल सेवाओं के हिस्से के रूप में, भा.लो.प्र.सं. लाइब्रेरी को सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय के रूप में चुना गया है और वर्ष 2016 के लिए 7000 पुस्तकालयों में से डेलनेट द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है।

भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय आधारिक संरचना का आधुनिकीकरण और उन्नयन:

- (i) पुस्तकालय सदस्यों के उपयोग के लिए पुस्तकालय परिसर में वाई-फाई सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी।
- (ii) संसाधन खोज के लिए भू-तल पर लाइब्रेरी के संदर्भ और संचलन क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के लिए दो नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

सहयोगी गतिविधियाँ

आम निकाय की अड़सठवीं वार्षिक बैठक

संस्थान की आम निकाय की 68वीं वार्षिक बैठक 31 अक्टूबर, 2022 को शाम 4.00 बजे भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में फिजिकल और वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। एजीएम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ की गरिमामय उपस्थिति रही, जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की और सम्मानित अतिथि के रूप में डॉ. जितेंद्र सिंह, माननीय केंद्रीय

मंत्री और अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद थे। यह पदभार ग्रहण करने के बाद माननीय उपराष्ट्रपति की भा.लो.प्र.सं. की पहली यात्रा भी है।

वर्ष भर में भा.लो.प्र.सं. की उपलब्धियों पर विचार करते हुए, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और आईआईपीए के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि 'मिशन कर्मयोगी एक परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाता है जो सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का दोहन करने की अनुमति देता है। भा.लो.प्र.सं. को अपनी विशाल क्षमता के साथ उस बदलाव को प्रेरित करना होगा।

अपने संबोधन के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने माननीय उपराष्ट्रपति को अवगत कराया कि भा.लो.प्र.सं. न केवल 'चयनित सिविल सेवकों' को बल्कि 'निर्वाचित जन प्रतिनिधियों' को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। मंत्री ने बताया कि भा.लो.प्र.सं. क्षमता निर्माण के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है, और महामारी के दौरान, यह 100 से अधिक ऑनलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम था और तेजी से खुद को डिजिटल प्रशिक्षण के पावरहाउस में बदल दिया, डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ डिजिटल सामग्री भी तैयार की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे भा.लो.प्र.सं. इस मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है और आईजीओटी, कार्यशालाओं और सम्मेलनों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के रूप में पूरे दिल से समर्थन दे रहा है। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईएस (सेवानिवृत्त) ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम के दौरान कई पुरस्कार वितरित किए गए और भा.लो.प्र.सं. प्रकाशन भी जारी किए गए। कार्यक्रम का संचालन कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने किया।

बैठक में न्यूनतम 50 सदस्यों के कोरम के मुकाबले संस्थान के 141 सदस्यों ने भाग लिया। सदन ने 1 नवंबर, 2021 को आयोजित आम निकाय की अड़सठवीं वार्षिक बैठक की कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्ट और वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों को मंजूरी दे दी।

छियासठवें सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन

संस्थान के छियासठवें सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन 1 नवंबर, 2022 को प्रातः 10.00 बजे भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में फिजिकल और वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था

सम्मेलन का विषय था 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है'। डॉ. रोमा देबनाथ ने थीम पेपर प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने अवधारणा पर प्रकाश डाला। अपने स्वागत भाषण में भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने विषय के महत्व पर प्रकाश डाला। क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। चर्चा के अलावा, सम्मेलन के दौरान विषय पर कागजात प्रस्तुत किए गए। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया और धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

वार्षिक सम्मेलन के आयोजन से पहले, भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं द्वारा अपने

संबंधित मुख्यालयों में थीम पर प्रस्तावना सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किए गए थे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं में आयोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों की सिफारिशों और टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत की गईं।

कार्यकारी परिषद

कार्यकारी परिषद की बैठकें

वर्ष के दौरान, कार्यकारी परिषद की दो बैठकें 5 जुलाई, 2022 और 12 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गईं।

सदस्यता

वर्ष के दौरान, 275 आजीवन सदस्यों, चार एसोसिएट सदस्यों और 36 विद्यार्थी सदस्यों को प्रवेश दिया गया। वर्ष के दौरान 24 आजीवन सदस्यों की मृत्यु हो गई है।

सदस्यता का श्रेणी-वार विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है :

	वार्षिक सदस्य	आजीवन सदस्य	सहयोगी सदस्य	विद्यार्थी सदस्य	कॉर्पोरेट सदस्य	कुल
31.3.2022 तक सदस्यता	15	10908	129	34	63	11149
2022-23 के दौरान स्वीकृत सदस्य	--	275	04	36	01	316
2022-23 के दौरान सदस्यों की मृत्यु हो गई	--	(-) 24	--	--		(-)24
31.3.2023 तक कुल सदस्यता	15	11159	133	70	64	11441

भा.लो.प्र.सं. के प्रतिष्ठित सदस्यों को पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

निम्नलिखित सदस्यों को भा.लो.प्र.सं. और सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए एजीएम में पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया:

1. श्री वी. बालासुब्रमण्यम, आईएएस (सेवानिवृत्त) (1.10.1994 से एल-7347)
2. डॉ. अरुण कुमार रथ, आईएएस (सेवानिवृत्त) (एल-6886 1.4.1993 से)
3. प्रो. डी. रवीन्द्र प्रसाद (एल-2472 1.1.1970 से)

वर्ष 2022 के लिए अकादमिक उत्कृष्टता के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार

भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भा.लो.प्र.सं. की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी स्मृति में, भा.लो.प्र.सं. ने अकादमिक उत्कृष्टता के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार की स्थापना की है, जैसा कि 5 जुलाई, 2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

यह पुरस्कार भा.लो.प्र.सं. के एक सदस्य को लोक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में उसकी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है जिसे भा.लो.प्र.सं. की ए.जी.एम में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस वर्ष का उद्घाटन पुरस्कार प्रो. रमेश कुमार अरोड़ा, (दिनांक 1.1.1966 से एल-1229), राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान अध्यक्ष, राजस्थान क्षेत्रीय शाखा को लोक प्रशासन और अकादमिक जगत में उत्कृष्टता के क्षेत्र में उनके विशाल योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया।

वर्ष 2021-22 के लिए इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईजेपीए) में सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए श्री टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार

श्री टी.एन. वर्ष 2021-22 के लिए आईजेपीए में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए चतुर्वेदी पुरस्कार बांग्लादेश के को चटगांव विश्वविद्यालय के डॉ. शमीम नूर और डॉ. सहारिन प्रिया शॉन को उनके लेख 'बांग्लादेश में ऑनलाइन शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी' कोविड 19 स्कूल बंद के दौरान समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियाँ और अवसर' के लिए सम्मानित किया गया।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी स्मृति प्रमाणपत्र

वर्ष 2021-22 में भा.लो.प्र.सं. संकाय द्वारा अधिकतम संख्या में शोध अध्ययन पूरा करने के लिए डॉ. सुरभि पांडे को श्री टी.एन. चतुर्वेदी मेमोरियल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया गया। इसमें एक प्रमाणपत्र और 5000/-रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

डॉ यू.सी. अग्रवाल स्मृति प्रमाणपत्र

वर्ष 2021-22 में भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी द्वारा लिखे गए सबसे अधिक लेखों के लिए डॉ. यू.सी. अग्रवाल मेमोरियल सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन डॉ. नीतू जैन और डॉ. श्यामली सिंह को प्रदान किया गया। इसमें प्रत्येक को एक प्रमाणपत्र और 5000/-रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

आईआईपीए शाखाओं को पुरस्कार

जैसा कि राष्ट्रपति की इच्छा थी, भा.लो.प्र.सं. 25

क्षेत्रीय और 42 स्थानीय शाखाओं के साथ एक बेहतर नेटवर्क बनाएगा और उन्हें प्रेरित करेगा, कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा को प्रमाण पत्र और 10,000/- रुपये के नकद पुरस्कार के साथ प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ दूसरा पुरस्कार दिया गया और जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रीय शाखा को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ तीसरा पुरस्कार दिया गया।

क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएँ और सदस्यों की गतिविधियाँ

31 मार्च, 2023 तक, संस्थान की क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 25 और 42 है। पुडुचेरी स्थानीय शाखा को क्षेत्रीय शाखा में उन्नत किया गया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं और उनके पदाधिकारियों के नाम, उनके द्वारा संचालित गतिविधियाँ और उनसे जुड़े सदस्यों की संख्या अनुलग्नक एफ-3 में दर्शाई गई है।

शाखाओं की कई गतिविधियाँ मासिक भा.लो.प्र.सं. न्यूजलेटर्स में भी रिपोर्ट की गई हैं।

भा.लो.प्र.सं. में 31 अक्टूबर, 2022 को भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड के माध्यम से क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं के अध्यक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों को मजबूत करने और शाखाओं के विकास से संबंधित बड़ी संख्या में मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएँ: बिहार, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश (क्षेत्रीय शाखाएँ) और औरंगाबाद, बरेली, बर्दवान, कुड्डालोर, धारवाड़ हावड़ा, करीमनगर, मदुरै, नागपुर, तिरुपतूर, तंजावुर और विल्लुपुरम (स्थानीय शाखाएँ) थीं।

बैठक में संस्थान की क्षेत्रीय शाखाओं से जुड़े संकाय सदस्यों ने भी भाग लिया। क्षेत्रीय शाखाओं से जुड़े संकाय सदस्यों की सूची अनुलग्नक एफ-7 में दी गई है।

वर्ष के दौरान शाखाओं को उनके कार्यक्रमों और गतिविधियों को चलाने के लिए सदस्यता पूंजी

निधि पर अर्जित ब्याज के पचास प्रतिशत हिस्से सहित वित्तीय सहायता के रूप में 10,69,601/-रुपये का भुगतान किया गया। संस्थान शाखा के अधीन शैक्षणिक गतिविधियाँ, प्रस्तावना सम्मेलन आदि के संचालन में मदद के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय शाखा को 35,000/-रुपये और स्थानीय शाखा को 20,000/-रुपये की प्रतीकात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करता है (ए) नियमित चुनाव आयोजित करना (बी) नियमित रूप से अपने खातों का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करना और (सी) इसकी गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसके अलावा, शाखाओं को सदस्यता कॉर्पस फंड के ब्याज का पचास प्रतिशत हिस्सा और वार्षिक सदस्यता सब्सक्रिप्शन का पचास प्रतिशत हिस्सा भी दिया जाता है। शाखाओं को अपने विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग और साझेदारी के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय करने और आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण दर्शाने वाला एक विवरण अनुलग्नक एफ-6 में दिया गया है।

वार्षिक आम सभा की बैठक और सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन जिसके लिए थीम पेपर सभी शाखाओं को भेजा जाता है, साथ ही भा.लो.प्र.सं. न्यूजलेटर का प्रकाशन भी सदस्य-उन्मुख गतिविधियाँ हैं।

भा.लो.प्र.सं. की आउटरीच और सहयोग गतिविधियाँ

वर्ष 2022-23 में, भा.लो.प्र.सं. ने विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भा.लो.प्र.सं. ने बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (BIPARD) के सहयोग से बिहार के राज्य सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यशदा, पुणे और वनमती, नागपुर के सहयोग से महाराष्ट्र के राज्य सिविल सेवकों के लिए पहले के कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेंगे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की एमडीपी भी जारी रही। भा.लो.प्र.सं. के उपभोक्ता अध्ययन केंद्र ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे विद्यार्थियों, गृहिणियों, नागरिक समाज संगठनों इत्यादि के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पंजाब विश्वविद्यालय के साथ, भा.लो.प्र.सं. ने अपने एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) के लिए अकादमिक सहयोग किया है और दोनों संस्थान अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग के अवसर भी तलाश रहे हैं। भा.लो.प्र.सं. और क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) आईजीओटी प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास और विभिन्न सीटीआई की क्षमता निर्माण के लिए सक्रिय रूप से मिलकर काम कर रहे हैं।

अप्रैल 2022 से 2023 तक निम्नलिखित संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मंत्रालयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन की सूची

क्रमांक	एमओयू का नाम
1.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल-2630001 उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन
2.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन
3.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और गणपति विश्वविद्यालय (GUNI) के बीच समझौता ज्ञापन
4.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के बीच समझौता ज्ञापन
5.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के बीच समझौता ज्ञापन
6.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी-स्कूल ऑफ लॉ (कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037) के बीच समझौता ज्ञापन
7.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और क्षमता निर्माण आयोग नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

भा.लो.प्र.सं. द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

वर्ष 2017-18 से, भा.लो.प्र.सं. ने राज्य सरकारों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है और राज्य सिविल सेवाओं के परिवीक्षार्थियों मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहा

है। भा.लो.प्र.सं. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (VANAMATI) और महाराष्ट्र सरकार के यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (YASHADA), श्रीनगर नगर प्रशासन (J&K) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के लिए आयोजित प्रशिक्षण की सूची इस प्रकार है :

क्रमांक	प्रोग्राम	अवधि
1.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी प्रशासन पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम	11-13 मई, 2022
2.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी प्रशासन पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम	25-27 मई, 2022
3.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	13 जून, 2022
4.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	14 जून, 2022
5.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	15 जून, 2022
6.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	17 जून, 2022
7.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	22-26 अगस्त, 2022
8.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	29 अगस्त- 2 सितंबर, 2022
9.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	5-9 सितंबर, 2022
10.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	12-16 सितंबर, 2022
11.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	19-23 सितंबर, 2022
12.	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों (महाराष्ट्र सरकार, वनमती) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-30 सितंबर, 2022

13.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	17-21 अक्टूबर, 2022
14.	श्रीनगर नगर निगम के लिए शहरी शासन पर ईआर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम	19-21 अक्टूबर, 2022
15.	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों (महाराष्ट्र सरकार, वनमती) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	7-11 नवंबर, 2022
16.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	14-18 नवंबर, 2022
17.	यशदा, महाराष्ट्र के परिवीक्षाधीन (समूह ए) अधिकारियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम	28 नवंबर-3 दिसंबर 2022
18.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	28 नवंबर - 02 दिसंबर, 2022
19.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	19-23 दिसंबर, 2022
20.	यशदा, महाराष्ट्र के परिवीक्षाधीन (समूह ए) अधिकारियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम	19-23 दिसंबर, 2022
21.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	3-7 जनवरी, 2023
22.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	9-13 जनवरी, 2023
23.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	16-20 जनवरी, 2023
24.	महाराष्ट्र सरकार के परिवीक्षार्थियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम (वनमती द्वारा प्रायोजित)	31 जनवरी, 4 फरवरी, 2023
25.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	30 जनवरी-3 फरवरी, 2023
26.	महाराष्ट्र सरकार के परिवीक्षार्थियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम (वनमती द्वारा प्रायोजित)	7-11 फरवरी, 2023
27.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	6-10 फरवरी, 2023
28.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	13-17 फरवरी, 2023

29.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	20-24 फरवरी, 2023
30.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	27 फरवरी-03 मार्च, 2023
31.	‘लोक प्रशासन और प्रशासन सह एक्सपोजर विजिट’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (BIPARD द्वारा प्रायोजित)	20-24 मार्च, 2023
32.	‘लोक प्रशासन और प्रशासन सह एक्सपोजर विजिट’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (BIPARD द्वारा प्रायोजित)	27-31 मार्च, 2023

संकाय विकास कार्यक्रम

भा.लो.प्र.सं. संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए, केस स्टडी शिक्षण, नई प्रौद्योगिकियों आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए वर्ष 2022-23 में कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1.	प्रोफेसर चारु मल्होत्रा और डॉ. रोमा देबनाथ द्वारा डिजिटल अकादमी की तैयारी पर ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यशाला	24 मई, 2022
2.	प्रोफेसर श्वेता मित्तल (बाहरी विशेषज्ञ) द्वारा ‘शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस विधि’ पर कार्यशाला	05 दिसंबर, 2022

इसके अलावा, भा.लो.प्र.सं. संकाय ने देश के विभिन्न स्थानों पर सुशासन, ई-गवर्नेंस आदि क्षेत्रों में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं/सेमिनारों में भी भाग लिया।

निबंध प्रतियोगिता

वर्ष 2022-23 के लिए निबंध प्रतियोगिता के विषय थे:

1. ‘महामारी के बाद की अवधि में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन’
2. ‘चौथी औद्योगिक क्रांति और शासन’
3. ‘नेतृत्व और समाज में महिलाओं की विकसित भूमिका’

वार्षिक निबंध प्रतियोगिता-2022 के विजेता निम्नलिखित हैं :

1. 10,000 रुपये के प्रथम पुरस्कार के लिए कोई प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई गई।

2. श्रीमती रमन शर्मा को ‘नेतृत्व और समाज में महिलाओं की विकसित भूमिका’ (हिंदी) पर 7,000 रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया।
3. सुश्री इहा रश्मि वर्मा को ‘नेतृत्व और समाज में महिलाओं की विकसित भूमिका’ (अंग्रेजी) पर 5000 रुपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया।

सभी निबंध विजेताओं (अंग्रेजी और हिंदी) को 31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में पुरस्कार दिए गए।

केस अध्ययन प्रोग्राम

संस्थान उच्च गुणवत्ता की केस स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक केस स्टडी पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसका उपयोग शिक्षण/प्रशिक्षण के माध्यम से अथवा स्वयं सीखने के लिए किया जा सकता है। वर्ष 2022-23 के लिए, केवल एक केस अध्ययन प्राप्त हुआ था और भा.लो.प्र.सं. के पूर्व निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों के आधार पर विशेषज्ञ

पैनल द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया था। केस स्टडी अंग्रेजी में थी और 31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में उसे पुरस्कार प्रदान किया गया।

मूल्यांकन के आधार पर 'डिजिटल इंडिया-प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमडीआईएसए) का एक मामला' पर डॉ. शिव प्रकाश कटिया से प्राप्त केस स्टडी को 6,000/- रुपये के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ढांचागत सुधार

भा.लो.प्र.सं. एक प्रमुख संस्थान है जिसके परिसर में अपना स्वयं का छात्रवास परिसर है जो एपीपीपीए, इसके बाहरी सदस्यों, मेहमानों, बोनाफाइड अनुसंधान विद्वानों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी विभागों के अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को बोर्डिंग और आवास प्रदान करता है।

छात्रवास में 89 कमरे और आठ एपीपीपीए फैमिली सुइट हैं। छात्रावास के सभी कमरों में ए.सी., संबद्ध शौचालय, गीजर, इंटरकॉम और केबल टी.वी हैं।

संस्थान का वित्त

जैसा कि प्राप्ति और भुगतान खाते (अनुसूची-ए) में दिखाया गया है, वर्ष 2022-23 के दौरान संस्थान की आय रु. 4525.43 लाख के व्यय के मुकाबले रु. 4526.02 लाख थी। रु. 4526.02 लाख कुल आय में से, संस्थान को सरकार से रु. 3200.93 लाख का सहायता अनुदान वेतन/सामान्य/पूँजी प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार, पिछले वर्ष से लाए गए 7.82 लाख रुपये के संचयी घाटे को समायोजित करने के बाद, वर्ष के अंत में अनुसूची ए के अनुसार संचयी कमी 7.24 लाख रुपये है।

वर्ष के दौरान आंतरिक संसाधनों से कुल आय 13.25 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष यह 9.57 करोड़ रुपये थी।

13.25 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में मुख्य रूप से प्रशिक्षण शुल्क (9.44 करोड़ रुपये), अनुसंधान कार्यों

से शुद्ध आय (1.59 करोड़ रुपये), उपयोगकर्ता शुल्क (1.43 करोड़ रुपये), प्रकाशनों की बिक्री (8.72 लाख रुपये) आदि शामिल हैं।

45.25 करोड़ रुपये के कुल भुगतान में से, संस्थान का वेतन और भत्ता 12.51 करोड़ रुपये और पेंशन 8.31 करोड़ रुपये थी। व्यय की अन्य प्रमुख वस्तुएं कैपेक्स रखरखाव (रु.3.76), प्रशासनिक और विविध व्यय (रु.1.00 करोड़), प्रशिक्षण कार्यक्रम (रु.6.83 करोड़) थीं।

संस्थान को पूंजीगत प्रकृति की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सरकार से 12.01 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता (पूँजी) भी प्राप्त हुई, जिसके प्रति कुल 12.01 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। व्यय की मुख्य वस्तुएँ बुनियादी ढाँचा विकास कार्य/नवनीकरण कार्य (1198.53 लाख रुपये) और आईसीटी गतिविधियाँ (2.47 लाख रुपये) थीं। संस्थान की विस्तृत वित्तीय स्थिति तुलन-पत्र और आय और व्यय खाते में दी गई है।

महत्वपूर्ण घटनाएँ

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/व्याख्यान

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित सेमिनार/सम्मेलन/व्याख्यान/वेबिनार आयोजित किए:

नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार द्वारा विशेष व्याख्यान

नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी ने 1 अप्रैल, 2022 को भा.लो.प्र.सं. के टीएनसी मेमोरियल हॉल में 47वें एपीपीपीए के प्रतिभागियों को एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण तथा समृद्धि में योगदान देने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों पर बात की। उन्होंने विस्तार से बताया कि भारतीय नौसेना एक अनुकूल बाहरी और आंतरिक सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित करके 'हमारे देश और उसके नागरिकों की निर्बाध आर्थिक प्रगति और सामाजिक-राजनीतिक विकास' के राष्ट्रीय लक्ष्य को

प्राप्त करने की दिशा में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को कैसे देखती है। 47वें एपीपीपीपीए के कार्यक्रम निदेशक प्रोफेसर सुरेश मिश्रा और डॉ. श्यामली सिंह ने अतिथि और दर्शकों का स्वागत किया। इसके अलावा, एपीपीपीए प्रतिभागियों, भा.लो.प्र.सं. संकाय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

साइबर अपराध: वर्तमान खतरे और सुझाव पर कार्यशाला

साइबर अपराध: वर्तमान खतरे और सुझाव पर 11 अप्रैल, 2022 को एक खुला सत्र-सह-कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे भारतीय साइबर समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था। गृह मंत्रालय के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 41 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसमें सहभागिता की।

भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया। श्री एम. के. नारायण, आईएस, अतिरिक्त सचिव, सीआईएस, एमएचए ने प्रतिभागियों को बधाई दी। श्री आशुतोष अग्निहोत्री, आईएस, संयुक्त सचिव, सीआईएस, एमएचए ने सभा को संबोधित किया। श्री वी.एस.के. कौमुदी, आईपीएस, विशेष सचिव इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्री दीपक विरमानी, आईएस, उप सचिव, आई4सी, गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुरभि पांडे ने किया।

महानगरीय लचीलापन: भारत और वैश्विक पर वेबिनार

भा.लो.प्र.सं. में शहरी अध्ययन केंद्र ने 1 अप्रैल, 2022 को मेट्रोपॉलिटन रेंजिलिएंस: इंडिया एंड ग्लोबल पर एक आभासी बातचीत का आयोजन किया, भा.लो. प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया। डीएआरपीजी के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने विशेष टिप्पणी दी, इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट

के प्रिंसिपल प्रोफेसर पेड्रो बी ऑर्टिज मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर के.के. पांडे ने किया।

महानिदेशक भा.लो.प्र.सं. ने स्कोप कन्वेंशन में 4 अप्रैल, 2022 को ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व के विस्तार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के सत्र-I की अध्यक्षता की।

सत्र के दौरान, उन्होंने कहा कि पंचायत अधिनियमों में कर लगाने और ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायतों द्वारा ओएसआर एकत्र करने के प्रावधान हैं, लेकिन पंचायतों की ओर से ओएसआर एकत्र करने की इच्छा होनी चाहिए और लोगों को विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। भा.लो.प्र.सं. के डॉ. वी.एन. आलोक ने पंचायत वित्त पर एक प्रस्तुति दी और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डाला जो पंचायतों को कर आदि लगाने और विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए इसके उपयोग का अधिकार देता है।

शहरी शासन पर कार्यशाला

जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के महापौरों/अध्यक्षों और नगर आयुक्तों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए शहरी प्रशासन पर एक अभिविन्यास कार्यशाला 11 मई, 2022 को आयोजित की गई थी। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रोफेसर के.के. पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया और कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

यूक्रेन में युद्ध की स्थिति: ग्रेट बियर द्वारा अमेरिका और नाटो को चुनौती पर वेबिनार

4 मई, 2022 को यूक्रेन में युद्ध की स्थिति: ग्रेट बियर द्वारा अमेरिका और नाटो को चुनौती विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। भा.लो.प्र.सं.के महानिदेशक श्री एस. एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। डॉ. मनन द्विवेदी, संकाय,

भा.लो.प्र.सं. ने परिचयात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. राजीव नयन, ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. माखन सैकिया, राजदूत डी.बी. वेंकटेश वर्मा और अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, सीआईपीओडी, जेएनयू इस अवसर के दौरान प्रख्यात वक्ता थे। डॉ. द्विवेदी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

यूआईडीआई अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन पर कार्यशाला

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन तकनीक पर 28 जून, 2022 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। डॉ. सुरभि पांडे ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

2020 बैच के सहायक सचिवों के लिए कार्यशाला

29 जुलाई, 2022 को भा.लो.प्र.सं. में सहायक सचिवों (2020 बैच आईएस) के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. ईसी के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित थे। भारत सरकार में सहायक सचिव के रूप में तीन महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले 2020 बैच के नए आईएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने 2047 के लिए उनकी भूमिका को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि सिविल सेवक की भूमिका कितनी होगी, सिविल सेवक की भूमिका क्या होगी और क्या 2047 में सिविल सेवक की कोई भूमिका होगी, यह सवाल है। अपने समापन भाषण में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा सिविल सेवकों से कहा कि भा.लो.प्र.सं. जैसे संस्थानों से ज्ञान प्राप्त करने से उन्हें निर्णय लेने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, जिनका उन्हें राज्यों और जिलों में सामना करना पड़ेगा और उन्होंने अधिकारियों को उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए

अपनी शुभकामनाएं दीं। डीएआरपीजी के सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कार्यक्रम के दौरान 'शासन में सुधार' पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर के दौरान भा.लो. प्र.सं. डाइजैस्ट का नवीनतम संस्करण भी जारी किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव श्रीमती एस. राधा चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। श्री एस. एन. त्रिपाठी, महानिदेशक भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. और डॉ. सुरभि पांडे द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।

रिसर्जेंट एंड वाइब्रेंट इंडिया पर राष्ट्रीय सेमिनार @ 75

रिसर्जेंट एंड वाइब्रेंट इंडिया @75: री-एनर्जाइजिंग कोऑपरेटिव गवर्नेंस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार, कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ ऑल रूरल इंडिया (CNRI) के सहयोग से 20 जुलाई, 2022 को आयोजन किया गया था। इसे नाबार्ड और नाफेड द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रोफेसर सुरेश मिश्रा और डॉ. सपना चड्ढा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

ब्लॉकचेन को रहस्यमुक्त करने पर कार्यशाला

30-31 अगस्त, 2022 तक ब्लॉकचेन को नष्ट करने पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रोफेसर चारु मल्होत्रा कार्यक्रम समन्वयक थीं।

जल गुणवत्ता निगरानी पर कार्यशाला

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी पर 26 अगस्त, 2022 का एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पर्यावरण प्रशिक्षण इकाई) (भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। प्रोफेसर विनोद के. शर्मा और डॉ. श्यामली सिंह कार्यक्रम समन्वयक थे।

सीपीएसई में लैंगिक संवेदीकरण और महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला

सीपीएसई में लैंगिक संवेदीकरण और महिला सशक्तिकरण पर 14-16 सितंबर, 2022 तक एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों में लैंगिक संबंधी सभी मुद्दों का समाधान करना था। डॉ. नीतू जैन एवं डॉ. मनन द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।

शहरी शासन पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम सह कार्यशाला

शहरी अध्ययन केंद्र (सीयूएस), भा.लो.प्र.सं. के तहत 21-23 अक्टूबर, 2022 तक जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के महापौरों/अध्यक्षों और नगर आयुक्तों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने श्रीनगर के उपमहापौरों और नगरसेवकों से भी बातचीत की। प्रोफेसर के.के. पांडे और डॉ. कुसुम लता ने कार्यक्रम का संचालन किया। कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

तनाव और स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन पर कार्यशाला

सीपीएसई में तनाव और स्वास्थ्य मुद्दों के प्रबंधन पर 10-12 अक्टूबर, 2022 तक एक तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठनात्मक प्रभावशीलता पर कर्मचारियों के व्यक्तित्व के बहुमुखी प्रभाव की मान्यता में इस प्रयास के पीछे तर्क देना था। इसका डॉ. नीतू जैन ने संचालन किया।

साइबर अपराध रोकथाम पर कार्यशाला

साइबर अपराध रोकथाम पर 2 नवंबर, 2022 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य साइबर वातावरण में प्रासंगिक सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ संगठन और उपयोगकर्ता की संपत्ति की सुरक्षा संपत्तियों की प्राप्ति और रखरखाव सुनिश्चित करना था। डॉ. सुरभि पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

‘रिपोजिशनिंग इंडिया @2047: रिविजिटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर नेशनल बिल्डिंग’ पर 15-16 दिसंबर, 2022 के दौरान उद्घाटन डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भा.लो. प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन त्रिपाठी ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। श्री राजेश अग्रवाल, आईएएस, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अध्यक्षीय भाषण दिया।

जन-केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत में जन-केंद्रित शहरी प्रशासन कार्यक्रम पर 6-7 दिसंबर, 2022 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और इस अवसर पर समापन भाषण दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 121 शहरी पेशेवर और अभ्यासकर्ता शामिल हुए। प्रोफेसर के.के. पांडे और डॉ. कुसुम लता ने कार्यक्रम का संचालन किया।

नागरिक सैन्य संबंधों पर विशेष व्याख्यान

20 दिसंबर, 2022 को 48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्य अधिकारियों के लिए नागरिक सैन्य संबंधों पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के माननीय राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) ने विशेष व्याख्यान दिया। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया। प्रोफेसर वी.एन. आलोक और डॉ. कुसुम लता, 48वें एपीपीपीए पाठ्यक्रम निदेशक और अन्य संकाय सदस्य उपस्थित थे। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

मानव-केंद्रित और रणनीतिक डिजाइन पर विशेष व्याख्यान

48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिकारियों के लिए 'प्रभावी निर्णय लेने के लिए मानव-केंद्रित और रणनीतिक डिजाइन' पर 9 दिसंबर, 2022 को एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था। प्रोफेसर पैट्रिक व्हिटनी, पूर्व डीन, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने विशेष व्याख्यान दिया। प्रोफेसर वी.एन. आलोक और डॉ. कुसुम लता, 48वें एपीपीपीए पाठ्यक्रम निदेशक और अन्य संकाय सदस्य उपस्थित थे। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया।

शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस विधि पर कार्यशाला

शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस मेथड पर 5 दिसंबर, 2022 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया। भा.लो.प्र.सं. संकाय: डॉ. नीतू जैन, डॉ. साकेत बिहारी, डॉ. सपना चड्ढा, डॉ. सुरभि पांडे और डॉ. गदाधर महापात्र ने कार्यशाला के दौरान प्रस्तुति दी। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। डॉ. श्वेता मित्तल कार्यशाला की विशेषज्ञ थीं। कार्यक्रम

का संचालन डॉ. नीतू जैन ने किया और कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

डिजाइन थिंकिंग पर कार्यशाला

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के सहयोग से 23-24 जनवरी, 2023 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए दो दिवसीय डिजाइन थिंकिंग कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और अन्य हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी प्रभागों में खुलेपन और सहयोग को प्रोत्साहित करना था। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने अतिथि का स्वागत किया। श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव, एमडीएसई और श्री जतींद्र नाथ स्वैन, सचिव, मत्स्य पालन ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया। सीबीसी के सदस्य श्री प्रवीण परदेशी ने कार्यशाला का सिंहावलोकन दिया। प्रोफेसर पैट्रिक व्हिटनी, निदेशक, डिजाइन प्रयोगशाला और प्रोफेसर आंद्रे नोगीरा, अध्यक्ष, भारत डिजाइन लैब ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। डॉ. नीतू जैन एवं डॉ. सुरभि पांडे कार्यक्रम समन्वयक रहीं।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए कार्यशाला

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए 27-28 जनवरी, 2023 तक दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश भर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मुकद्दमों के तेजी से निपटान के लिए लगातार बाधाओं को दूर कर रही है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नमानि गंगे कैलेंडर भी जारी किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रंजीत वसंतराव मोरे, डीओपीटी की अतिरिक्त सचिव श्रीमती रश्मि चौधरी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली

ने समापन भाषण दिया। कार्यशाला का संचालन डॉ. सपना चड्ढा ने किया। भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

कृषि में जीएम सरसों और आत्मनिर्भर भारत पर कार्यशाला

कृषि में जीएम सरसों और आत्मनिर्भर भारत पर 10 जनवरी, 2023 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग और प्रोफेसर त्रिलोचन महापात्र, पूर्व सचिव, डीएआरई, भारत सरकार सत्र के अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष थे। व्याख्यान में सभी संकाय सदस्यों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और 48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों के साथ-साथ अन्य चल रहे कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रोफेसर अशोक विशनदास ने कार्यक्रम का संचालन किया।

थल सेनाध्यक्ष का विशेष व्याख्यान

थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी ने 7 फरवरी, 2023 को चल रहे 48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों को एक विष्टोज व्याख्यान दिया। सत्र के दौरान, उन्होंने रक्षा बलों की आत्मनिर्भर पहल पर प्रकाश डाला और मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के परिवर्तन के स्तंभों पर जोर दिया। कार्यक्रम में भा.लो.प्र.सं. संकाय के सदस्यों और वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी भाग लिया। एपीपीपीए पाठ्यक्रम निदेशक प्रोफेसर वी.एन आलोक और डॉ. कुसुम लता द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया गया।

वायुसेना प्रमुख का विशेष व्याख्यान

वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी ने 9 फरवरी, 2023 को चल रहे 48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों के लिए एक विशेष व्याख्यान दिया। भा.लो.प्र.सं. संकाय के सदस्यों और वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। एपीपीपीए पाठ्यक्रम निदेशक प्रोफेसर वी. एन आलोक और डॉ. कुसुम लता द्वारा कार्यक्रम का समन्वय किया गया।

नौसेना प्रमुख द्वारा विशेष व्याख्यान

नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी ने 28 फरवरी, 2023 को चल रहे 48वें एपीपीपीए प्रतिभागियों के लिए एक विशेष व्याख्यान दिया। भा.लो.प्र.सं. संकाय के सदस्य और वरिष्ठ कर्मचारी, एमडीपी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का समन्वयन एपीपीपीए पाठ्यक्रम निदेशक प्रोफेसर वी.एन आलोक और डॉ. कुसुम लता द्वारा किया गया।

75वें वर्ष पर भारतीय कूटनीति पर सेमिनार

स्वतंत्रता के बाद के युग में पचहत्तर वर्षों में भारत की कूटनीति पर 9-10 फरवरी, 2023 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित किया गया था। सेमिनार का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पिछले दशकों से चली आ रही भारत की विदेश नीति पर फिर से विचार करने के लिए प्रासंगिक शिक्षाविदों और राजनयिकों को शामिल करना था। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनन द्विवेदी ने किया।

भा.लो.प्र.सं. के 69वें संस्थापक दिवस पर द्वितीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. ने अपने 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 29 मार्च, 2023 को द्वितीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष, श्री जगदीप धनखड़, माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. इसी के अध्यक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति जैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री शंकर दत्त, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और डीएआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव श्री एस. क्षत्रिय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने आगमन पर भा.लो.प्र.सं. परिसर में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। शासन: शक्तियों का पृथक्करण विषय पर स्मारक व्याख्यान देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा, 'राष्ट्रीय ख्याति के इस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इसकी सराहना करता हूँ कि भा.लो.प्र.सं. प्रशासन और छात्रवृत्ति को एक साथ लाता है।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन एक गतिशील अवधारणा है और सार्वजनिक प्रशासकों को नागरिकों की बदलती अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप रहना होगा। अगले 25 वर्ष देश के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज जो सिविल सेवक शामिल हो रहे हैं, वे '2047 के योद्धा' होंगे। उन्होंने कहा कि आज, भारत बढ़ रहा है, आकांक्षाओं और नवाचारों की वृद्धि से प्रेरित है और हमारे नागरिकों की उपलब्धियों से प्रमाणित है। उन्होंने सरकार की विभिन्न नागरिक-केंद्रित कल्याण योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। हाल के समय के भारत के, 'शासन : शक्तियों का पृथक्करण' विषय पर बोलते हुए, उन्होंने राज्य के तीन अंगों के बीच 'नाजुक संतुलन' की प्रकृति को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि इसे बनाए रखा जाना चाहिए। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री और ईसी भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी बात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक प्रशासन के मामलों में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण की अवधारणा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद, उन्होंने हमें जो सबसे पहला मंत्र दिया था, वह था 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार'। माननीय केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भा.लो.प्र.सं. पाठ्यक्रमों में बदलाव आया है और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों के अलावा आत्मनिर्भर भारत और मिशन कर्मयोगी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, "यह पाठ्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाता है और इससे ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं का अच्छा प्रदर्शन हुआ है। इससे अधिकारियों को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को बेहतर ढंग से समझने और सराहना करने में मदद मिली है। कार्यक्रम के दौरान संकाय डॉ. श्यामली सिंह द्वारा भा.लो.प्र.सं. की कॉफी

टेबल बुक और श्री एस.एन. त्रिपाठी और डॉ. साकेत बिहारी द्वारा भारत रत्न: इम्पायरिंग वर्क्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. द्वारा कार्यक्रम का संचालन और समन्वयन किया गया। 48वें एपीपीपीए के प्रतिभागियों के अलावा, भा.लो.प्र.सं. के संकाय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ चल रहे कार्यक्रमों के अन्य प्रशिक्षुओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली में बदलते रुझान पर संगोष्ठी

भारत में राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली में बदलते रुझान पर 14-15 मार्च, 2023 को एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। यह सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भा.लो.प्र.सं. में सामाजिक न्याय में डॉ. अंबेडकर चेयर, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय राजनीति विज्ञान संघ के साथ साझेदारी में किया गया था। माननीय जनजातीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा, मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉ. नूपुर तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

डॉ. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. में डॉ. अंबेडकर चेयर ने 13 मार्च, 2023 को डॉ. अंबेडकर के संविधान और बदलती सामाजिक गतिशीलता पर एक स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और सदस्य, एनएचआरसी ने व्याख्यान दिया। भा.लो.प्र.सं. में डॉ. अंबेडकर चेयर की डॉ. नूपुर तिवारी, चेयर प्रोफेसर ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

यू-20 एजेंडा पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भा.लो.प्र.सं. के शहरी अध्ययन केंद्र ने 22-24 मार्च, 2023 तक नगरपालिका सेवाओं के लिए यू-20 एजेंडा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. डेविड डोडमैन, महानिदेशक, एचआईएस, नीदरलैंड

मुख्य वक्ता थे। कार्यशाला का संचालन प्रो. के.के. पांडे, डॉ. कुसुम लता, डॉ. सचिन चौधरी और डॉ. अमित कुमार सिंह ने किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव ने समापन टिप्पणी दी।

संस्थान के प्रतिष्ठित आगंतुक

भा.लो.प्र.सं. ने 17 जून, 2022 को नाइजीरिया के संघीय सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. तुकुर बेल्लो इंगावा और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम का भा.लो.प्र.सं. में स्वागत किया।

भा.लो.प्र.सं. ने 30 सितंबर, 2022 को पीएमओ और लोक सेवा विभाग/कार्मिक, श्री लोह खुम येन के नेतृत्व में सिंगापुर से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। श्री एस.एन त्रिपाठी ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का संचालन किया।

एच.एच 14वें दलाई लामा ने भा.लो.प्र.सं. का दौरा

संस्थान ने भा.लो.प्र.सं. के टीएनसी मेमोरियल हॉल में 21 जनवरी, 2023 को 'करुणा और सुशासन' पर उद्घाटन टीएन चतुर्वेदी मेमोरियल व्याख्यान की मेजबानी की। परम पावन 14वें दलाई लामा ने विशेष व्याख्यान दिया। यह कार्यक्रम श्री टी.एन. चतुर्वेदी के परिवार द्वारा भा.लो.प्र.सं. और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। श्री टी.एन चतुर्वेदी कर्नाटक और केरल के पूर्व राज्यपाल और भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। परम पावन ने करुणा के गुण और सुशासन में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने दर्शकों से भी बातचीत की और सभी से व्यक्तिगत स्तर पर भी करुणा का व्यवहार करने को कहा। 2000 की शुरुआत में अपनी आखिरी यात्रा के बाद यह भा.लो.प्र.सं. में उनकी दूसरी यात्रा थी। भा.लो.प्र.सं. के महानिदेशक श्री एस.एन त्रिपाठी ने परम पावन का स्वागत किया, जबकि भा.लो.प्र.सं. के कुलसचिव श्री अमिताभ रंजन ने कार्यक्रम का समन्वय और संचालन किया।

तंजानिया सरकार की माननीय मंत्री सुश्री जेनिस्टा म्हागामा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय तंजानिया प्रतिनिधि मंडल ने 6 जनवरी, 2023 को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया। विचारों के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण के लिए संभावित सहयोग पर चर्चा की गई।

इटालियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल में प्रोफेसर पाओला सेवेरिनो, अध्यक्ष, इटालियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजदूत गैयानी एनालिसा जेजा, कृषि और खाद्य अताशे और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने 28 फरवरी, 2023 को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव भा.लो.प्र.सं. ने दौरे का समन्वय किया।

नेपाल के माननीय राजदूत डॉ. शंकर पी शर्मा ने 20 फरवरी, 2023 को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया।

शैक्षणिक केंद्र/चेयरस

शैक्षणिक केंद्र, जिनमें से प्रत्येक में अध्ययन के संबंधित क्षेत्र में रुचि, अनुभव और विशेषज्ञता वाले संकाय सदस्यों का एक समूह शामिल है, समय-समय पर मिलते हैं (ए) अनुसंधान और प्रशिक्षण के अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य की वार्षिक योजना तैयार करते हैं, और उस पर समय-समय पर समीक्षा करें; (बी) व्यक्तिगत कार्य योजनाओं पर चर्चा, समन्वय और समीक्षा करना; (सी) सदस्यों की शैक्षणिक बातचीत और व्यावसायिक विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना; और (डी) अंतर-विषयक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अन्य शैक्षणिक समूहों के साथ समन्वय करना। महानिदेशक द्वारा केंद्र समन्वयकों को नामित किया जाता है। संस्थान की तंग वित्तीय स्थिति के कारण प्रत्येक शैक्षणिक केंद्र को अपनी गतिविधियों के लिए धन की तलाश करनी पड़ती है। 31 मार्च, 2023 तक शैक्षणिक केंद्रों की सदस्यता संरचना **अनुलग्नक-एफ.4** में दिखाई गई है।

विभिन्न आईआईपीए संकाय (भा.लो.प्र.सं. के भीतर आयोजित प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा) के शैक्षणिक योगदान का विवरण **अनुलग्नक-एफ.5** में दिया गया है।

शहरी अध्ययन केंद्र

अनुलग्नक-एफ.9 के अनुसार

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र

वर्ष 2022-23 के दौरान उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की शैक्षणिक गतिविधियाँ

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	संबद्ध संकाय
1.	भारतीय डाक सेवा के परिवीक्षाधीनों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम	28-30 जून, 2022	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. ममता पठानिया
2.	'पुनर्जीवित और जीवन्त भारत @75-सहकारी शासन को पुनः सक्रिय करना' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार	20 जुलाई, 2022	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. सपना चड्ढा
3.	उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति में ऑनलाइन डिप्लोमा पाठ्यक्रम	1 दिसंबर, 2022 28 फरवरी, 2023	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. सपना चड्ढा डॉ. ममता पठानिया
4.	अमेज़ॅन इंडिया द्वारा संचालित 'स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना' विषय पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह	15 मार्च 2023	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. सपना चड्ढा
5.	उपभोक्ता संरक्षण पर स्ट्रीम: कानून और नीतियां	48वां एपीपीपीए	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. ममता पठानिया

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	संबद्ध संकाय
1.	एनसीएच के माध्यम से एकीकृत शिकायत समाधान प्रणाली	डीओसीए, भारत सरकार	जून, 2022

तैयार किये गये शोध प्रस्ताव एवं उनका स्टेटस

क्रमांक	नाम	को प्रस्तुत	वर्तमान स्टेटस
1.	जीएसटी और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर परियोजना प्रस्ताव	वस्तु एवं सेवा कर महानिदेशालय, नई दिल्ली	विचाराधीन
2.	उपभोक्ता संरक्षण में स्कूली बच्चों के लिए इंटरएक्टिव संवेदीकरण प्रोग्राम का प्रस्ताव	अमेज़ॅन इंडिया	रु. 20 लाख स्वीकृत
3.	भारत का प्रशासनिक इतिहास	भा.लो.प्र.सं. की आंतरिक फंडिंग	जारी है
4.	भारत में जिला शासन का दस्तावेजीकरण (संस्थाएं, संरचनाएं और प्रणालियां)	भा.लो.प्र.सं. आंतरिक फंडिंग (क्षेत्रीय शाखाएं)	जारी है

प्रो.सुरेश मिश्रा द्वारा दिए गए व्याख्यान/ लिए गए सत्र /प्रस्तुत किए गए पेपर इत्यादि (अनुलग्नक-एफ.5 में संकाय योगदान में उल्लिखित)

डॉ. सपना चड्ढा द्वारा दिए गए व्याख्यान/लिए गए सत्र/प्रस्तुत किए गए पेपर (अनुलग्नक-एफ.5 में संकाय योगदान में उल्लिखित)

डॉ. ममता पठानिया द्वारा दिए गए व्याख्यान /लिए गए सत्र /प्रस्तुत किए गए पेपर (अनुलग्नक-एफ.5 में संकाय योगदान में उल्लिखित)

संकाय योगदान में उल्लिखित)

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सूखा प्रशासन केंद्र

भा.लो.प्र.सं. में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सूखा प्रशासन के लिए एक पूर्ण केंद्र है और जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय घटनाओं से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करने की विशेषज्ञता है।

अनुसंधान परियोजना			
क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना समन्वयक	अवधि
1.	गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	जुलाई 2020 - जून 2023

नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम - मास्टर प्रशिक्षकों और स्कूली विद्यार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

मास्टर प्रशिक्षकों की कुल संख्या: 319
स्कूली विद्यार्थियों की कुल संख्या: 4,657

नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम- मास्टर प्रशिक्षकों और स्कूली विद्यार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

कॉलेज विद्यार्थियों की कुल संख्या : 735

नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम- आध्यात्मिक समुदाय और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आध्यात्मिक समुदाय और अन्य हितधारकों की कुल संख्या: 600

नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम- सामान्य जनता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

सामान्य जनसमूह की कुल संख्या: 1,775

नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम- शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अधिकारियों की कुल संख्या : 441

अनुसंधान परियोजना			
क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना समन्वयक	अवधि
1.	गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम-फेज-II	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	अगस्त 2023 - मार्च 2026

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची (अनुलग्नक- एफ.2) में किया गया है।

प्रकाशनों (अनुलग्नक-एफ.5 में संकाय योगदान में उल्लिखित)

चल रही अनुसंधान परियोजना

1. गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम- फेज-II नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा एकीकृत संरक्षण मिशन 'नमामि गंगे' के तहत अगस्त 2023. में तीन वर्ष की परियोजना 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम -फेज-II सौंपी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम हितधारकों को गंगा के महत्व के बारे में जागरूक करना और हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा के कार्याकल्प के साथ-साथ प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने और संरक्षण के उद्देश्यों को पूरा करना है।

आर्थिक विकास और प्रबंधन अध्ययन केंद्र का शैक्षणिक योगदान (2022-2023)

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला

(प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित अनुलग्नक एफ.2 में)

पूर्ण अनुसंधान परियोजना

(अनुलग्नक एफ.1 में पूर्ण और चालू अनुसंधान परियोजनाओं की सूची में उल्लिखित)

प्रकाशन

(अनुलग्नक एफ 5 में संकाय योगदान में उल्लेख किया गया है)

प्रशासनिक और कार्मिक मामले

ए. नियुक्तियाँ/ज्वाइनिंग

(i) शहरी वित्त में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वी.एन आलोक को दिनांक 28.07.2022 से दो वर्ष के

लिए परिवीक्षा पर शैक्षणिक वेतन स्तर -14 में शहरी वित्त में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया है।

(ii) ई-गवर्नेंस और आईसीटी में डॉ. चारु मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर को दिनांक 28.07.2022 से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर शैक्षणिक वेतन स्तर-14 में ई-गवर्नेंस और आईसीटी में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया है।

(iii) डॉ. नूपुर तिवारी को दिनांक 28.02.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शैक्षणिक वेतन स्तर-14 में सामाजिक न्याय में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर चेयर में डीम्ड प्रतिनियुक्ति के आधार पर चेयर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है।

बी. सेवा का विस्तार (अनुबंध के आधार पर)

i. शहरी विकास के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमित कुमार सिंह की नियुक्ति की अवधि दिनांक 25. 10.2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

ii. एप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर प्रोफेसर अशोक कुमार विशनदास की नियुक्ति की अवधि दिनांक 02.11.2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

iii. लोक प्रशासन के प्रोफेसर (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता के साथ) प्रोफेसर सुरेश मिश्रा की नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.01.2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

iv. आपदा प्रबंधन के प्रोफेसर प्रो. वी. के. शर्मा की नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.03.2023 को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

v. शहरी विकास के प्रोफेसर प्रोफेसर के.के. पांडे की नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.03.2023 को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

vi. श्री ओ.पी. चावला, उप कुलसचिव (वित्त एवं प्रशासन) की नियुक्ति की अवधि दिनांक 01.02. 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

- vii. श्री के.एस. रांगा, कार्यकारी अभियंता की नियुक्ति की अवधि को दिनांक 14.02.2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

सी. निम्नलिखित संकाय और कर्मचारी सदस्य संस्थान की सेवाओं से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए

- I- श्रीमती नीलम हांडा, निजी सचिव, दिनांक 30.11.2022 को सेवानिवृत्त हुईं
- II- श्रीमती मैथिली, सहायक कुलसचिव, दिनांक 28.02.2023 को सेवानिवृत्त हुईं

डी. कर्मचारी संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त/मुक्त/अन्यत्र प्रतिनियुक्त

- प्रोफेसर सी. शीला रेड्डी को कार्यालय आदेश भाग II- 33/2023 दिनांकित 28.02.2023 (पूर्वा.) के माध्यम से सामाजिक-राजनीतिक विकास (अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान) में भा.लो.प्र.सं. में चेयर प्रोफेसर, डॉ. अंबेडकर चेयर और एसोसिएट प्रोफेसर के वास्तविक स्टेटस से प्रतिनियुक्ति पद से कार्यमुक्त कर दिया गया।

ई. कर्मचारी की मृत्यु

- श्री अतर सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक का दिनांक 21.04.2022 को निधन हो गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए टीए/डीए और मानदेय का विवरण

- (ए) वर्ष 2022-2023 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए मानदेय और वेतन का विवरण।
- अनुलग्नक एफ.10 देखें।

आभार

हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

हमारा विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री और भा.लो.प्र.सं. कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हम मंत्रालय के सभी अधिकारियों, विशेषकर श्रीमती राधा एस. चौहान, सचिव डीओपीटी, श्रीमती रश्मि चौधरी, अतिरिक्त सचिव, श्री राहुल सिंह, अतिरिक्त सचिव, श्री एस.डी. शर्मा, संयुक्त सचिव, श्री राजुल भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और श्री ए.एन. नारायणन, निदेशक (प्रशिक्षण) को संस्थान के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद।

इसके अलावा हम सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार और उसके अधिकारी, विशेष रूप से श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, डीएआरपीजी, श्री अश्वनी राजपूत, संयुक्त सचिव, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी), नीति आयोग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी जनजातीय मामले और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ-साथ भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों में उनकी निरंतर रुचि के लिए विदेशी सरकारों सहित अन्य सभी विभाग के आभारी हैं। हम अपने अधिकारियों की क्षमता निर्माण में हमारे साथ सहयोग करने के लिए राज्य सरकारों, विशेष रूप से बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारा आभार संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और सहयोगी कर्मचारियों के प्रति भी आभार है।

वित्त एवं लेखा, राजस्व लेखा (नकद आधार पर)

प्राप्तियां

अपने स्वयं के संसाधन उत्पन्न करने के अलावा, संस्थान को कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य से अनुदान प्राप्त हुआ। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऐसी प्राप्तियों का विवरण इस प्रकार है:

धनराशि (लाख रुपये में)		टिप्पणियाँ	
ए. सरकार से अनुदान		निम्नानुसार ब्रेक-अप (लाख रुपये में)	
1.	वेतन	1099.93	(i) प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विभिन्न शुल्क-आधारित शुल्क 944.69
2.	सामान्य	900.00	(ii) उपयोगकर्ता शुल्क 143.67
3.	पूँजीगत	1201.00	(iii) अनुसंधान कार्यों से शुद्ध आय 159.47
बी. भा.लो.प्र.सं. द्वारा अर्जित आंतरिक प्राप्तियां		1325.09	(iv) सदस्यता शुल्क (सदस्यता निधि पर ब्याज सहित) 12.04
			(v) प्रकाशनों की बिक्री 8.72
			(vi) विविध प्राप्तियां 56.50
		कुल	1325.09

इस प्रकार वर्ष 2022-23 के दौरान संस्थान को कुल प्राप्तियां 4526.02 लाख रुपये थीं।

व्यय

4526.02 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले, रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान भुगतान निम्नानुसार 4525.43 लाख रुपये था:

	(लाख रुपये में)
1. स्थापना (वेतन एवं भत्ते)	1250.66
2. शुल्क आधारित एवं प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	682.54
3. पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ (परिऑडिक्स)	15.60
4. प्रकाशन	8.47
5. पेन्शन	831.00
6. शाखा गतिविधियों का प्रचार	10.70
7. छात्रावास के सामान्य शुल्क, पानी और बिजली शुल्क, किराया, दरें और कर सहित कैम्पस रखरखाव	376.28
8. प्रशासनिक एवं विविध खर्चे	100.06
9. परिसंपत्ति की खरीद	25.51
10. सीजीएचएस को भुगतान की गई धनराशि	14.45
11. जीएसटी/प्रीमियम खर्चे	9.16
12. पूँजीगत खर्चे	1201.00
	
कुल	4526.43

वर्ष यानी 2021-22 के अंत में संचयी घाटा 7.83 लाख रुपये था। हालाँकि, संस्थान वर्ष 2022-23 के अंत में केवल 7.24 लाख रुपये की संचयी कमी का प्रबंधन करने में सक्षम था।

शहरी अध्ययन केंद्र (सीयूएस)

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से 322.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सीयूएस प्रकाशनों की बिक्री से 0.20 लाख रुपये और बैंक ब्याज से 1.46 लाख रुपये अर्जित हुए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 114/- रुपये की कमी को पूरा किया गया।

323.66 लाख रुपये की कुल निधि (पिछली कमी रु.114/- के समायोजन के बाद), के प्रति 323.66 लाख रुपये का व्यय किया गया :

	(लाख रुपये में)
1. वेतन एवं भत्ते	237.42
2. पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ (परिऑडिकल्स)	3.34
3. यात्रा खर्चे	3.77
4. आधारिक संरचना	3.48
5. प्रकाशन का मुद्रण	1.26
6. अन्य आकस्मिकताएँ एवं विविध खर्चे	1.62
7. कैम्पस रखरखाव जिसमें कंप्यूटर सुविधा, सुरक्षा, दूरभाष शामिल है।	9.74
8. पानी और बिजली	6.58
9. ओवरहेड शुल्क	26.30
10. ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण व्यय	15.45
11. मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.38
12. अनुसंधान और केस स्टडी	14.32
कुल	323.66

285/- रुपये की कमी को अगले वर्ष (2023-24) में समायोजन के लिए आगे लाया गया है।

प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान अध्ययन आदि पर विशिष्ट अनुदान और व्यय।

प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान अध्ययनों और सेमिनारों इत्यादि के संचालन के लिए प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों से निम्नानुसार 1566.16 लाख रुपये का अनुदान/शुल्क प्राप्त हुआ:

	(लाख रुपये में)
1. 48वां अप्पा (विभिन्न प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों से)	286.51
2. अप्पा प्रतिभागियों द्वारा फील्ड विजिट/शोध प्रबंधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से	86.00
3. मंत्रालयों/विभागों (डीओपीटी के अलावा) और विशेष कार्यक्रमों, अनुसंधान	1193.65
4. अध्ययन, अनुसंधान/असाइनमेंट, सेमिनार के लिए अन्य संगठनों से	
कुल	1566.16

पिछले वर्ष का 1242.88 लाख रुपये का अव्ययित शेष भी सामने लाया गया। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि 2809.04 लाख रुपये थी।

उपर्युक्त के प्रति, विभिन्न कार्यक्रमों, अनुसंधान अध्ययनों आदि पर व्यय रु.1291.66 लाख जैसा कि नीचे बताया गया है :

	(लाख रुपये में)
1. 48वां अप्पा	70.22
2. अप्पा प्रतिभागियों द्वारा फील्ड विजिट/शोध प्रबंधन आदि	61.09
3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन/अनुसंधान कार्य और सेमिनार आदि।	1160.35
कुल	1291.66

1517.38 लाख रुपये की शेष धनराशि उपयोग के लिए अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दी गई है।

विदेशी योगदान (एफसीआरए)

वर्ष 2022-23 में ब्याज के रूप में 2.07 लाख रुपये की धनराशि अर्जित की गई और इस खाते में जमा की गई।

पिछले वर्ष से 20.81 लाख रुपये का अव्ययित शेष अग्रानीत किया गया। आगे लाया गया। इस प्रकार, कुल उपलब्ध धनराशि 22.88 लाख रुपये थी जिसके प्रति वर्ष के दौरान 8.82 लाख रुपये की धनराशि का उपयोग किया गया। 14.06 लाख रुपये की अव्ययित शेष धनराशि को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है।

मेसर्स जीएसए एंड एसोसिएट्स ने रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए संस्थान के खातों की लेखापरीक्षा की।

संस्थान ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास जारी रखा।

अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएँ

वर्ष के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित 17 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए जिनका विवरण **अनुलग्नक एफ.1 (ए)** में दिया गया है।

इनके अलावा, 9 चालू शोध अध्ययन थे जो **अनुलग्नक एफ.1 (बी)** में सूचीबद्ध हैं।

अनुलग्नक एफ.1 (ए)
पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ
(2022 से मार्च 2023)

क्रमांक	परियोजना	परियोजना समन्वयक	एजेंसी
1.	एमएसएमई को व्यावसायिक सहायता (भारत में एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय नीति की तैयारी)	प्रो. के.के पांडे डॉ. सचिन चौधरी डॉ. सपना चड्ढा	एमएसएमई मंत्रालय
2.	वन अधिकार अधिनियम, 2006-जमीनी वास्तविकता	डॉ. गदाधर महापात्र	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3.	इकाइयों/संस्थानों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने और खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों/ संस्थानों द्वारा उत्पन्न उत्पादन, बिक्री और रोजगार का अनुमान लगाने के लिए मूल्यांकन अध्ययन	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन के. तनेजा	खादी और ग्रामोद्योग आयोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
4.	पंचायत चुनावों पर नीति अनुसंधान अध्ययन	प्रो. वी.एन. आलोक	पंचायती राज मंत्रालय
5.	पंचायतों और विवाद समाधान पर अध्ययन	प्रो. वी.एन. आलोक	पंचायती राज मंत्रालय
6.	ई-कॉफी टेबल बुक की डिजाइनिंग और संकलन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	डॉ. सुरभि पांडे	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
7.	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. ममता पठानिया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
8.	जनकपुरी पश्चिम से राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश दिल्ली में आर.के. आश्रम कॉरिडोर तक डीएमआरसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सपना चड्ढा डॉ. अमित सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9.	ग्राम खानपुर, दिल्ली में डीएमआरसी परियोजना एयरो-सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर चरण-IV के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सपना चड्ढा डॉ. अमित कुमार सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी शिक्षाविदों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की योजना का प्रभाव आकलन	प्रो. चारु मल्होत्रा डॉ. पवन के. तनेजा	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
11.	आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत एमएफएल द्वारा सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	प्रो. अशोक विशनदास	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड

क्रमांक	परियोजना	परियोजना समन्वयक	एजेंसी
12.	श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत पीएम-एसवाईएम योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	डॉ. गदाधर महापात्र	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
13.	जीएपी विश्लेषण अध्ययन	प्रो. चारु मल्होत्रा	ट्राइफेड
14.	दक्षता कार्यक्रम आईएसटीएम का प्रभाव आकलन	प्रो. अशोक विशनदास डॉ सुरभि पांडे	क्षमता निर्माण आयोग
15.	आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण के रूप में उर्वरक विभाग की पारदर्शिता लेखापरीक्षा	प्रो. अशोक विशनदास	रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग
16.	फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	डॉ. सुरभि पांडे	विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग
17.	आईएस इनटेक अध्ययन	डॉ. सुरभि पांडे	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

अनुलग्नक एफ.1 (बी)
चल रही अनुसंधान परियोजनाएँ
(अप्रैल 2022 से मार्च 2023)

क्रमांक	अध्ययन का शीर्षक	संकाय का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	प्रो. वी.के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन
2.	पटना और आरा नगर निगम के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (सीडीएमपी) योजना	डॉ. साकेत बिहारी	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग)
3.	दिशा परियोजना- न्याय विभाग, भारत सरकार के कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन के लिए वेब पोर्टल विकास	डॉ. सपना चड्ढा डॉ. कुसुम लता डॉ. रोमा देबनाथ	न्याय विभाग
4.	ग्राम ताजपुर खुर्द, दिल्ली में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सपना चड्ढा डॉ. अमित कुमार सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5.	सोनिया विहार, दिल्ली में पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सपना चड्ढा डॉ. अमित कुमार सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
6.	अध्ययन भारत में घर खरीदने वालों पर रियल एस्टेट नियामक अधिनियम की प्रभावशीलता के प्रभाव आकलन अध्ययन	डॉ. अमित के सिंह डॉ. सपना चड्ढा	आईसीएसएसआर
7.	सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग विकसित करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई की शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का फील्ड आकलन	प्रो. वी.एन. आलोक	पंचायती राज मंत्रालय
8.	जिला शासन सूचकांक (डीजीजीआई-यूपी)	प्रो. चारु मल्होत्रा डॉ. पवन के. तनेजा	डीएआरपीजी, भारत सरकार डीएआर, उत्तर प्रदेश सरकार
9.	उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में लैंगिक सुरक्षा ऑडिट	डॉ. अमित के सिंह डॉ. सपना चड्ढा डॉ. कुसुम लता डॉ. रोमा देबनाथ	राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुलग्नक एफ.2

इस अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला (अप्रैल 2022 से मार्च 2023)

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मेट्रोपॉलिटन रेजिलिएशन पर वेबिनार: भारत और वैश्विक	1 अप्रैल, 2022	प्रो. के.के. पांडे	56
2.	14 सी, एमएचए (आई-4 सीएमएचए) के लिए साइबर अपराधा-वर्तमान व्यवहार और सुझाव पर ओपेन सत्र-सह कार्यशाला	11 अप्रैल, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
3.	नमामि गंगे के तहत ऑनलाइन 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	11-13 अप्रैल, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	636
4.	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक जांच पर न्यायिक अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। (आई-4 सीएमएचए)	18-22 अप्रैल, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	29
5.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	20-22 अप्रैल, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	10
6.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	4-6 मई, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	478
7.	नव नियुक्त सहायक निदेशकों के लिए प्रशिक्षण (भारतीय खेल प्राधिकरण, एसएआई द्वारा प्रायोजित)	9-20 मई, 2022	डॉ. साकेत बिहारी	10
8.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	11-13 मई, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सचिन चौधरी	22
9.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित ऑनलाइन 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	18-20 मई, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	509

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
10.	आईएफएस अधिकारियों के लिए 'योजनाओं की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन-कार्यान्वयन अधिकारियों की जिम्मेदारियां' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-27 मई, 2022	डॉ. साकेत बिहारी	20
11.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित ऋषिकेश में आध्यात्मिक नेताओं और समुदाय पर कार्यशाला	24-26 मई, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	2000
12.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	25-27 मई, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. अमित कुमार सिंह	30
13.	अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एनआईडीईएम द्वारा प्रायोजित)	6-10 जून, 2022	डॉ. ममता पठानिया	9
14.	भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारियों का मध्य-कैरियर प्रशिक्षण, चरण-I।	6-17 जून, 2022	डॉ. पवन तनेजा डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. ममता पठानिया	25
15.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	13 जून, 2022	डॉ. ममता पठानिया	33
16.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	14 जून, 2022	डॉ. ममता पठानिया	40
17.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	15 जून, 2022	डॉ. ममता पठानिया	42
18.	भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम	17 जून, 2022	डॉ. ममता पठानिया	38

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
19.	ऑनलाइन 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण' (ऑनलाइन)	22-24 जून, 2022	प्रो. विनोद शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	488
20.	वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम यूआईडीएआई अधिकारियों के लिए 'साइबर सुरक्षा और ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी' (यूआईडीएआई द्वारा प्रायोजित)	28 जून, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
21.	कार्यशाला 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर परिवीक्षाधीन' डाक सेवा विभाग (आरएएनकेपीए)	28-30 जून	डॉ. ममता पठनिया	33
22.	लोक प्रशासन का 48वां एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम (डीओपीटी द्वारा प्रायोजित)	1 जुलाई, 2022 से अप्रैल, 2023 तक	प्रो. वी.एन. आलोक डॉ. कुसुम लता	38
23.	ईईई के लिए 'वित्त खाता, खरीद, प्रबंधन और लेखापरीक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंडियन एकेडमी ऑफ हार्डवे इंजीनियर्स (आईएचई) द्वारा प्रायोजित)	18-29 जुलाई, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन के. तनेजा	26
24.	'पुनर्जीवित और जीवंत भारत / 75 : सहकारी शासन को फिर से सक्रिय करना' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (नाबार्ड और नेफेड द्वारा प्रायोजित)	20 जुलाई, 2022	डॉ. सपना चड्ढा प्रो. सुरेश मिश्रा	80
25.	सीबीसी, आईएसटीएम के सहयोग से 2020 बैच के सहायक सचिवों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला (डीओपीटी द्वारा प्रायोजित)	29 जुलाई, 2022	श्री अमिताभ रंजन डॉ. सुरभि पांडे	176
26.	नमामि गंगे, गंगा परिप्रेक्ष्य प्रदर्शनी के तहत गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	8-15 अगस्त, 2022	प्रो. विनोद शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	478
27.	लीन भारत पर 10वां एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम (पीएसयू द्वारा प्रायोजित)	22 अगस्त से 20 सितंबर, 2022	डॉ. नीतू जैन डॉ. सचिन चौधरी	11
28.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	22-26 अगस्त, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	35
29.	सीआईएसओ प्रोग्रामनेजीडी प्रायोजित	22-26 अगस्त, 2022	प्रो. चारु मल्होत्रा	39

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
30.	आईटीएस 2019 बैच के लिए 'सार्वजनिक नीति निर्माण' पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण	22-26 अगस्त, 2022	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. ममता पठानिया	8
31.	साइबर इको सिस्टम विकसित करने और साइबर अपराधा की रोकथाम के लिए उपाय (14 सी, एमएचए द्वारा प्रायोजित)	26 अगस्त, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	100
32.	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (सीबीसी, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित) के तहत 'वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी' पर एक दिवसीय कार्यशाला	26 अगस्त, 2022	प्रो विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	15
33.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	29 अगस्त- 2 सितम्बर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	39
34.	संयुक्त सचिवों के लिए ब्लॉक चैन पर विषयगत कार्यशाला 1	30 अगस्त, 2022	प्रो. चारु मल्होत्रा	16
35.	निदेशकों के लिए ब्लॉक चैन पर विषयगत कार्यशाला 2	31 अगस्त 2022	प्रो. चारु मल्होत्रा	20
36.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	5-9 सितम्बर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
37.	'शुरुआती लोगों के लिए डेटा एनालिटिक्स' (ई-आईटीईसी) पर ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	5-9 सितंबर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन के. तनेजा	36
38.	भारत में मलिन बस्तियों के पुनरोत्तर पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला	5-7 सितंबर, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. अमित कुमार सिंह	11
39.	आईसीएआरई, देहरादून के प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए 'प्रशासनिक सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही'	12-14 सितम्बर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. अमित सिंह	25
40.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	12-16 सितंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
41.	हिंदी दिवस भारत और समकालीन वैश्विक सत्ता केंद्र/बहु ध्रुवीय विश्व	14 सितम्बर, 2022	प्रो. के.के. पांडे	100
42.	'लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण' पर आवासीय कार्यशाला	14-16 सितम्बर, 2022	डॉ. नीतू जैन डॉ. मनन द्विवेदी	30

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
43.	नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के हितधारकों के लिए 'गंगा जन भागीदारी महोत्सव' मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर कार्यशाला	17 सितम्बर, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	506
44.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	19-23 सितंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	36
45.	ईई (सिविल और इलेक्ट्रिकल), सीपीडब्ल्यूडी के लिए 'उच्च प्रशासन और कानूनी मामले' पर दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	19-30 सितंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे डॉ. अमित कुमार सिंह	36
46.	एसएआई (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित) के उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए सहायक निदेशकों हेतु एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	19-23 सितम्बर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	16
47.	ऑनलाइन वित्त और गैर-वित्त पृष्ठभूमि वाले नेतारू (आईटीईसी द्वारा प्रायोजित)	19-23 सितम्बर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन के. तनेजा	22
48.	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् के लिए 21वां फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीएसटी द्वारा प्रायोजित)	19 सितंबर से 11 नवंबर, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	16
49.	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (महाराष्ट्र सरकार, वनमती)	26-30 सितंबर, 2022	डॉ. सचिन चौधरी	90
50.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री आर. सुब्रह्मण्यम द्वारा 'महिलाओं के विकास पर 15वां डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण' पर स्मृति व्याख्यान (भा.लो.प्र.सं. द्वारा सामाजिक न्याय में डॉ. अंबेडकर चेंयर द्वारा प्रायोजित)	7 अक्टूबर, 2022	डॉ. नीतू जैन	100
51.	ऑनलाइन 'तनाव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का प्रबंधन' (डीपीई द्वारा प्रायोजित)	10-12 अक्टूबर, 2022	डॉ. नीतू जैन	36
52.	आईआरएस (एनएसीआईएन, सी एंड आईटी) के 73वें बैच के लिए 'सार्वजनिक नीति और प्रशासन' पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-13 अक्टूबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	32

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
53.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए ऑनलाइन मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	10-12 अक्टूबर, 2022	प्रो. विनोद शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	100
54.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	17-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	33
55.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायक निदेशकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	17-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	15
56.	सीजीएलई 2019 बैच के नव नियुक्त सहायक अनुभाग अधिकारियों-परिवीक्षाधीनों (एसओ-पीएस) के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (आईएसटीएम द्वारा प्रायोजित)	17-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	145
57.	श्रीनगर नगर निगम के लिए शहरी प्रशासन पर ईआर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम	19-21 अक्टूबर, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. कुसुम लता	19
58.	नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण ऑनलाइन कार्यक्रम	19-21 अक्टूबर, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	100
59.	शासन के लिए क्षमता निर्माण उभरती प्रौद्योगिकी (सीटीआई और एटीआई)	20-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	38
60.	नमामि गंगे के तहत ऑनलाइन 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	31 अक्टूबर- 2 नवंबर, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	30
61.	'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन	01 नवंबर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ श्री अमिताभ रंजन	140
62.	भा.लो.प्र.सं. में बैंकों, यूपीआई सेवा प्रदाताओं, ई-वॉलेट, फिनटेक कंपनियों और सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ साइबर अपराध रोकथाम पर कार्यशाला, (14सी एमएचए द्वारा प्रायोजित)	2 नवंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	120

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
63.	प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (महाराष्ट्र सरकार, वनमती)	7-11 नवंबर, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सचिन चौधरी डॉ. मनन द्विवेदी	74
64.	आईटीएस फेज-1 (बैच II) के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-25 नवंबर, 2022	डॉ. पवन तनेजा डॉ. रोमा देबनाथ	30
65.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर अनुभाग अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	25
66.	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के अधिकारियों के लिए डायरेक्ट ट्रेनर स्किल (डीटीएस) पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ	25
67.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
68.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से संगठन की उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायक निदेशक (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	14-25 नवंबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	25
69.	12वीं टी.पी. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शासन में उभरते रुझानों पर (वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् सभी स्तर के डीएसटी)	21-25 नवंबर, 2022	प्रो. विनोद के. शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	25
70.	‘संविधान दिवस’	25 नवंबर, 2022	डॉ. नीतू जैन	100
71.	कम आय वाले शहरी क्षेत्रों के लिए आजीविका संवर्धन पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला	28-30 नवंबर, 2022	प्रो. के.के. पांडे डॉ. अमित सिंह	30
72.	यशदा, महाराष्ट्र के परिवीक्षाधीन (समूह ए) अधिकारियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम	28 नवंबर- 3 दिसंबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. नीतू जैन	50
73.	उभरते रुझानों पर क्षमता निर्माण (सीबीसी)	29-30 नवंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	35
74.	एनवीएस के अधिकारियों के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28 नवंबर- 02 दिसंबर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ	24

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
75.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	28 नवंबर-02 दिसंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
76.	डेटा विश्लेषणात्मक और जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीईसी द्वारा प्रायोजित)	5-16 दिसंबर, 2022	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन तनेजा	32
77.	वरिष्ठ वास्तुकार, सीपीडब्ल्यूडी के लिए 'उच्च प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन कार्यक्रम' पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	5-16 दिसंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	20
78.	'शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस विधि' पर एक दिवसीय कार्यशाला (विशेषज्ञ- डॉ. श्वेता मित्तल)	5 दिसंबर 2022,	डॉ. नीतू जैन	30
79.	भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन सीयूएस	6-7 दिसंबर, 2022	प्रो. के.के. पांडे	147
80.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	12-16 दिसंबर, 2022	डॉ. साकेत बिहारी डॉ. मनन द्विवेदी	25
81.	'राष्ट्र निर्माण के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर दोबारा गौर करना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन-II: स्मारक व्याख्यान श्रृंखला	15-16 दिसंबर, 2022	डॉ. नीतू जैन	50
82.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	19-23 दिसंबर, 2022	डॉ. सुरभि पांडे	40
83.	यशदा, महाराष्ट्र के परिवीक्षाधीन (समूह ए) अधिकारियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम	19-23 दिसंबर, 2022	डॉ. मनन द्विवेदी डॉ. अमित कुमार सिंह	60
84.	ग्रामीण समाजों (महिला घटक) के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 11वीं टी.पी. (वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् सभी स्तर डीएसटी)	19-23 दिसंबर, 2022	प्रो. चारु मल्होत्रा	21
85.	ब्रिगेडियर डॉ. बी. डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त), अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के माननीय राज्यपाल द्वारा नागरिक सैन्य संबंधों पर विशेष व्याख्यान	20 दिसंबर, 2022	श्री अमिताभ रंजन	150

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
86.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	3-7 जनवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	83
87.	नमामि गंगे के तहत गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण ऑनलाइन कार्यक्रम	04-06 जनवरी, 2023	प्रो विनोद के शर्मा डॉ. श्यामिली सिंह	30
88.	कर्गिस्तान सरकार (आईटीईसी) के लिए निवेश परियोजनाओं की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी पर ऑनलाइन विशेष कार्यक्रम	9-20 जनवरी, 2023	डॉ. पवन तनेजा डॉ. रोमा देबनाथ	18
89.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	9-13 जनवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	37
90.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	9-13 जनवरी, 2023	डॉ. साकेत बिहारी	25
91.	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक जांच (14 सी एमएचए द्वारा प्रायोजित)	9-13 जनवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	24
92.	सीटीए (प्रायोजित लोक सेवा आयोग, सीटीए) के निपटान अधिकारियों के लिए उच्च नेतृत्व कार्यक्रम	9-13 जनवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	18
93.	11वीं टी.पी. वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए वैज्ञानिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन पर (वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद्, सभी स्तर डीएसटी)	16-20 जनवरी, 2023	डॉ. पवन तनेजा	25
94.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	16-20 जनवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	40
95.	डिजाइन प्रशिक्षण कार्यशाला (क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रायोजित)	18-19 जनवरी, 2023	डॉ. नीतू जैन डॉ. सुरभि पांडे	40
96.	करुणा और सुशासन पर परमपावन 14वें दलाई लामा द्वारा विशेष व्याख्यान	21 जनवरी, 2023	श्री अमिताभ रंजन	160
97.	केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण (कैट) के सदस्यों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला	27-28 जनवरी, 2023	डॉ. सपना चड्ढा	50

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
98.	महाराष्ट्र सरकार के परिवीक्षार्थियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम (वनमती द्वारा प्रायोजित)	31 जनवरी, 4 फरवरी, 2023	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सचिन चौधरी डॉ. मनन द्विवेदी	90
99.	‘कानूनी और अनुशासनात्मक मामलों’ पर ऑनलाइन पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम (सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एमईएस) द्वारा प्रायोजित)	30 जनवरी- 3 फरवरी, 2023	डॉ. सपना चड्ढा	18
100.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	30 जनवरी- 3 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	32
101.	महाराष्ट्र सरकार के परिवीक्षार्थियों के लिए अध्ययन यात्रा कार्यक्रम (वनमती द्वारा प्रायोजित)	7-11 फरवरी, 2023	प्रो. के.के. पांडे डॉ. सचिन चौधरी डॉ. मनन द्विवेदी	90
102.	तकनीकी कार्मिकों के लिए 17वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डीएसटी द्वारा प्रायोजित)	06-17 नवम्बर, 2023,	प्रो. विनोद शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	22
103.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	6-10 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	40
104.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	13-17 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	80
105.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	13-17 फरवरी, 2023	डॉ. साकेत बिहारी	40
106.	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक जांच (14 सी एमएचए द्वारा प्रायोजित)	13-17 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	25
107.	भारतीय रक्षा संपदा सेवा राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन (एनआईडीईएम), रक्षा मंत्रालय के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए ‘लोक प्रशासन’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-17 फरवरी, 2023	डॉ. ममता पठानिया	6
108.	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक जांच (14 सी एमएचए द्वारा प्रायोजित)	20-24 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	24

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
109.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	20-24 फरवरी, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	36
110.	लोक निर्माण में परियोजना और जोखिम प्रबंधन (आईटीईसी)	20 फरवरी- 17 मार्च, 2023	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन तनेजा	33
111.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	27 फरवरी- 03 मार्च 2023	डॉ. सुरभि पांडे	85
112.	फ्रांस और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल के साथ 15 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 'संगठनात्मक प्रबंधन में नवाचारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम'	27 फरवरी से 13 मार्च 2023	डॉ. साकेत बिहारी	6
113.	डीएसटी, डीबीटी और एमओईएस के वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक चिंतन शिविर (डीएसटी द्वारा प्रायोजित)	3-4 मार्च, 2023	श्री अमिताभ रंजन	130
114.	सूचना प्रौद्योगिकी और उभरती प्रौद्योगिकी पर क्षमता निर्माण (भारत के जनगणना आयुक्त, सीसीआई द्वारा प्रायोजित)	06-10 मार्च, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	22
115.	प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर सहायकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई द्वारा प्रायोजित)	13-17 मार्च, 2023	डॉ. साकेत बिहारी	32
116.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	13-17 मार्च, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	74
117.	सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता पर एक सप्ताह लंबा प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायक अनुभाग अधिकारी (आईएसटीएम द्वारा प्रायोजित)	13-17 मार्च, 2023	डॉ. साकेत बिहारी	136
118.	अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सत्यवती कॉलेज (आईसीएसएसआर) सामाजिक न्याय में डॉ. अम्बेडकर चेयर	14-15 मार्च, 2023	डॉ. नूपुर तिवारी	100

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
119.	‘स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना (अमेजॉन द्वारा संचालित)’ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार सम्मेलन	15 मार्च 2023	प्रो. सुरेश मिश्रा डॉ. सपना चड्ढा	50
120.	साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक जांच (14 सी एमएचए द्वारा प्रायोजित)	20-24 मार्च, 2023	डॉ. सुरभि पांडे	25
121.	‘लोक प्रशासन और शासन सह एक्सपोजर विजिट’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बिपार्ड द्वारा प्रायोजित)	20-24 मार्च, 2023	डॉ. अमित सिंह डॉ. ममता पठानिया	57
122.	नगरपालिका सेवाओं के लिए यू-20 एजेंडा पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला	22-24 मार्च, 2023	प्रो. के.के. पांडे डॉ. कुमुम लता डॉ. सचिन चौधरी डॉ. अमित कुमार सिंह	67
123.	गंगा नदी के हितधारकों के लिए ऑनलाइन मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम छठा संवाद : गंगा संवाद	22 मार्च, 2023	प्रो विनोद के शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	150
124.	विकास और सतत विकास के लिए वैश्विक रणनीतिक नेतृत्व (आईटीईसी द्वारा प्रायोजित)	23 मार्च से 19 अप्रैल, 2023	डॉ. रोमा देबनाथ डॉ. पवन तनेजा	35
125.	गंगा नदी ‘नमामि गंगे’ के हितधारकों के लिए ऑनलाइन मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम	28-30 मार्च, 2023	प्रो विनोद के शर्मा डॉ. श्यामली सिंह	300
126.	‘लोक प्रशासन और शासन सह एक्सपोजर विजिट’ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बिपार्ड द्वारा प्रायोजित)	27-31 मार्च, 2023	डॉ. अमित सिंह डॉ. ममता पठानिया	60
127.	भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा ‘शासन : शक्तियों का पृथक्करण’ विषय पर 69वां स्थापना दिवस और द्वितीय डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मृति व्याख्यान	29 मार्च, 2023	श्री अमिताभ रंजन	220
	प्रतिभागियों की कुल संख्या			11313

अनुलग्नक एफ.3

शाखाओं की गतिविधियाँ (2022-2023)

क्षेत्रीय शाखाएँ

असम

द्विवार्षिक बैठक

असम क्षेत्रीय शाखा की द्विवार्षिक बैठक और उस दौरान मौजूदा सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और एक नई समिति का गठन किया गया। (13 नवंबर, 2022)

वार्षिक क्षेत्रीय कॉन्वेंट (प्रस्तावना सम्मेलन)

‘भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है’ पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावना सम्मेलन (16 अक्टूबर, 2022)

वार्ता

1. ‘निवाजब्रांड की सफलता की कहानी’ पर वार्ता (30 अगस्त, 2022)
2. ‘वित्तीय प्रक्रियाओं’ पर वार्ता।

अनुसंधान अध्ययन

1826 (यंदाबू की संधि) से 1972 (मेघालय का निर्माण) तक की अवधि को कवर करने वाले अविभाजित असम के प्रशासनिक इतिहास को पूरा करने के लिए शाखा द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजना पर काम करना।

बिहार

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/वेबिनार

1. ‘वैश्विक नेता के रूप में उभरता भारत’ विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी (14 अक्टूबर, 2022)।

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएं आदि

1. ‘बिहार में पंचायत राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली’ पर पैनल चर्चा (24 अप्रैल, 2022)

2. ‘बिहार में सुशासन में भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखा के योगदान की संभावनाएं’ पर पैनल चर्चा (09 दिसंबर, 2022)
3. पटना कॉलेज के सहयोग से ‘नीति प्रक्रिया के पहलू’ पर व्याख्यान आयोजित (25 जनवरी, 2023)।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये

(अनुसंधान विकास कार्यक्रम के तहत व्याख्यान)

1. कॉलेज के शिक्षकों और रिसर्च स्कॉलर के लिए एक कार्यशाला ‘अनुसंधान नैतिकता और गुणवत्ता प्रस्ताव और पेपर का विकास’ (20 मार्च, 2023)

प्रकाशन

1. बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम XIX नंबर 1 जनवरी-जून, 2022
2. बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम XIX नंबर 2 जुलाई - दिसंबर, 2022
3. बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉल्यूम XIX नंबर 2 एस जुलाई-दिसंबर 2022 (कानून और शासन पर अनुपूरक, फरवरी, 2023 में मुद्रित)

अन्य गतिविधियाँ

शाखा की वेबसाइट <www-iapabiharbranch-org> का रखरखाव और विकास

जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रीय शाखा

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/ प्रदर्शनी-सह-बातचीत

1. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर दो दिवसीय कार्यशाला (13-14 मई, 2022)

2. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों (डीएसपी/एसडीपीओ) के लिए एक दिवसीय कार्यशाला (10 सितंबर, 2022)।
3. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय शाखा ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), भारत सरकार के सहयोग से : अग्नि सुरक्षा का सार' (10 अक्टूबर, 2022) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
4. 'सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर पाकिस्तान को भारत का हालिया नोटिस, इसका महत्व और पृष्ठीभूमि' पर सेमिनार (25 मार्च, 2023)
5. प्रदर्शनी सह इंटरैक्शन जम्मू स्मार्ट सिटी : कनेक्टिंग द डॉट्स (18 जून, 2022)।

व्याख्यान बैठकें/पैनल चर्चाएं/बहसें/एजीएम/इंडा होस्टिंग समारोह/इत्यादि।

1. 'उद्योग अकादमिक साझेदारी के माध्यम से कौशल अंतर को पाटना' विषय पर 9वां श्री राम सहाय मेमोरियल व्याख्यान (25 जून, 2022)
2. 'भारत वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर व्याख्यान (23 सितंबर, 2022)
3. 'की बोर्ड लर्निंग औपचारिक शिक्षा का विकल्प नहीं है' विषय पर वार्षिक भा.लो.प्र.सं. बहस (20 जुलाई, 2022)
4. 'सदन की राय में, चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है और वित्तीय स्थिरता में बाधा डालता है' विषय पर 21वीं वार्षिक वीरन्ना ऐवल्ली मेमोरियल वाद-विवाद प्रतियोगिता (15 दिसंबर, 2022)

संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जम्मू और कश्मीर सरकार के मध्य और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में उच्च प्रदर्शन मानसिकता विकसित करने पर दो दिवसीय नेतृत्व कार्यक्रम। (26-27 अगस्त, 2022)

चल रहे अनुसंधान अध्ययन/परियोजनाएँ

1. अनुसंधान परियोजना : जम्मू-कश्मीर में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कामकाज पर प्रस्ताव। (1 मार्च, 2023)
2. अनुसंधान परियोजना : जम्मू क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय की शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन। (1 मार्च, 2023)
3. परियोजना : भारत में जिला प्रशासन (संस्थाएं, संरचनाएं और प्रणालियाँ) का दस्तावेजीकरण। (अक्टूबर, 2022)
4. 25वें राष्ट्रीय-शासन सम्मेलन (एनईजीसी) का दस्तावेजीकरण (26-27 नवंबर, 2022)।

प्रकाशन

1. भा.लो.प्र.सं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय शाखा न्यूजलैटर वॉल्यूम:XIII जुलाई, 2022 नंबर 1
2. भा.लो.प्र.सं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय शाखा न्यूजलैटर वॉल्यूम :XIII दिसंबर 2022 नंबर 2

झारखंड

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. ई-कॉमर्स पर एक दिवसीय सेमिनार - लाभ और हानि (24 सितंबर, 2022)
2. सतत नवाचार के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व पर एक दिवसीय संगोष्ठी (17 अक्टूबर, 2022)

अन्य गतिविधियाँ

हीमोग्लोबिन, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, तापमान और वजन इत्यादि की जांच के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर (23 सितंबर, 2022)

कर्नाटक

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी

1. 'कर्नाटक में शासन और विकास' पर दो दिवसीय संगोष्ठी (26-27 अप्रैल, 2022)

2. 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर एक प्रस्तावना सम्मेलन-2022, (9 सितंबर, 2022)

विशेष व्याख्यान/वेब वार्ता/पैनल चर्चा/पुस्तक चर्चा

1. 'लोकतंत्र और सुशासन' पर एक विशेष व्याख्यान (18 जून, 2022)
2. 'कर्नाटक में प्रशासनिक सुधार' पर एक विशेष व्याख्यान (01 जुलाई, 2022)
3. 'सरकार में भ्रष्टाचार -सीखे गए और छूटे गए सबक' पर एक व्याख्यान-चर्चा (30 नवंबर, 2022)
4. 'बेंगलुरु में बाढ़' पर एक पैनल चर्चा (10 जनवरी, 2023)
5. 'भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक कार्मिक प्रणाली : एक तुलनात्मक मूल्यांकन' पर एक विशेष व्याख्यान (12 जनवरी, 2023)
6. 'कर्नाटक में कोविड-19 का प्रबंधन - भविष्य के लिए सबक' पर एक गोलमेज बैठक 9 (13 जनवरी, 2023)
7. 'जेल सुधार' पर एक विशेष व्याख्यान (22 फरवरी, 2023)।

प्रकाशन

1 सितंबर, 2022 को शाखा की वार्षिक आम बैठक में भा.लो.प्र.सं.-केआरबी वर्चुअल न्यूजलेटर्स का सार-संग्रह-2 जारी किया गया था।

अन्य

1. सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन के क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में अक्टूबर, 2022 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा को 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शाखा' का पुरस्कार प्रदान किया गया।

3. श्री वी. बालासुब्रमण्यम, आईएस (सेवानिवृत्त) को अक्टूबर, 2022 में नई दिल्ली में एजीएम में 'भा.लो.प्र.सं. और लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं' के लिए भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली से पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
4. श्री मदन गोपाल, आईएस (सेवानिवृत्त) को उनके 'सार्वजनिक मामलों में विशिष्ट योगदान' के सम्मान में, कर्नाटक सरकार से 2022 राज्योत्सव पुरस्कार प्राप्त हुआ।

केरल

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

1. तटीय क्षेत्र सफाई अभियान, ऑल सेंट्स कॉलेज, तिरुवनंतपुरम (15 सितंबर, 2022)
2. तटीय क्षेत्र सफाई अभियान, चावरा सरकारी कॉलेज (22 सितंबर, 2022)
3. तटीय क्षेत्र सफाई अभियान, एमएसएम कॉलेज, कायमकुलम (22 सितंबर, 2022)
4. सुशासन पर संवैधानिक दृष्टिकोण। सरकारी कॉलेज अट्टापाडी (09 जनवरी, 2023)

व्याख्यान बैठकें/चर्चाएँ

1. भारतीय संविधान का दर्शन : प्रस्तावना डॉ. पी.जी. अलेक्जेंडर आईपीएस (सेवानिवृत्त) (25 नवंबर, 2022)
2. भारतीय संविधान का दर्शन, डॉ. डिंपी दिवाकरन (10 मार्च, 2023)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. भारतीय संविधान और शासन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, यूनिवर्सिटी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम (25 नवंबर, 2022)
2. भारतीय संविधान और शासन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, ऑल सेंट कॉलेज, तिरुवनंतपुरम (16 जनवरी, 2023)
3. सार्वजनिक नीतियों और शासन में प्रमाणपत्र

पाठ्यक्रम, दूसरा बैच, सेंट जॉन्स कॉलेज, आंचल
(09 जनवरी, 2023)

प्रकाशन

1. कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान केरल विश्वविद्यालय के तहत विद्यार्थियों के बीच अतिरिक्त कौशल का अधिग्रहण
2. न्यूजलैटर

महाराष्ट्र

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

‘भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है’
विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (21 अक्टूबर, 2022)
67वीं वार्षिक आम बैठक (29 सितम्बर, 2022)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से तनाव प्रबंधन (28 नवंबर, 2022)
2. लोक सेवा अधिकार अधिनियम-2015 (नवंबर 29, 2022)
3. सरकार में कानूनी मामले (30 नवंबर, 2022)
4. सरकार में विधायी कार्य (01 दिसम्बर, 2022)
5. आचरण, अनुशासन और अपील नियम और विभागीय पूछताछ (02 दिसंबर, 2022)

अन्य गतिविधियाँ

1. पुस्तकालय : शाखा में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय है जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, इतिहास, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जीवनियां और सेवा तथा रक्षा कर्मियों द्वारा लिखित पुस्तकों सहित विभिन्न विषयों अथवा लोक प्रशासन पर 12000 पुस्तकें हैं।
2. स्वर्गीय श्री बी.जी. देशमुख वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2021-22 के पुरस्कारों का वितरण एवं वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित विषयों पर

वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया:

1. नेतृत्व और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका
2. महाराष्ट्र में शहरी प्रशासन में परिवर्तन और चुनौतियाँ
3. लोक प्रशासन में नवाचार हेतु स्वर्गीय डॉ. एस. एस. गडकरी स्मृति पुरस्कार-2021-22 का वितरण एवं वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित।

मिजोरम

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

‘भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है’
विषय पर राष्ट्रीय सह प्रस्तावना सम्मेलन (18 अक्टूबर, 2022)

व्याख्यान/बैठक/चर्चाएँ

‘रेस, स्पेस एंड द सिटी’ पर अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान/
बैठक (23 फरवरी, 2023)

पुस्तकें/रिपोर्ट/न्यूजलेटर्स

1. ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 : भारत में स्कूली शिक्षा पर परिप्रेक्ष्य; मिजोरम यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आइजोल : एमजेड्यू श्रीनिवासपति, जून, 2022
2. ‘नई विश्व ज्ञान व्यवस्था : उत्कृष्टता के लिए शाश्वत खोज; मिजोरम यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आइजोल: एमजेड्यू श्रीनिवासपति जून, 2022
3. ‘उच्चाधिकार प्राप्त समिति, लुंगलेई : इसकी शक्तियों और कार्यों का एक अध्ययन’ समकालीन सामाजिक वैज्ञानिक, (एक राष्ट्रीय संदर्भित जर्नल); प्रो. लालरेंटलुआंगाय; 2022
4. ‘1947 से मिजोरम में राजनीतिक विकास’ समकालीन सामाजिक वैज्ञानिक, (एक राष्ट्रीय संदर्भित जर्नल); प्रो. लालरेंटलुआंगाय; 2022

5. 'जल और स्वच्छता नीति: मिजोरम में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन; समकालीन सामाजिक वैज्ञानिक, (एक राष्ट्रीय संदर्भित जर्नल), लालनिहजोवीय 2022
6. वाश : लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण का मार्ग, समकालीन सामाजिक वैज्ञानिक, (एक राष्ट्रीय संदर्भित जर्नल); बेबी जोरिनपुरई हमार, लालनिहजोवी और लालथाजुअली; 2022
7. उत्तर-पूर्व भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए भारत नेट परियोजना का मूल्यांकन; तीसरी अवधारणा विचारों का एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल डॉ. टी. सदाशिवम और डॉ. शाहला तबस्सुम; 2023
8. डिजिटल इंडिया : लोगों के सशक्तिकरण की ओर एक यात्रा; इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस; डॉ. टी. सदाशिवम और डॉ. शाहला तबस्सुम; 2022
9. भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के जिलों में सतत विकास लक्ष्य : स्थानीयकरण की दिशा में एक अध्ययन; बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डॉ. टी. सदाशिवम और डॉ. शाहला तबस्सुम; 2022
10. भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना : रिश्वत देने वालों को दंडित करने के लिए कानून की जांच : बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (राष्ट्रीय), बाबूजी; 2022
11. असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन : जेनेसिस, सरकारी हस्तक्षेप और चुनौतियाँ; सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट जर्नल (इंटरनेशनल), सालेह अहमद और बाबूजी; 2022
12. राज्य प्रशासन और लोक सेवक की जिम्मेदारियाँ; मिजो कल्याण प्रशासन, बैंगलोर, कर्नाटक, पी.सी. लॉनकुंगा; (2022) समीक्षाधीन

अन्य

नई पुस्तकों, जर्नल्स और पत्रिकाओं को शामिल करके शाखा के पुस्तकालय का उन्नयन।

ओडिशा

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशाला

1. सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन-2022 (30 मार्च, 2022)
2. 'भारत में सिविल सेवा : आगे की राह' (21 अप्रैल, 2022)
3. मधुसूदन दास : आधुनिक ओडिशा के एक वास्तुकार (28 अप्रैल, 2022)
4. ओडिशा में बौद्ध विरासत (24 मई, 2022)
5. पोषित भारत : सशक्त भारत (06 जून, 2022)
6. आत्मज्ञान से आत्मबोधा तक (12 जुलाई, 2022)
7. वार्षिक थीम जर्नल विमोचन (17 जुलाई, 2022)
8. ओडिशा में सतत जनजातीय विकास (17 जुलाई, 2022)
9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता : लोकतंत्र की नींव (13 अगस्त, 2022)
10. मौलिक कर्तव्य : हमारे संविधान की रीढ़ (14 अगस्त, 2022)
11. भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर प्रस्तावना सम्मेलन (24 सितंबर, 2022)
12. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता : लोकतंत्र की नींव।
13. 'स्थायी समाज बनाने के लिए शांति, न्याय और मानवाधिकार' (05 नवंबर, 2022)
14. 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर वार्षिक निबंध प्रतियोगिता (14 नवंबर, 2022)
15. 'क्या भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता (03 दिसंबर, 2022)
16. नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत का स्वतंत्रता संग्राम (04 दिसंबर, 2022)
17. सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन-2023-ओडिशा के

माननीय राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। (04 दिसंबर, 2022)

अन्य गतिविधियाँ

1. पुस्तकालय उन्नयन एवं डिजिटलीकरण
2. आजीवन सदस्यता बढ़ाना
3. अनुसंधान परियोजना कार्य
4. विभिन्न प्रकाशनों पर चर्चा
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा

पंजाब और चंडीगढ़ (यू.टी)

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन

1. भा.लो.प्र.सं. के सदस्यों के 2022 के वार्षिक सम्मेलन के थीम पेपर पर प्रस्तावना सम्मेलन, जिसका शीर्षक है, 'भारत वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' (28 अक्टूबर, 2022)।
2. 'लोक प्रशासन के अनुशासन की स्थिति' विषय पर पैनल चर्चा (19 जनवरी, 2023)

राजस्थान

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर क्षेत्रीय संगोष्ठी (25 अक्टूबर, 2022)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएँ

1. सुशासन के व्यावहारिक आयाम (22 मई, 2022)
2. जवाहर लाल नेहरू : शासन और विकास में उनका योगदान (27 मई, 2022)
3. उपभोक्ता के अधिकार और उत्तरदायित्व (5 जून, 2022)
4. मानव संबंध प्रबंधन (12 जून, 2022)
5. भारत में महिला सशक्तिकरण (19 जून, 2022)
6. भारत में स्थानीय स्वशासन सुधार की दूसरी लहर अपरिहार्य (26 जून, 2022)

7. नौकरशाही के अध्ययन में मैक्स वेबर्स का योगदान (17 जुलाई, 2022)

8. सफल प्रशासक के गुण 925 जुलाई, 2022)
9. प्रभावी कार्यालय प्रबंधन (31 जुलाई, 2022)
10. महान नेताओं के जीवन के लिए सबक (7 अगस्त, 2022)
11. स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी (अगस्त 15, 2022)
12. भ्रष्टाचार उन्मूलन (3 सितंबर, 2022)
13. सफलता के खुले राज (18 सितंबर, 2022)
14. प्रशासन में निर्णय लेना (9 अक्टूबर, 2022)
15. मेरी आकांक्षाओं, मेरे संकल्प पर खुला विचार (18 दिसंबर, 2022)
16. सुशासन, सेवा तथा नागरिक (मार्च 15, 2023)

उत्तर प्रदेश

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. 'उत्तर प्रदेश में यातायात प्रबंधन एवं सड़क सुरक्षा' पर वेबिनार (2 अप्रैल, 2022)
2. सुशासन (क्या हम मुरझाने के लिए बाधय हैं?) (11 मई, 2022)

प्रकाशन

गतिशील समाचार पत्र (जनवरी-दिसंबर 2022)

अनुसंधान अध्ययन

प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में, बाराबंकी में शासन पर दस्तावेज।

अन्य गतिविधियाँ

कक्षा 9 से 12 के लिए (1) स्वच्छ भारत अभियान और (2) उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के पुनरुद्धार की आवश्यकता विषयों पर वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2022 आयोजित की गई थी।

स्थानीय शाखाएँ

बर्दवान

सेमिनार

1. 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर वेबिनार की प्रस्तावना (28 सितंबर, 2022)
2. महिला दिवस उत्सव - मानव तस्करी और बाल विवाह (09 मार्च, 2023)

व्याख्यान बैठक

संविधान दिवस के उपलक्ष्य में स्मारक व्याख्यान (26 नवंबर, 2022)

अन्य गतिविधियाँ

समय-समय पर अन्य संस्थानों/एजेंसियों के साथ छोटी-मोटी गतिविधियों में सहयोग करना।

कुड़डालोर

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएँ

कृषि सहित स्थानीय स्वशासन पर चर्चा (23 दिसंबर, 2022)

हावड़ा

सेमिनार/सम्मेलन

1. जल जमाव और उसके समाधान (13 जुलाई, 2022)
2. 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन (06 सितंबर, 2022)
3. साइबर अपराध और उसके सुरक्षा गार्ड (30 नवंबर, 2022)
4. कानून तोड़ने वालों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से विशेषाधिकार मिल रहा है (10 दिसंबर, 2022)
5. हावड़ा शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (29 मार्च, 2023)

पाट्येतर गतिविधियाँ

1. हावड़ा स्थानीय शाखा के सदस्यों ने वर्ष 2022-2023 की अवधि के दौरान हावड़ा, पश्चिम बंगाल के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों/संघों और राष्ट्रीय सेमिनारों में ऑनलाइन, वर्चुअल और ऑफलाइन भी सहभागिता की।
2. हावड़ा स्थानीय शाखा ने वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान हावड़ा जिला पुस्तकालय को कई पुस्तकें और जर्नल्स दान कीं, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों और शोध कार्यों के लिए हावड़ा स्थानीय शाखा के लिए अलग स्थान आरक्षित हैं।

जबलपुर

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

छात्रों के लिए शिक्षा प्रणाली (24 दिसंबर, 2022)

व्याख्यान/बैठक/चर्चाएँ

महिलाओं पर अत्याचार पर रोक (24 दिसंबर, 2022)

मदुरै

वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन

'वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे भारतीय' विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी (27 सितंबर, 2022)

पुदुचेरी

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशाला

1. कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा और यूपीएससी जागरूकता कार्यक्रम (02 अप्रैल, 2022)
2. सिविल सेवा दिवस 2022 - यूपीएससी जागरूकता कार्यक्रम (21 अप्रैल, 2022)
3. लोक प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम (28 मई, 2022)
4. 15वें वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा कार्यक्रम (27 अगस्त, 2022)

5. 'वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे भारतीय' विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी (17 सितंबर, 2022)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएँ

1. नई शिक्षा नीति (15 अगस्त, 2022)
2. नगर एवं देश नियोजन विभाग के लिए शहरी भूमि प्रबंधन और लोक प्रशासन (15 सितंबर, 2022)

संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. पुलिस विभाग के लिए पुलिस प्रशासन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 अक्टूबर, 2022)
2. आचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियर्स के संकाय सदस्यों के लिए यूपीएससी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम (20 अक्टूबर, 2022)
3. उच्च शिक्षा विभाग के लिए सुशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम (24 दिसंबर, 2022)
4. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रशासन प्रशिक्षण (04 मार्च, 2023)

तिरुपति

सेमिनार/वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. आंध्र प्रदेश में ग्रामीण पुनर्निर्माण पहल पर कार्यशाला (02 जून, 2022)
2. भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर प्रस्तावना सम्मेलन (25 अक्टूबर, 2022)
3. विश्व उपभोक्ता दिवस (15 मार्च, 2023)

व्याख्यान बैठक

1. आंध्र प्रदेश विकास में नवरत्नों के मूल्यांकन पर गोलमेज चर्चा (19 मई, 2022)
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर पत्रकारिता के प्रभाव पर व्याख्यान कार्यक्रम (06 सितंबर, 2022)

प्रकाशन

पुस्तक 'द डॉयन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन' का विमोचन डॉ. जी.एन. रेड्डी, 2 जून 2022।

तिरुपत्तूर

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. तिरुपत्तूर में पंचाल पंचायत में 200 पौधों लगाए (15 फरवरी, 2022)
2. होली क्रॉस आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज फॉर वुमेन, तिरुपत्तूर में विवाह पूर्व परामर्श (08 मार्च, 2023)
3. सेक्रेड हार्ट कॉलेज, तिरुपत्तूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (18 जून, 2022)
4. शेमफोर्ड "यूचरिस्टिक स्कूल, वानीबाडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2022)
5. स्कूली छात्राओं के लिए आत्महत्या रोकथाम और सामान्य स्वच्छता, मीनाक्षी सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल (27 जुलाई, 2022)
6. स्कूली छात्राओं के लिए आत्महत्या रोकथाम और सामान्य स्वच्छता, सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मदावलम (27 जुलाई, 2022)
7. भारत के वैश्विक नेता के रूप में उभरने पर प्रस्तावना सम्मेलन (26 सितंबर, 2022)

अन्य गतिविधियाँ

1. पुलिस कर्मियों हेतु कोविड-19 के लिए मास्क वितरण (10 जनवरी, 2022)
2. पर्यावरण एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा की गई (15 जनवरी, 2022)
3. तिरुपत्तूर में गरीब लोगों के लिए नेत्र शिविर जिला (20 फरवरी, 2022)

वडोदरा

सेमिनार

विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून, 2022) के दौरान 'स्थायी जीवन के लिए पारिस्थितिकी जागरूकता' पर संगोष्ठी

अन्य

वडोदरा शाखा के सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ शहर की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए कंबल और खाने हेतु तैयार (रेडी-टू-ईट) किट वितरित किए।

अनुलग्नक एफ.3.1

क्षेत्रीय एवं स्थानीय शाखाओं के अध्यक्ष एवं मानद सचिवों की सूची

कृपया विवरण निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त करें :

<https://www-iipa-org-in/cms/public/uploads/267841666002570-pdf>

अनुलग्नक एफ.3.2

दिनांक 31-03-2023 को क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाओं से जुड़े सदस्यों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्रीय शाखाएँ	स्थानीय शाखाएँ	सदस्य
1.	असम		201
2.	बिहार		554
3.		पाटलिपुत्र	37
4.		मुजफ्फरपुर	38
5.	दिल्ली		1898
6.	गोवा		45
7.	गुजरात		141
8.		वल्लभ विद्यानगर	37
9.		वडोदरा	46
10.	हरियाणा		242
11.	हिमाचल प्रदेश		94
12.	जम्मू एवं कश्मीर		367
13.	झारखंड		180
14.		जमशेदपुर	16
15.	कर्नाटक		314
16.		गुलबर्गा	41
17.		धारवाड़	25
18.		मैसूर	32
19.	केरल		216
20.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़सहित)		287
21.		जबलपुर	62
22.		इंदौर	40
23.	महाराष्ट्र		772
24.		औरंगाबाद	57
25.		नागपुर	93
26.		पुणे	162
27.		सांगली	18
28.		नासिक	20
29.	मिजोरम		79

क्र.सं.	क्षेत्रीय शाखाएँ	स्थानीय शाखाएँ	सदस्य
30.	मणिपुर		63
31.	मेघालय		77
32.	ओडिशा		271
33.		कटक	36
34.	पुडुचेरी		53
35.	पंजाब और चंडीगढ़		284
36.		पटियाला	37
37.	राजस्थान		333
38.		सिरोही	8
39.	तमिलनाडु		680
40.		कोयंबटूर	31
41.		डिंडीगुल	23
42.		मदुरै	117
43.		तिरुनेलवेली	21
44.		तिरुचिरापल्ली	25
45.		वेल्लोर	40
46.		विल्लुपुरम	20
47.		विरुद्धनगर	16
48.		सैदापेट	23
49.		सेलम	18
50.		तंजावुर	29
51.		कुड्डालोर	45
52.		तिरुपत्तूर	19
53.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश		531
54.		करीमनगर	30
55.		वारंगल	89
56.		तिरुपति	70
57.		विशाखापत्तनम	85
58.	उत्तर प्रदेश		854
59.		बदायूँ	101
60.		मेरठ	55
61.		आगरा	34
62.		कानपुर	73

क्र.सं.	क्षेत्रीय शाखाएँ	स्थानीय शाखाएँ	सदस्य
63.		बरेली	43
64.	उत्तराखंड		251
65.	पश्चिम बंगाल		346
66.		बर्दवान	19
67.		हावड़ा	20
68.	अन्य राज्य'		56
69.	विदेश'		119
			11159

अनुलग्नक एफ.4

शैक्षणिक केंद्र (2022-23)

शहरी अध्ययन केंद्र		उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	
1.	प्रो. के.के. पांडे-समन्वयक	1.	प्रो. सुरेश मिश्रा-समन्वयक
2.	डॉ. कुसुम लतां	2.	डॉ. सपना चड्ढा
3.	डॉ. सचिन चौधरी	3.	डॉ. ममता पठानिया
4.	डॉ. अमित कुमार सिंह		
आर्थिक विकास केंद्र और प्रबंधन अध्ययन केंद्र		जनजातीय अनुसंधान और अन्वेषण (सीओओआईआरईएक्स) केंद्र	
1.	प्रो. वी.एन. आलोक-समन्वयक	1.	प्रो. नूपुर तिवारी-समन्वयक
2.	डॉ. रोमा देबनाथ	2.	डॉ. साकेत बिहारी
3.	डॉ. पवन कुमार तनेजा	3.	डॉ. गदाधर महापात्र
डॉ. अम्बेडकर सार्वजनिक नीति और सामाजिक न्याय केंद्र		जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं सूखा प्रशासनकेंद्र	
1.	प्रो. नूपुर तिवारी-समन्वयक	1.	डॉ. श्यामली सिंह-समन्वयक
		2.	प्रो. वी.के. शर्मा
सुशासन केंद्र		ई-गवर्नेंस केंद्र	
1.	श्री अमिताभ रंजन-समन्वयक	1.	प्रो. चारु मल्होत्रा-समन्वयक
2.	श्री एच.सी. यादव	2.	डॉ. सुरभि पांडे
3.	श्री मिथुन बरुआ		
4.	सुश्री मेघना चुक्कथ		
अंतर्राष्ट्रीय संबंध केंद्र			
1.	प्रो. अशोक विशनदास-समन्वयक		
2.	डॉ. मनन द्विवेदी		

*केंद्रों का संविधान और सदस्यता केवल भा.लो.प्र.सं. की आंतरिक शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए है और प्रत्येक केंद्र और भा.लो.प्र.सं. वेतन संरचना के तहत अनुदान/संसाधनों से इसका कोई संबंध नहीं है।

अनुलग्नक एफ. 5

आईआईपीए संकाय और अन्य का शैक्षणिक योगदान प्रशिक्षण और अनुसंधान अध्ययन के अलावा

विनोद कुमार शर्मा

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

क. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

- I. शीर्षक : गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- II. अवधि : 3 वर्ष
- III. फंडिंग एजेंसी: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)
- IV. अनुदान: ₹.5,00,00,000/- (पांच करोड़)
- V. प्रारंभ करने की तिथि: जुलाई 2020
- VI. पूर्ण होने की तिथि: जून 2023
- VII. समापन की प्रस्तावित तिथि: जून 2023
- VIII. स्थिति (स्टेटस): जारी है

ख. प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

- I. शीर्षक: शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों के लिए पुस्तिका
- II. प्रकाशक: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक प्रशासन
- III. स्थान : नई दिल्ली
- IV. प्रकाशन की तिथि: 2022
- V. शीर्षक: शहरी स्थानीय निकाय अधिकारी हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका
- VI. प्रकाशक: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
- VII. स्थान : नई दिल्ली
- VIII. प्रकाशन की तिथि: 2022

(बी) कागजात और लेख

इस वर्ष के दौरान मैंने भा.लो.प्र.सं., एनआईडीएम,

एनडीएमए, राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित 18 वेबिनार में भाग लिया और वेबिनार के कई सत्रों की अध्यक्षता की।

(सी) कोई अन्य प्रकाशन

- I. वर्ष 2022 में पालगेव मैकमिलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन एशिया पैसिफिक' के संयुक्त संपादक (संपादक: हेलेन जेम्स; राजीव शॉय विनोद शर्मा और अन्ना लुकासलेविकज ने भी पुस्तक में तीन अध्यायों का भी योगदान दिया।

घ. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)-भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के परियोजना अन्वेषक
- समन्वयक, डीएसटी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण गतिविधियाँ

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

ड.. शाखाओं के साथ जुड़ाव

नियुक्त शाखा: महाराष्ट्र शाखा समन्वयक

च. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

1. इंटरनेशनल सोसायटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी के आजीवन सदस्य
2. सदस्य, जर्नल 'आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन' के सलाहकार बोर्ड, आईएसएसएन नंबर 2347-2553 एलबीएसएनएए, मसूरी।

3. सदस्य, संपादकीय टीम, आपदा प्रबंधन पर संसाधन पुस्तक, एलबीएसएनएए, मसूरी।
4. सदस्य, एलबीएसएनएए, मसूरी के पर्वतमाला कार्यक्रम
5. सदस्य, संपादकीय बोर्ड, एनआईयू इंटरनेशनल जर्नल ऑन ह्यूमन राइट्स।
6. सदस्य, संपादकीय बोर्ड जर्नल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट साइंस। आईएसएसएन: 0974-6382, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित।
7. सदस्य, व्यावसायिक विकास और सामाजिक-पर्यावरण प्रबंधन संस्थान (पीआरआईएसएम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की सलाहकार समिति
8. उपाध्यक्ष, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

के.के. पांडे

क. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

ख. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होती हैं)

I- शीर्षक:

- ए. एमएसएमई के लिए एक व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने पर अध्ययन
- बी. कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान के पुनर्गठन पर अध्ययन, जयपुर
- सी. राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश में जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम कॉरिडोर तक डीएमआरसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन
- डी. ग्राम खानपुर, नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन
- ई. पीएम स्वनिधि - इक्विटी और विकास के लिए एक मॉडल
- एफ. भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की पूर्व भूमिका

ग. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

I- शीर्षक:

- ए. अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए ताजपुर खुर्द गांव में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)
- बी. पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए सोनिया विहार में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)।
- सी. विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र और पंपिंग स्टेशन के निर्माण के लिए बख्तावर पुर गांव में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)
- डी. भा.लो.प्र.सं. द्वारा बीएफएआईआर कार्यक्रम का स्वतंत्र सत्यापन आयोजित करना

सीयूएस का समन्वय

- I. भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र से संबंधित विकास और नीति के प्रसार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय।
- II. समन्वय के हिस्से के रूप में समय-समय पर एमओएचयूए द्वारा अनुरोध किए जाने पर आवधिक रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट, संसद प्रश्न, कागजात, डेटाशीट और अन्य तकनीकी कागजात भी तैयार किए जाते हैं।
- III. संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई और अन्य आरसीयूईएस के साथ बातचीत की गई।

प्रकाशन

उच्च प्रतिष्ठा वाले समाचार पत्रों में छपी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ और लेख

- I. प्रमुख प्रकाशनों का शीर्षक
- ए. फास्टेस्ट मूवर इंडियन मेगासिटी-2021 में अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल: प्रक्रिया और सबक
- बी. शहरी मिशनों पर नागरलोक में नियमित कॉलम
- सी. भारत की संघीय संरचना स्थानीय सरकारों पर सीएलजीएफ जर्नल में पेपर: स्थिति और अवसर

डी. मोरबी से सीखें पर लेख: स्थानीय सरकार को ठीक करें

ई. पीएमस्वनिधि पर नीति समीक्षा लेख- इक्विटी और विकास के लिए एक मॉडल

एफ. संरचनात्मक सुधारों के लिए एमसीडी के एकीकरण पर लेख

II. जर्नल/समाचार पत्र:

ए. पुस्तक

बी. नागरलोक

सी. स्थानीय शासन का राष्ट्रमंडल जर्नल

डी. द टाइम्स ऑफ इंडिया

ई. आश्रय

एफ. अग्रणी

III. तारीख :

ए. अप्रैल, 2022

बी. अंक (अप्रैल-जून, 2022, जुलाई-सितंबर, 2022, अक्टूबर-दिसंबर, 2022 और जनवरी-मार्च, 2023)

सी. अंक 27 2022, 21 दिसंबर 2022

डी. 3 नवंबर, 2022

ई. वॉल्यूम. 23 नंबर 2, अक्टूबर, 2022

एफ. 10 मई, 2022

सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि में प्रस्तुत किए गये पेपर।

- भा.लो.प्र.सं. और आईएमपीआरआई, आईटीपीआई, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, एचएसएमआई, एएमडीए और एआईआईएलएसजी के भीतर विशिष्ट शहरी मुद्दों पर वेबिनार में मुख्य वक्ता
- आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के प्रमुख सचिवों की विशेष बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे और निवेश के मुख्य वक्ता (26 नवंबर, 2022)

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार

समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- (i) भा.लो.प्र.सं. में शहरी अध्ययन केंद्र का समन्वय
- (ii) भा.लो.प्र.सं. में राजभाषा समिति का समन्वय
- (iii) भा.लो.प्र.सं. में शहरी प्रवाह का समन्वय
- (iv) भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी समिति के सदस्य
- (v) भा.लो.प्र.सं. में अनुसंधान कर्मचारी के लिए चयन समिति के सदस्य
- (vi) संपादकीय बोर्ड नगरलोक के सदस्य

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव

(समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- (i) आईटीपीआई संपादकीय बोर्ड के सदस्य
- (ii) शहरी विकास पर आईटीपीआई विशेषज्ञ समिति के सदस्य
- (iii) डल और अन्य झीलों पर कर संबंधी विशेषज्ञ समिति के सदस्य
- (iv) एएमडीए (नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों का संघ) के सलाहकार बोर्ड के सदस्य
- (v) श्रीनगर महानगर क्षेत्र के विकास पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य (जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित)
- (vi) जम्मू महानगर क्षेत्र के विकास पर विशेषज्ञ समिति के सदस्य (जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित)
- (vii) एचएसएमआई (मानव निपटान और प्रबंधन संस्थान) के पुनर्गठन पर हुडको के कार्य समूह के सदस्य
- (viii) इग्नू के शहरी विकास पर कार्य समूह के सदस्य
- (ix) पर्यावास क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों के लिए हुडको पुरस्कारों की जूरी के सदस्य

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: पंजाब और चंडीगढ़

सुरेश मिश्रा

क. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

ए. व्याख्यान

क्रमांक	
1.	23 जून, 2022 को फिक्की, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 11वें एग्रोकैमिकल्स सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्रों में नकली उत्पादों के बारे में जागरूकता पर एक प्रस्तुति दी।
2.	दिनांक 17.09.2022 को गुरुदक्षता 5वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 'प्रोफेशनल विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया गया।
3.	21 सितंबर, 2022 को अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चेन्नई और सिटीजन कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप (सीएजी) द्वारा तमिलनाडु जिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए आयोजित ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यशाला में 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का विकास और अवलोकन' पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
4.	19 अक्टूबर, 2022 को सत्र ट्रेक- 1 मानविकी में डॉ. अम्बेडकर चेयर, अनामालिया विश्वविद्यालय, चिदम्बरम द्वारा 'उच्च शिक्षा में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी और उनके अनुप्रयोग' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उच्च शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक और सामाजिक संवर्धन विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
5.	20 अक्टूबर, 2022. को टीआरआई, उदयपुर के अनुसंधान विद्वानों और अनुसंधान कर्मियों के लिए राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित "अनुसंधान पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम" में "अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों का निर्माण, सर्वेक्षण आयोजित करना और रिपोर्ट लेखन" पर ऑनलाइन सत्र दिया।
6.	5 नवंबर, 2022 को एनएलआईयू भोपाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून: चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में विचार-मंथन पर तकनीकी सत्र में पैनेलिस्ट।
7.	यूजीसी- मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ऑनलाइन) में नवंबर 2022 को 'अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों का निर्माण, सर्वेक्षण आयोजित करना और रिपोर्ट लेखन' पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया। .
8.	16 नवंबर, 2022 को यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित 10वें संकाय प्रेरणा कार्यक्रम (ऑनलाइन) में 'शिक्षा और उपभोक्ता अधिकार' पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया।
9.	17 नवंबर, 2022 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'सतत जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में भारत में आदिवासियों के बीच जनजातीय स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल उपयोग पर एक सत्र की अध्यक्षता की।
10.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु द्वारा 19 नवंबर, 2022 को आयोजित उपभोक्ता संरक्षण के नए पहलू: चुनौतियां और आगे की राह पर अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप भारत में उपभोक्ता संरक्षण का आकलन' विषय पर मुख्य वक्ता।

11.	9 दिसंबर, 2022 को एओटीएस एलुमनी एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मुंबई द्वारा 'डिजिटलीकरण: चीजों को सरल बनाने का एक सरल तरीका' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में नागरिक केंद्रित प्रशासन: ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया गया।
12.	आर्ट्स कॉलेज पीजी और रिसर्च सेंटर ऑफ कॉमर्स, डिंडीगुल, तमिलनाडु में 26 नवंबर, 2022 को जी.टी.एन. आर्ट्स में उपभोक्तावाद: वाणिज्य अनुसंधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी में हालिया रूझान में अवसर और चुनौतियाँ विषय पर व्याख्यान दिया।
13.	लोक प्रशासन पर अभ्यास एआईआर
अन्य भा.लो.प्र.सं. पाठ्यक्रमों में लिए गए सत्र	
14.	प्रशासनिक सुधारों पर सत्र: 06 जनवरी, 2022 को वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए 20वें फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अवलोकन
15.	एनसीआर दिल्ली में 13, 14, 15 और 16 जून 2022 को राजस्व विभाग, सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही पर चार सत्र
16.	प्रशासनिक सतर्कता और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक नैतिकता, जवाबदेही और सुशासन पर सत्र, 12 सितंबर 2022
17.	18 अक्टूबर, 2022 को वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए 21वें फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुशासन और नागरिक अनुकूल प्रशासन पर सत्र
18.	13 जून, 2022 से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही पर सत्र
19.	14 जून, 2022 से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही पर सत्र
20.	15 जून, 2022 से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही पर सत्र
21.	17 जून, 2022 से भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राजस्व विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार) के राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए 'शासन में नैतिकता' पर एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रशासनिक नैतिकता और जवाबदेही पर सत्र

बी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

क्रमांक	शीर्षक	द्वारा प्रायोजित	अनुदान	स्थिति	पूर्ण या पूर्ण होने की तिथि
1.	जून 2022 तक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (परियोजना निदेशक)	उपभोक्ता मामले विभाग		पूर्ण हुई	जून 2022
2.	भारत में जिला स्तरीय शासन व्यवस्था के दस्तावेजीकरण पर परियोजना (परियोजना समन्वयक)	भा.लो.प्र.सं.			

प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

1. आत्मनिर्भर भारत: उभरते परिप्रेक्ष्य (संस्करण) सुरेश मिश्रा, श्यामली सिंह और पवन कुमार तनेजा द्वारा, प्रेस में, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2023। (प्रेस में)
2. मिशन कर्मयोगी: ट्रांसफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज, (संस्करण) प्रेस में सुरेश मिश्रा और अमित सिंह द्वारा, एलआईपीए, नई दिल्ली, 2023 द्वारा प्रकाशित। (आईएन प्रेस)

बी. कागज

1. शीर्षक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया गया पेपर
किरण गुप्ता, पार्थ प्रतिम मित्र, और प्रकाश शमा (एड) में वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उपभोक्ता कानून में उभरते रुझान, थॉमसन रॉयटर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। (प्रकाशन हेतु स्वीकृत)

(सी) सेमिनार सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पेपर

1. नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने क्या हासिल किया है? 5 और 6 नवंबर, 2022 को एनएलआईयू भोपाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून: चुनौतियां और अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में सुरेश मिश्रा और सपना चड्ढा द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन।
2. भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में 6-7 दिसंबर, 2022 को भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली सुरेश मिश्रा और ममता पठानिया द्वारा स्ट्रीट फूड विक्रेता: भारत में खाद्य सुरक्षा मानक और स्वच्छता व्यवहार पर व्याख्यान
3. दिल्ली में अनौपचारिक साप्ताहिक बाजार: सुरेश मिश्रा और सपना चड्ढा द्वारा भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन पर नेशनल कॉन्वेंट में उपभोक्ता खरीद व्यवहार का एक केस अध्ययन, 6-7 दिसंबर, 2022, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली

4. 1 मार्च, 2023 को डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज, आईयांगुडी, तमिलनाडु द्वारा आयोजित आईसीएसएसआर प्रायोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का पोषण विषय पर मुख्य भाषण दिया।
5. 4 नवंबर, 2022 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून: चुनौतियां और अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य भाषण देंगे।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

- (ए) समिति/अन्य (डिवीजन और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक कर्ता, संपादकीय, संयोजक कर्ता आदि)– विवरण और भागीदारी की प्रकृति

1. अध्यक्ष अनुसंधान कर्मचारी चयन समिति
2. सदस्य अप्पा नियंत्रण बोर्ड
3. सदस्य, अप्पा परीक्षा बोर्ड
4. महानिदेशक, भा.लो.प्र.सं. की अध्यक्षता में सदस्य अनुसंधान कर्मचारी चयन समिति
5. 5 दिसंबर, 2022 को भा.लो.प्र.सं. द्वारा आयोजित केस स्टडी कार्यशाला में भाग लिया

- (बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- सदस्य कोपोल्को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
- सदस्य, डॉक्टरल अनुसंधान समिति, लोक प्रशासन विभाग, इग्नू, नई दिल्ली
- दिनांक 01.12.2017 से दो वर्ष की अवधि हेतु आईएसएस विश्वविद्यालय, जयपुर के 'लोक प्रशासन' में अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। जुलाई 2021 से जून 2023।
- जर्नल ऑफ डॉ. अम्बेडकर चेयर, अन्नामई विश्वविद्यालय, चिदम्बरम के संपादकीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

- श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक, ओडिशा में सुशासन के क्षेत्र में बाहरी अनुसंधान परीक्षक के रूप में सूचीबद्ध

ज. शाखाओं के साथ जुड़ाव

- संकाय प्रभारी राजस्थान क्षेत्रीय शाखा

इ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

1. श्री करुणेश कुमार पांडे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज की पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए वीसी द्वारा परीक्षक नियुक्त किया गया।
2. मद्रुरै जिले में मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय से संबद्ध कला और विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों के कार्य जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षक नियुक्त, मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय, मद्रुरै
3. पीएचडी थीसिस 'टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यवहार-डिंडीगुल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन, मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय' का मूल्यांकन करने के लिए वीसी द्वारा नियुक्त परीक्षक
4. मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय, 'टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यवहार-डिंडीगुल जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक वाली पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए वीसी द्वारा नियुक्त परीक्षक
5. पीएचडी के मूल्यांकन के लिए वीसी द्वारा परीक्षक नियुक्त किया गया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शिप्टिंग पावर डायनेमिक्स शीर्षक वाली थीसिस: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
6. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के जिला चंबा (एच.पी.) की गद्दी जनजाति को विशेष प्राथमिकता के साथ हिमाचल प्रदेश में जनजातीय विकास कार्यक्रमों पर पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए वीसी द्वारा नियुक्त परीक्षक

7. पंडित प्रेम नाथ बजाज पर पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए वीसी द्वारा नियुक्त परीक्षक: राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण, इग्नू, नई दिल्ली
8. महिला कर्मचारियों की अपने संगठन के प्रति नैतिकता पर पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने के लिए वी.सी द्वारा नियुक्त परीक्षक- डिंडीगुल जिले में कपड़ा मिलों का विशेष संदर्भ, मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय
9. तमिलनाडु में ई-गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर थीसिस, मद्रुरै कामराज विश्वविद्यालय डी.लिट. का मूल्यांकन करने के लिए वी.सी द्वारा परीक्षक नियुक्त किया गया।
10. सत्ता परिवर्तन की गतिशीलता पर थीसिस: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ पर एम.फिल का मूल्यांकन करने के लिए वी.सी द्वारा परीक्षक नियुक्त किया गया। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इग्नू, नई दिल्ली

अन्य गतिविधियां

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग के गोपनीय कार्य संचालन हेतु आमंत्रित

अशोक विशनदास

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

बी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)
(वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होती हैं)

- I. शीर्षक: विभिन्न एमडीओ के एसओ/एएसओ के लिए आईएसटीएम द्वारा संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) का प्रभाव आकलन
- II. अवधि: 60 दिन
- III. फंडिंग एजेंसी: क्षमता निर्माण आयोग
- IV. अनुदान: रु.3 लाख

- V. प्रारंभ करने की तिथि: 25 नवंबर, 2022
- VI. पूर्ण होने की तिथि: 24 जनवरी, 2022
- VII. उद्देश्य: विभिन्न एमडीओ के एसओ/एसओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) के प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करना
- VIII. कार्यप्रणाली: व्यक्तिगत साक्षात्कार, एफजीडी और सांख्यिकीय तकनीकों का अनुप्रयोग
- IX. सारांश और निष्कर्ष: प्रशिक्षित अधिकारियों की दक्षताओं की उपयोगिता और प्रभाव के आधार पर दक्षता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी कुशल हो गए, भले ही उनकी योग्यताओं में अलग-अलग डिग्री हो।

सी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

- I. शीर्षक: उर्वरक विभाग की पारदर्शिता लेखापरीक्षा
- II. अवधि: 15 दिन
- III. फंडिंग एजेंसी: उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
- IV. अनुदान: रु.3.00 लाख
- V. प्रारंभ करने की तिथि: 16 अगस्त, 2022
- VI. पूर्ण होने की तिथि: 30 अगस्त, 2022
- VII. उद्देश्य: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत उर्वरक विभाग की पारदर्शिता लेखापरीक्षा करना
- VIII. कार्यप्रणाली: डेस्क टॉप अनुसंधान
- IX. सारांश और निष्कर्ष: उर्वरक विभाग द्वारा स्वेच्छा से खुलासे किये गये थे। हालाँकि, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर उर्वरक विभाग को अधिक सक्रिय खुलासे करने की सलाह दी गई थी।

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

- I. शीर्षक: मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की पारदर्शिता लेखापरीक्षा।
- II. अवधि: 15 दिन
- III. फंडिंग एजेंसी: मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई
- IV. अनुदान: रु. 2.40 लाख

- V. प्रारंभ करने की तिथि: 12 अक्टूबर, 2022
- VI. पूर्ण होने की तिथि: 26 अक्टूबर, 2022
- VII. समापन की प्रस्तावित तिथि 26 अक्टूबर, 2022
- VIII. स्थिति (स्टेटस): रिपोर्ट सौंपी गयी
- IX. उद्देश्य: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अनिवार्य पारदर्शिता लेखापरीक्षा करना।
- X. कार्यप्रणाली : डेस्कटॉप अनुसंधान
- XI. सारांश और निष्कर्ष : मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) द्वारा स्वेच्छा से खुलासे किए गए थे। हालाँकि, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर एमएफएल को अधिक सक्रिय खुलासे करने की सलाह दी गई थी।

ट. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों इत्यादि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन इत्यादि का शीर्षक: 'भारतीय कृषि में समसामयिक मुद्दे'। आधार व्याख्यान दिया।
- II. आयोजन एजेंसी: मिरांडा हाउस, नई दिल्ली
- III. स्थान और दिनांक: नई दिल्ली, जुलाई, 2022
- IV. फंडिंग एजेंसी: मिरांडा हाउस, नई दिल्ली
- V. अनुदान
- VI. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: 'भारतीय कृषि में समसामयिक मुद्दे' पर आधार व्याख्यान दिया।
प्रस्तुत पेपर : 'भारतीय कृषि में समसामयिक मुद्दे' पर आधार व्याख्यान दिया।

ट. (II) सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों इत्यादि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- I. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय,

संयोजक, इत्यादि)– भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

आईसीएसएसआर ने एक परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया

I. शाखाओं के साथ जुड़ाव

सौंपी गई शाखाएँ:

- (i) जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्रीय शाखा
- (ii) गुजरात क्षेत्रीय शाखा

ड.. भा.लो.प्र.सं. के बाहर लिए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- i. एम.फिल की ओर अग्रसर दो 48वें एपीपीए प्रतिभागियों को उनके शोध प्रबंध के लिए मार्गदर्शन किया।
- ii. मैंने भा.लो.प्र.सं. के संकाय और गैर-संकाय सदस्यों की फ्रैसिंग का संचालन किया।

ढ. किसी अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर शामिल नहीं है।

पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए यूजीसी द्वारा गठित एक समिति के अध्यक्ष थे

- i. दो 48वें अप्पा प्रतिभागियों को उनके शोध प्रबंध के लिए मार्गदर्शन किया, जिससे एम.फिल
- ii. फ्रैसिंग का कार्य किया गया
- iii. मिशन कर्मयोगी को संभाला और इस पर नोट्स तैयार किये
- iv. सचिव (कृषि) और सदस्य (नीति आयोग), नई दिल्ली द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया।
- v. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में बैठकों में भाग लिया।
- vi. नीति आयोग में बैठकों में भाग लिया।

वी. एन. आलोक

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजना

क्रमांक	नाम	द्वारा प्रायोजित	स्थिति
1.	सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग विकसित करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई को शक्तियों और संसाधनों के हस्तांतरण की स्थिति का क्षेत्र मूल्यांकन पर नीति अनुसंधान परियोजना	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	चल रहे

क्रमांक	नाम	द्वारा प्रायोजित	स्थिति
1.	भारत के सभी राज्यों में 'पंचायत चुनाव' पर नीति अनुसंधान परियोजना	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	मसौदा अंतिम रिपोर्ट अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत की गई
2.	भारत में चार राज्यों में 'पंचायत और विवाद समाधान' पर दूसरी नीति अनुसंधान परियोजना	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार	मसौदा अंतिम रिपोर्ट अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत की गई

प्रकाशन

संपादित पुस्तक में पेपर

- (2023) समीर कोचर में 'भारत में स्थानीय सरकारें: 2047 के लिए विजन' (संपादित) भारत 2047 : इक्विटी के साथ उच्च आय। ओक ब्रिज. प्रकाशन, आईएसबीएन 978-93-95764-36-0.

टीवी चैनलों (चयनित) पर आमंत्रित व्याख्यान/प्रस्तुति/पैनलिस्ट:

- 1 मार्च, 2023 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणाओं के बाद मंथन में 'संपत्ति कर सुधार' पर एक प्रस्तुति दी। सेमिनार में लगभग 30 डोमेन विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया।
- 7 फरवरी, 2023. आईएमपीआरआई इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा 'शहर और केंद्रीय बजट 2023-24' पर आयोजित एक पैनल चर्चा में वर्चुअल मोड में एक प्रस्तुति दी।
- 4 जनवरी 2023 को आईएसबी, हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) और भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित चार दिवसीय (3-6 जनवरी) 'सार्वजनिक नीति संवाद-अनुसंधान और प्रैक्टिस को पाटना' के तहत 'राजकोषीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन' पर एक विशेषज्ञ पैनल में एक प्रस्तुति दी। सह-पैनलिस्ट डॉ. जी नरेंद्र कुमार, प्रोफेसर श्रीनिवास चारी और डॉ. देवर्पिता रॉय थे। संचालक श्री एस. एन. त्रिपाठी थे।
- 6-9 दिसंबर 2022, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली। हैन्स सीडेल फाउंडेशन, जर्मनी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा द्वारा 'संकट के समय में संघवाद' विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 'राजकोषीय संघवाद और एकजुटता' पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। जिसमें तीन देशों के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने पेपर प्रस्तुत किये। दूसरे दिन 'आपदा प्रबंधन में स्थानीय सरकारों की भूमिका' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 29-30 नवंबर, 2022 एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) द्वारा आयोजित एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राज्य वित्त आयोगों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के कई सत्रों में प्रस्तुतिकरण दिया।
- 25 नवंबर, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में। समापन सत्र का संचालन किया जिसमें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बिबेक देबरॉय वक्ता थे। यह उस परामर्श के तहत था जिसे प्रजा फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) ने 'शहरी सरकारों के वित्तीय सशक्तिकरण' पर 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 31 शहरों में आयोजित किया था।
- 29 अक्टूबर, 2022 चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों के लिए दो दिवसीय (29-30 अक्टूबर) ओरिएंटेशन कार्यक्रम में ए) 'पार्षद की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और कर्तव्य' और बी) 'जनता और सरकारों के साथ पार्षद की सहभागिता' पर बातचीत की गई। कार्यक्रम का आयोजन निगम एवं रामभाऊ म्हेगीप्रबोधिनी ने किया।
- 16 अक्टूबर 2022 हंसराज कॉलेज, दिल्ली। हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद द्वारा आयोजित भारत की ज्ञान परंपरा में सामाजिक विज्ञान पर दो दिवसीय (15-16 अक्टूबर) 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सामाजिक विज्ञान - पूर्वव्यापी और संभावनाएं' विषय पर एक पैनल चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में प्रस्तुति दी। श्री मुकुल कानेटकर, प्रोफेसर सुनील चौधरी और प्रोफेसर रघुनंदन शर्मा सह-पैनलिस्ट थे।
- 13 सितंबर 2022 एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) द्वारा आयोजित और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित

‘ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्वयं के स्रोत’ पर दो दिवसीय (13-14 सितंबर) राष्ट्रीय कार्यशाला में एक तकनीकी सत्र का संचालन किया गया।

- 29 अगस्त, 2022 को स्टेट कन्वेंशन सेंटर, शिलांग में नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के सहयोग से ‘मेघालय में स्वायत्त जिला परिषदों के वित्त और वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करना’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय राज्य सम्मेलन में आधार व्याख्यान दिया।
- 22 अगस्त, 2022 त्रिची में 27-31 जनवरी, 2023 के दौरान निर्धारित XLVI भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस के एक भाग के रूप में भारतीदासन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित ‘राजकोषीय संघवाद: ‘सिद्धांत और रुझान’ पर प्री कांग्रेस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया। भारतीदासन विश्वविद्यालय ने कुलपति कार्यक्रम का संचालन किया।
- 23 जून, 2022 को टीआरसी हॉल, राज बाग, श्रीनगर में आवासन और शहरी विकास विभाग, नागरिक सचिवालय, जम्मू-कश्मीर और प्रजा फाउंडेशन की यूटी द्वारा आयोजित श्रीनगर नगर निगम को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने पर मेयर, डिप्टी मेयर और सभी कॉर्पोरेट सदस्यों द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में विशेषज्ञ विचार प्रस्तुत किए गए।
- 5 जून, 2022 को नई दिल्ली में (ऑनलाइन) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ‘पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग’ पर सर्टिफिकेट कोर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक समूह को ए) पब्लिक फाइनेंस और बी) फिस्कल फेडरलिज्म पर वार्ता दी गई।
- 1-3 जून, 2022 को पोखरा, नेपाल में संस्थान की अनुमति से नेपाल का दौरा किया और जर्मनी के हैन्स सेडेल फाउंडेशन द्वारा आयोजित दक्षिण/

दक्षिणपूर्व एशियाई देशों को कवर करने वाले एशिया संघवाद सम्मेलन में ‘संघों में अंतर सरकारी संबंध’ पर एक प्रस्तुति दी।

- 26 मई, 2022 (ऑनलाइन), जमीनी स्तर पर भागीदारी और स्थानीय विकास पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में ‘राजस्व जुटाना और स्थानीय आर्थिक विकास पर एक सत्र का संचालन: केरल (भारत) में ‘पीपुल्स प्लान अभियान’ और ‘बाथो पेले पहल’ से सीख दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर रूरल मैनेजमेंट (सीआरएम), केरल, द घाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (जीआईएमपीए), घाना और द नेशनल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट (एनएसजी), दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित किया गया।
- 24 मई, 2022 को भा.लो.प्र.सं. में, ग्रासरूट्स रिसर्च एवं एडवोकेसी मूवमेंट (जीआरएएम) और भा.लो.प्र.सं. द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ‘3पीई-सार्वजनिक नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन, 23 मई से 4 जून, 2022’ कार्यशाला में केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन द्वारा ‘भारत का बजट बनाना’ विषय पर एक सत्र का संचालन किया गया।
- 14 अप्रैल, 2022 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘प्रतिष्ठित सप्ताह’ के भाग के रूप में ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व में वृद्धि पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व को बढ़ाने की दिशा में राज्य अधिनियमों/नियमों की स्थिति’ पर प्रस्तुति दी गई।

अन्य शैक्षणिक कार्यों से जुड़ाव

इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखों की समीक्षा।

समन्वयक, आर्थिक विकास और प्रबंधन केंद्र

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल, 2022 के आदेश संख्या एम-11015/116/2022-एफडी

द्वारा गठित 'पंचायतों को 16वें वित्त आयोग अनुदान' पर टास्क फोर्स के सदस्य।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या एम-11015/449/2020-एफडी दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा सदस्य, ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

भा.लो.प्र.सं. शाखा के साथ जुड़ाव

उत्तराखंड

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स के लेखों की समीक्षाएँ

भारत में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए पेपर सेटर

भारत में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए परीक्षक

चारु मल्होत्रा

क. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुबंध एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

ख. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ

ए) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है)

चालू/पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ

(01)

शीर्षक: इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीटी अकादमियों की स्थापना के लिए सहायता योजना का प्रभाव आकलन

अवधि: 13 महीने (लगभग)

फंडिंग एजेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय (MeitY)

प्रारंभ करने की तिथि : दिनांक 10.03.2022

समापन: दिनांक 31.03.2023

शीर्षक: जिला सशासन सूचकांक (डीजीजीआई-यूपी)

फंडिंग एजेंसी: भा.लो.प्र.सं. और डीएआरपीजी

प्रारंभ करने की तिथि: दिनांक 03.03.2022

समापन की तिथि: चल रही है

शीर्षक: प्रौद्योगिकी अंतर विश्लेषण

अवधि: 5 महीने 19 दिन

फंडिंग एजेंसी: ट्राईड

प्रारंभ करने की तिथि : दिनांक 13.10.2022

पूर्ण करने की तिथि : दिनांक 31.13.2023

ग. प्रकाशन

पुस्तकें

1. भा.लो.प्र.सं. में पुस्तक लॉन्च का एक विशेष कार्यक्रम माननीय केंद्रीय मंत्री और अध्यक्ष भा.लो. प्र.सं. इसी डॉ. जितेंद्र सिंह ने 29 अप्रैल, 2022 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) द्वारा की गई 'एसएपी का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन: नवाचार ईंधन विकास' रिपोर्ट जारी की।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए डिजिटल स्वच्छता (उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए श्रेणी) की बुनियादी बातों पर एक पुस्तिका।

घ. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (वित्तीय प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकत्व संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

1. संपादकीय समिति (भा.लो.प्र.सं.)
2. भा.लो.प्र.सं. पूर्व छात्र संघ

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

क्रमांक	सदस्यता संगठन का नाम	समिति/परियोजना का नाम
1.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार (जीओआई)	जनता के लिए आईटी कार्यक्रम 'साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम'
2.	सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रमुख योगदानकर्ता, यंग लीडर्स नेबरहुड- प्रथम (वाईएलएनएफ) प्रशिक्षण
3.	राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान-एनआईसीएफ (दूरसंचार विभाग)	सदस्य, स्क्रीनिंग समिति
4.	इग्नू	विशेषज्ञ, ओपेन दूरी के लिए एमओओसी/स्वयं पाठ्यक्रमों के विकास पर समिति
5.	यू.जी.सी	साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ समिति
6.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जूरी सदस्य, 'डिजिटल पावरग्रिड-2025' प्रतियोगिता
7.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार (डीएआरपीजी)	सदस्य, ई-गवर्नेंस केस-स्टडी समिति
8.	ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन,	एआई, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस स्टीयरिंग कमेटी के संयोजक

ड.. शाखाओं के साथ जुड़ाव

सौंपी गई शाखा: पुडुचेरी

च. किए गए किसी भी अन्य शैक्षणिक या संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर शामिल नहीं है।

- सरकार में जूरी सदस्य 'कनेक्ट 8वें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2022'
- ईपीएफओ द्वारा दिनांक 08-09-2022 को आयोजित 'चिंतन शिविर' के लिए नीति विशेषज्ञ।
- वर्चुअल प्रेजेंटेशन में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्पेशल इंटररेस्ट ग्रुप वन- गवर्नेंस (सीएसआईएसआईजीआईओवी) का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विशेषज्ञ सदस्य।

- 'बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स, 2022' में शॉर्टलिस्ट किया गया।

- 'डिजिटल पावरग्रिड-2025 प्रतियोगिता' में प्राप्त लगभग 230 प्रविष्टियों का मूल्यांकन
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण एसोसिएशन लुधियाना: लुधियाना एसोसिएशन ने 'कैसे साइबर सुरक्षित रहें और वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों के लिए डिजिटल स्वच्छता और साइबर सुरक्षा की मूल बातें' विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया।

नूपुर तिवारी

- शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

समाजिक न्याय में डॉ. अम्बेडकर पीठ (चेयर) की गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	अवधि	गतिविधि का संक्षिप्त विवरण
1.	‘भारत में राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली में बदलते रुझान’ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान	14 -15 मार्च, 2023	डॉ. अंबेडकर चेयर इन सोशल जस्टिस, भा.लो. प्र.सं., नई दिल्ली ने सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और भारतीय राजनीति विज्ञान एसोसिएशन के सहयोग से 14-15 मार्च, 2023 को ‘भारत में राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली में बदलते रुझान’ विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्देश्य भारत की राजनीतिक प्रणाली में विभिन्न गेम-चेंजर रुझानों पर चर्चा करना था। सेमिनार की शुरुआत डॉ. अंबेडकर चेयर, सामाजिक न्याय, भा.लो.प्र.सं. की प्रमुख प्रो. नूपुर तिवारी के स्वागत भाषण से हुई। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, डॉ. सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, महानिदेशक, भा.लो. प्र.सं. नई दिल्ली, प्रो. धनंजय सिंह, सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर, नई दिल्ली, प्रो. संजीव शर्मा, महासचिव, भारतीय राजनीति विज्ञान संघ, डॉ. जिया लाल, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, और डॉ. स्वदेश सिंह, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। लगभग 100 प्रतिभागियों ने पेपर प्रस्तुत किया और सेमिनार में भाग लिया।
2.	डॉ. अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान	13 अप्रैल, 2023	डॉ. अंबेडकर सामाजिक न्याय पीठ, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) ने 13 अप्रैल, 2023 को ‘डॉ. अम्बेडकर का संविधान और बदलती सामाजिक गतिशीलता’ विषय पर डॉ. अंबेडकर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार, ने व्याख्यान दिया। एफआईएमटी, नई दिल्ली के विद्यार्थियों ने डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर से पहले एफआईएमटी की थिएटर सोसायटी ‘जहानत’ द्वारा नाटक का प्रदर्शन किया। स्मृति व्याख्यान में लगभग 70-80 व्यक्तियों ने भाग लिया।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	अवधि	गतिविधि का संक्षिप्त विवरण
3.	समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास और शिक्षाशास्त्र पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिप्रेक्ष्य)	20 अप्रैल, 2023	कापसहेड़ा, नई दिल्ली में 20 अप्रैल, 2023 को फेयरीलड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास और शिक्षाशास्त्र (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिप्रेक्ष्य) पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन समारोह के साथ हुई। जिसके बाद गणमान्य व्यक्ति प्रो. (डॉ.) एस.सी. रैना, प्रो. (डॉ.) क्वीनी प्रधान, प्रो. (डॉ.) नूपुर तिवारी और श्री अमिताभ रंजन को प्रो. (डॉ.) सरोज व्यास और प्रो. (डॉ.) श्वेता गगनेजा, और प्रो. (डॉ.) एम. अफजल वानी द्वारा सम्मानित किया गया।
4.	एक दिवसीय 'राष्ट्रीय एससी, एसटी महिला उद्यमी सम्मेलन'	06 मई, 2023	डॉ. अंबेडकर चेयर इन सोशल जस्टिस, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने 06 मई, 2023 को आईसीसीएसटीडब्ल्यू, एमएसएमई, नीति आयोग के सहयोग से उद्यमिता विकास गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए 'राष्ट्रीय एससी, एसटी महिला उद्यमी कॉन्क्लेव' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते, भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री, भारत सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में देशभर से लगभग 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
5.	'हाशिए पर मौजूद समुदायों का समावेशी विकास : सामाजिक विचारकों, लेखकों और नेताओं की नजर से' विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन	8-9 जून, 2023	

48वें अप्पा प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिया (2022-2023)

- क) समावेश, समानता एवं विविधता और अपनापन
- ख) समावेशी शासन के माध्यम से समावेशी विकास
- ग) समानता, सामाजिक समावेशन और लैंगिक नारीवाद

- घ) लैंगिक संवेदीकरण और समानता के उपाय
- ङ) लैंगिक रिस्पॉन्सिव बजटिंग के माध्यम से समावेशन
- च) समावेशन की निर्भरता सिंड्रोम- पंचायत में महिलाएं 'कांच की छत से कांच की चट्टान तक'
- छ) भारत में जनजातियों का बहिष्कार और समावेशन

- ज) जनजातीय विकास के लिए समावेशी शासन
 झ) समावेशी विकास और जनजातीय विकास में तेजी लाना
 ज) विविधता और समावेशन: कुछ सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस

व्याख्यान

2. एससी, एसटी और महिला उद्यमियों के लिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4 तथा 5 मई, 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय उद्यमिता शिखर सम्मेलन में भाषण दिया।
3. 20 अप्रैल, 2023 को समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकास और शिक्षाशास्त्र (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिप्रेक्ष्य) पर एफआईएमटी, गुरुग्राम में एक विशेष व्याख्यान दिया।
4. एसजेईटीए-टीआरआई अरुणाचल प्रदेश, डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज (डीएनजीसी) आरजीएनटीयू विभाग द्वारा 22 नवंबर 2022 को आयोजित मानसिक स्वास्थ्य और आदिवासियों में मदद मांगने वाले व्यवहार पर एक व्याख्यान दिया।
5. राष्ट्रीय परामर्श नामक कार्यक्रम में 7-8 जुलाई, 2022 को 'एफआरए 2006 पर टीआरआई के कार्यान्वयन की भूमिका' पर एक व्याख्यान दिया। जनजातीय विकास के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम की संभावनाएं: कार्यान्वयन अंतराल और आगे का रास्ता भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से एससी एसटी आरटीआई, ओडिशा और यूएनडीपी द्वारा आयोजित किया गया
6. यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा 05 जुलाई, 2022 को आयोजित 09वें एक माह के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के सम्मानित अतिथि की हैसियत से समापन भाषण दिया।
7. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) के तहत नए पैनल में शामिल 'कानूनी सलाहकार' (लास) और 'फील्ड लेवल काउंसल' (एफएलसी) के लिए 13 और 14 मई, 2022 को भा.लो.प्र.सं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय शाखा परिसर, जम्मू में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रेरण कार्यशाला में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पर व्याख्यान दिया।
8. भा.लो.प्र.सं. जेएंडके क्षेत्रीय शाखा द्वारा 26 मार्च, 2022 को आयोजित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर संवेदीकरण कार्यशाला में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर व्याख्यान दिया गया।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 15 और 16 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय संवाद में संचालित और अध्यक्षता वाले सत्र: जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया।
10. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 08 मार्च, 2022 को सीजीएसटी दिल्ली जोन के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित किया।
11. 'राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन' 62वां एनडीसी पाठ्यक्रम पर पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) में एक व्याख्यान दिया।

ए (iii) अन्य कार्य

- क) नेशनल डीडी न्यूज द्वारा 07 फरवरी, 2023 को आयोजित अमृत काल बजट पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- ख) आदि-महोत्सव: आदि विरासत की 16 फरवरी, 2023 को भव्य प्रस्तुति पर भाषण दिया गया और समाचार फीचर में प्रदर्शित किया गया।
- ग) राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 (24 अप्रैल, 2023) पर संसद टीवी पर आयोजित विषय: स्वामित्व योजना विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।

बी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

क्र.सं.	विवरण
1.	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र को स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन
2.	अनुसूचित जनजाति घटक के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचे का विकास
3.	नीतिगत निर्णय लेने के लिए जनजातीय अनुसंधान संग्रह
4.	शोध पत्रों का संग्रह टीआरआई, सीओई और अन्य संगठन
5.	जनजातीय विकास के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण ढांचे का विकास
6.	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जनजातीय अनुसंधान संस्थान परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन
7.	आदि-समाचार (आदिवासी अनुसंधान पर मासिक समाचार पत्र का प्रारूपण और उत्पादन
8.	एसटी विद्वानों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण।
9.	नीति पृष्ठभूमि पेपर की तैयारी और राष्ट्रीय जनजातीय नीति का तुलनात्मक विश्लेषण (पुराना मसौदा बनाम प्रस्तावित)
10.	एसटी मानव विकास रिपोर्ट 2022 का आलोचनात्मक विश्लेषण
11.	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एसईसीएमओएल को स्वीकृत परियोजना पर तीसरे पक्ष का मूल्यांकन और व्यापक रिपोर्ट तैयार करना
12.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सुदृढीकरण और पुनरुद्धार पर एक अध्ययन
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह-आवास के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जनजातियों के लिए विशेष वैकल्पिक कार्य योजना तैयार करना।

डी. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

- क) पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर एक अध्ययन: सार्वजनिक वस्तुओं की भागीदारी और वितरण की गुणवत्ता।
- ख) बहुआयामी गरीबी का एक अध्ययन: अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की स्थिति
- ग) छत्तीसगढ़ के अबूझ मारिया: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर एक अध्ययन

ई. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

एफ. केस स्टडीज तैयार

- क) बर्फ के स्तूपों के माध्यम से परित्यक्त गाँव का पुनर्वास (जून, 2022 जनजातीय कार्य मंत्रालय, एसईसीएमओएल-सीओई)
- ख) हिमालयन फार्म स्टे की स्थापना और युवा प्रवासन को रोकने के लिए इसकी क्षमता पर शोध करना- जुलाई, 2023 जनजातीय कार्य मंत्रालय एसईसीएमओएल-सीओई
- ग) निष्क्रिय सौर तापित इमारतों को मुख्य धारा में लाना- सितंबर 2023, जनजातीय कार्य मंत्रालय एसईसीएमओएल-सीओई

जी. प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज शीर्षक
1.	नीतिगत निर्णय लेने के लिए जनजातीय अनुसंधान संग्रह
2.	मध्य प्रदेश के एसटी पीआरआई सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर रिपोर्ट

3.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर प्रशिक्षकों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट
4.	राष्ट्रीय जनजातीय प्रतिभा पूल कॉन्क्लेव पर रिपोर्ट
5.	सभी टीआरआई के साथ दो दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन कार्यशाला पर रिपोर्ट
6.	जनजातीय क्षेत्रों में जीपीडीपी की तैयारी पर ग्राम पंचायतों के दो दिवसीय क्षमता निर्माण पर रिपोर्ट
7.	मासिक ई-न्यूजलेटर का पहला संस्करण- आदि-समाचार
8.	उत्कृष्टता केंद्र के लिए एमओटीए द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्यांकन पर अंतरिम रिपोर्ट
10.	विकेंद्रीकरण, जनजातीय स्थानीय स्वशासन और इसके निहितार्थों पर अनुभवों पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर सार-पुस्तक
11.	विकेंद्रीकरण, जनजातीय स्थानीय स्वशासन और इसके निहितार्थों पर अनुभवों पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर रिपोर्ट
12.	सिक्किम में एफआरए 2006 के संचालन पर रिपोर्ट
13.	अनुसंधान पद्धति पर क्षमता निर्माण कार्यशाला पर रिपोर्ट
14.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एफआरए 2006 पर अभिविन्यास पर एक रिपोर्ट
15.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के साथ माननीय एमटीए की बातचीत पर रिपोर्ट
16.	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत जनजातीय अनुसंधान संस्थान परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन पर रिपोर्ट
17.	वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उत्कृष्टता केंद्र परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन पर रिपोर्ट
18.	फलता की कहानियों की पहचान- एनएफएसटी विद्वान
19.	‘आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनाने के सिद्धांत और सिफारिशें’ पर दो दिवसीय कार्यशाला पर रिपोर्ट
20.	सीओई: एसईसीएमओएल की मंत्रालय-अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यापक रिपोर्ट
21.	वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एनटीआरआई वार्षिक प्रगति रिपोर्ट
22.	जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के पुनरुद्धार और सुदृढीकरण पर अध्ययन पर रिपोर्ट
23.	एनटीआरआई में जन-जातीय गौरव दिवस समारोह 2022 पर रिपोर्ट
24.	टीआरआई उदयपुर के अनुसंधान विद्वानों और अनुसंधान अधिकारियों के लिए अनुसंधान पद्धति पर रिपोर्ट
25.	सतत जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर रिपोर्ट
26.	भगवान बिरसा मुंडा स्मृति व्याख्यान पर रिपोर्ट
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह- जारावास के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जनजातियों के लिए विशेष वैकल्पिक कार्य योजना की तैयारी पर प्रगति रिपोर्ट।

ई. प्रकाशन

ए. आगे प्रकाशित होने वाली पुस्तकें

शीर्षक	प्रकाशक	स्थान	प्रकाशन की तिथि
सतत जनजातीय विकास के लिए जनजातीय स्थानीय स्वशासन पर दोबारा गौर करना	कॉन्सेप्ट प्रकाशन	दिल्ली	आगामी-प्रकाशित होना
भारत में विभिन्न दृष्टियों से जनजातियों को समझना	कनिष्क प्रकाशन वितरक	दिल्ली	आगामी-प्रकाशित होना

एफ. कोई अन्य प्रकाशन

भारत सरकार के लिए रिपोर्ट

जी. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर

1. राष्ट्रीय परामर्श नामक कार्यक्रम में 7-8 जुलाई, 2022 को 'एफआरए 2006 पर टीआरआई के कार्यान्वयन की भूमिका' पर एक पेपर प्रस्तुत किया। एससी एसटी आरटीआई, ओडिशा और जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से यूएनडीपी द्वारा आयोजित जनजातीय विकास के संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम की संभावनाएं: कार्यान्वयन अंतराल और आगे का रास्ता।
2. भा.लो.प्र.सं. जम्मू-कश्मीर क्षेत्रीय शाखा परिसर, जम्मू में 13 और 14 मई, 2022 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) के तहत नए सूचीबद्ध 'कानूनी सलाहकार' (लास) और 'फील्ड स्तर परामर्शदाता' (एफएलसी) के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण सह प्रेरण कार्यशाला में नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संरक्षण पर एक पेपर प्रस्तुत किया गया।
3. भा.लो.प्र.सं. जम्मू व कश्मीर क्षेत्रीय शाखा द्वारा 26 मार्च 2022 को आयोजित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर संवेदीकरण कार्यशाला में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर एक पेपर प्रस्तुत किया।
4. 15 एवं 16 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित

जनजाति आयोग द्वारा आयोजित जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल और अनुसूचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के मूल्यांकन राष्ट्रीय डायलॉग संवाद में एक पेपर प्रस्तुत किया गया।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (डिवीजन और योजना और सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक जहाज, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

1. चयन वर्ष 2019-20, 2020-2021, 2021-22 और 2022-23 के लिए एसटी उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) के पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए चयन समिति के सदस्य।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

1. एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एआईपीपी), एमिटी यूनिवर्सिटी के एरिया सलाहकार बोर्ड (एएबी) और अध्ययन बोर्ड (बीओएस) के विशेषज्ञ सदस्य।
2. संपादकीय बोर्ड के सदस्य- जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस
3. मानद संपादक - नीति संवाद (पीयर समीक्षित)

जे. शाखाओं के साथ जुड़ाव शाखा को सौंपा गया: भा.लो.प्र.सं. बिहार शाखा गतिविधियों के साथ जुड़ाव:

1. प्रशिक्षण

II. अनुसंधान/केस का अध्ययन

III. सेमीनार/सम्मेलन

कुसुम लता

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

बी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होती हैं)

सी. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

I. शीर्षक: कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और मूल्यांकन के कार्य करना।

II. अवधि: चौबीस महीने

III. फंडिंग एजेंसी: न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

IV. अनुदान: रु. 39,90,000- (कर सहित)

V. प्रारंभ होने की तिथि: 2 नवंबर, 2021

VI. पूरा होने की तिथि:

VII. पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि: अक्टूबर, 2023

VIII. स्थिति: जारी है

I. शीर्षक: 14 टियर- II शहरों (गाजियाबाद) में महिला सुरक्षा ऑडिट

II. अवधि: 12 महीने

III. फंडिंग एजेंसी: एनसीडब्ल्यू

IV. अनुदान: रु. 23.43 लाख

V. प्रारंभ की तिथि: 11 अगस्त, 2022

VI. पूरा होने की तिथि :

VII. पूरा होने की प्रस्तावित तिथि :

VIII. स्थिति: जारी है

डी. प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

(बी) कागजात और लेख : शहरी मुद्दों पर नगरलोक में नियमित कॉलम का योगदान (अप्रैल-जून, 2022, जुलाई-सितंबर, 2022, नगरलोक 2022 के अंक 2, और 3)

1) 'भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन' (अक्टूबर-दिसंबर 2022, नगरलोक 2022 के अंक 4) पर एक लेख लिखने में योगदान दिया

2) नगरलोक जर्नल में कॉलम के लिए नीचे दिए गए लेखों में योगदान दिया गया:

- अंक 2 में 'भारत में पारगमन उन्मुख विकास' अप्रैल से जून 2022.

- अंक 3 में 'चांदनी चौक, शाहजहानाबाद, दिल्ली का पुनर्विकास' अगस्त से सितंबर 2022.

3) 66वें सदस्यों के वार्षिक सम्मेलन 2022 में 'भारत: एक वैश्विक नेता के रूप में उभरता हुआ' विषय पर डीआरबी प्रस्तावना सम्मेलन में 'आयुर्वेद में भारत एक वैश्विक नेता' विषय पर पेपर प्रस्तुत किया।

4) 'भारत में लोग केंद्रित शहरी प्रशासन' पर सीयूएस टीम द्वारा 6-7 दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समानांतर सत्र IV-बी में 'शहरी योजना और भूमि प्रबंधन' शीर्षक से 'दिल्ली की शहरी और क्षेत्रीय योजना' पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

5) 22 मार्च, 2022 को 22-24 मार्च, 2023 के दौरान एनआईयू के सहयोग से सीयूएस द्वारा आयोजित 'नगरपालिका सेवाओं के लिए यू-20 एजेंडा' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में 'G-20' पर एक प्रस्तुति दी।

6) 22-24 मार्च 2023 के दौरान 24 मार्च, 2022 को एनआईयू के सहयोग से सीयूएस द्वारा आयोजित 'नगरपालिका सेवाओं के लिए यू-20 एजेंडा' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के 'पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहार' पर तकनीकी सत्र 8 में 'रणनीतिक पर्यावरण योजना' पर एक प्रस्तुति दी।

(सी) कोई अन्य प्रकाशन

(डी) पुस्तक समीक्षाएँ

ई. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- प्राइड प्लाजा, नई दिल्ली में जीआईजेड द्वारा 26-27 सितंबर, 2022 को आयोजित 'शहरी क्षेत्रों में जलवायु गतिविधियों को मुख्यधारा में लाना-शहरों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना' विषय पर कार्यशाला में भाग लिया।

- सेंटर फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, जीएनडीयू, अमृतसर और केएसएस-आईएसपीईआर, पंचकुला द्वारा 3 अक्टूबर, 2022 को विश्व पर्यावास दिवस 2022 का जश्न मनाने के लिए 'माइंड द गैप' नो वन एंड प्लेस लेफ्ट बिहाइंड' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।

सेंटर फार सस्टेनेबल हैबिटेट, जीएनडीयू, अमृतसर और केएसएस-आईएसपीईआर, पंचकुला द्वारा 3 अक्टूबर, 2022 को विश्व पर्यावास दिवस 2022 का आयोजन किया गया।

- 5 दिसंबर, 2022 को भा.लो.प्र.सं. द्वारा 'शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस विधि' पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- 15-16 दिसंबर, 2022 के दौरान 16 दिसंबर, 2022 को डॉ. नीतू जैन, भा.लो.प्र.सं. द्वारा 'रिपोजिशनिंग इंडिया @2047: राष्ट्र निर्माण के लिए एसडीजी का पुनरावलोकन' पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मेलन में 'पी.के. उमाशंकर मेमोरियल थीम पर व्याख्यान: उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा' विषय पर के टैक 4 में 'लचीला बुनियादी ढांचा' राष्ट्रीय निर्माण के लिए पूर्व-आवश्यकता' शीर्षक से एक पेपर प्रस्तुत किया। आयोजित किया गया।
- 31 जनवरी 2023 को विज्ञान भवन में एनसीडब्ल्यू के 31वें स्थापना दिवस में भाग लिया।
- 13-14 मार्च 2023 को एमओएचयूए के सहयोग से एनआईयूए द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय युवा सम्मेलन' में भाग लिया।

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 11 मार्च, 2023 को आईटीपीआई के दिल्ली क्षेत्रीय चैप्टर द्वारा आयोजित वेबिनार 'शहरों में महिलाओं की सुरक्षा' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।

एफ. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

ख आईआईपीए में सीनियर रिसर्च स्टॉफ के चयन के लिए डीजी सर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सदस्य

- नगरलोक अंक 2, 3 और 2023 का 2022 (प्रकाशित) अंक 1 के 4 के संयुक्त संपादक।
- समय-समय पर एमओएचयूए के अनुरोध के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट, संसद प्रश्नों के उत्तर और डेटाशीट तैयार करने में योगदान दिया।
- 48वें अप्पा में 'विजन इंडिया @2047: गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा' स्ट्रीम का आयोजन किया गया।
- 7-12 अक्टूबर, 2022 के दौरान 48वें अप्पा के 38 प्रतिभागियों की चंडीगढ़ आईसीसीसी, देहरादून शहर की यात्रा का आयोजन किया गया।
- 48वें अप्पा के आठ प्रतिभागियों की सिक्किम की फॉरवर्ड एरिया दौरा आयोजित किया गया।
- 14-19 नवंबर, 2022 के दौरान विशाखापट्टनम जिले के दकामरी ग्राम पंचायत में 19 प्रतिभागियों की नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम और ग्रामीण अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

जे. शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा के गठन की दिशा में काम किया।

के. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- यूएनओएसएसएससी, यूएनडीआरआर जीईटीआई, पीएचओ, डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित 'जटिल जोखिम प्रबंधन और लचीले शहरी भविष्य में परिवर्तन: दक्षिण को दोहन-दक्षिण सहयोग का लाभ उठाना और कोविड-19 सीखना' पर 23 अगस्त-13 सितंबर 2022 तक एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा किया।
- 5 सितंबर, 2022 को प्रस्तुत आईटीपीआई की एसोसिएटशिप परीक्षा के पुरस्कार के लिए यूपी के गाजीपुर के लिए सिटी एसडब्ल्यूएम पर उनकी थीसिस के लिए श्री स्कंद कुमार, पंजीकरण संख्या 1605/18 का मार्गदर्शन किया गया।
- 5 और 8 दिसंबर, 2022 को आईटीपीआई की एसोसिएटशिप परीक्षा के तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 'इंफास्ट्रक्चर के लिए योजना' पर छह सत्र लिए गए।
- आठवें सेमेस्टर, बी. प्लानिंग, एसपीए के श्री जलज राणा को 21 फरवरी से 2 जून, 2023 तक 'एनसीटी ऑफ दिल्ली में योजनाबद्ध और अनियोजित क्षेत्र में जल सेवा वितरण' शीर्षक वाली थीसिस के लिए मार्गदर्शन किया गया।
- कॉन्स्ट्रक्शंस क्लब ऑफ इंडिया, रफी मार्ग में 28 मार्च, 2023 को नेचर केयर इनिशिएटिव द्वारा आयोजित 'जल और जीवन' शिखर सम्मेलन पर राष्ट्रीय बहु-हितधारक संवाद (एनएमएसडी) के दूसरे तकनीकी सत्र में 'जीवन के लिए प्रकृति आधारित समाधान' पर एक व्याख्यान दिया।

सचिन चौधरी

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी ए) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है)

- I. शीर्षक: कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान, जयपुर के पुनर्गठन पर अध्ययन
- II. अवधि: मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियों के बाद 1 महीना
- III. फंडिंग एजेंसी: केवीआईसी, मुंबई
- IV. प्रारंभ की तिथि: 12 दिसंबर, 2022 को ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रस्तुति
- V. समापन की तिथि: दिसंबर, 2022

सी. चल रही अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी बी)

- I. शीर्षक: पंजाब का स्वतंत्र सत्यापन: राजकोषीय और संस्थागत लचीलापन परियोजना का निर्माण
- II. अवधि: 5 वर्ष
- III. फंडिंग एजेंसी: पंजाब सरकार
- IV. प्रारंभ करने की तिथि: मार्च, 2023
- V. पूर्ण होने की तिथि: मार्च, 2028
- VI. समापन की प्रस्तावित तिथि : मार्च, 2028
- VII. स्थिति: जारी है

डी. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- II. आयोजन एजेंसी: सीयूएस, आईआईपीए
- III. स्थान एवं दिनांक: नई दिल्ली (6-7 दिसंबर, 2022)
- IV. फंडिंग एजेंसी: सीयूएस
- V. अनुदान: एमओएच एवं यूए
- VI. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: पीएमस्वनिधि: एक मूल्यांकन

ई. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार

समिति, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि की सदस्यता)

- भागीदारी का विवरण और प्रखरति।

अनुसंधान कर्मचारी हेतु चयन समिति के सदस्य (बी)भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

एफ. शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: मणिपुर क्षेत्रीय शाखा

आई. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- सार्वजनिक नीति पेपर के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली में अतिथि संकाय।
- इग्नू के लिए इकाई लेखन।
- कई लोक सेवा आयोगों में लोक प्रशासन विशेषज्ञ।

नीतू जैन

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ

- I. शीर्षक : सीएपीएफ में दुर्घटना और आत्महत्या के मामलों का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय
- II. अवधि : 14 महीने
- III. फंडिंग एजेंसी : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
- IV. अनुदान : रु. 18,937,230
- V. प्रारंभ होने की तिथि : 25 अगस्त, 2020
- VI. पूर्ण होने की तिथि : अक्टूबर, 2021
- VII. स्थिति : पूर्ण । प्रस्तुति के कई दौर दिए गए। अध्ययन को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एमएचए में 2 नवंबर, 2022 को आयोजित बैठक में पुलिस अनुसंधान संबंधी स्थायी समिति द्वारा स्वीकार किया गया था।

VIII. शीर्षक : 'एनबीसीएफडीसी की योजनाओं का मूल्यांकन'

IX. अवधि : 3 महीने

X. फंडिंग एजेंसी : एनबीसीएफडीसी

XI. अनुदान : रु.35,0000/-

XII. प्रारंभ की तिथि : अगस्त, 2021

XIII. पूर्ण होने की तिथि : मई, 2022

XIV. स्थिति : पूर्ण

कागजात और लेख

1. त्रिपाठी, एस.एन. और जैन, नीतू, सह-संपादित पुस्तक 'ड्राइवर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत', नवंबर, 2022, भा.लो.प्र.सं. प्रकाशन, आईएसबीएन. 978-81-9555533- 4-1 माननीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा जारी की गई।
2. जैन, नीतू और शौरन, भारती, कर्मचारियों की भूमिका तनाव और भूमिका प्रभावकारिता पर मार्गदर्शन का प्रभाव, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एचआरडी एंड मैनेजमेंट (स्कोपस इंडेक्सड और एबीडीसी-सी श्रेणी)*, वॉल्यूम -22, नंबर 3-4, अगस्त 2022.
3. जैन, नीतू, डॉ. अम्बेडकर और राष्ट्र निर्माण पर उनकी विरासत, *एनआईयू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स* (एक यूजीसी सूचीबद्ध जर्नल है), वॉल्यूम में प्रकाशित. 9, सितम्बर, 2022, पीपी. 135-139.
4. जैन, नीतू और शर्मा, पूजा, भारतीय समाज के प्रति डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का योगदान। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च* में प्रकाशित, खंड-8, अंक-1, जनवरी 2023, पीपी-536-540.
5. जैन, नीतू और शर्मा, तनुष्का, विविधता, समानता और समावेशन: संगठनों में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित *'रेसिलिएंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज*

इन टर्बुलेंट मैनेजमेंट टाइम्स' नामक पुस्तक में प्रकाशित. 2022, आईएसबीएन नंबर 978-81-955661-2-9, पीपी. 73-76.

6. जैन, नीतू और शर्मा, तनुष्का, डॉ. बी.आर. का पुनरावलोकन समावेशी शिक्षा पर अम्बेडकर का दर्शन, आईपीईएम जर्नल फॉर इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, खंड 7, जुलाई 2022 में प्रकाशित।
7. जैन, नीतू और शर्मा, तनुष्का, कोविड-19 आपदा : कार्यस्थल में बढ़ती लैंगिक असमानता, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसायटी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'रेसिलिएंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज इन टर्बुलेंट मैनेजमेंट टाइम्स' में प्रकाशित। 2022, आईएसबीएन नंबर 978-81-955661-2-9, पीपी. 93-96.
8. जैन, नीतू और शौरन, भारती, प्रतिभा को प्रेरित करने, विकसित करने और बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण, एमएस राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वॉल्यूम 57, नंबर 1 (1), 2023, (यूजीसी केयर ग्रुप-1 जर्नल).
9. जैन, नीतू और शौरन, भारती, प्रशिक्षुओं के सीखने पर नियंत्रण के स्थान (लोकस) का प्रभाव, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वॉल्यूम 17, क्रमांक 1, जनवरी-मार्च, 2023 (यूजीसी केयर ग्रुप-1 जर्नल).
10. जैन, नीतू और शौरन, भारती, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और शासन, मध्य प्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 28, क्रमांक 1, 2023 (यूजीसी केयर ग्रुप-1 जर्नल).
11. शौरन, भारती और जैन, नीतू, नौकर नेतृत्व (सर्वेंट लीडरशिप) : नई व्यावसायिक योग्यता : साउथ इंडिया जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम XX, नंबर -2, 2023 (यूजीसी केयर ग्रुप -1 जर्नल).
12. जैन, नीतू और शर्मा, तनुष्का, आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी-विरोधी नेतृत्व शैली, आत्मनिर्भर भारत के चालक, नवंबर, आईआईपीए प्रकाशन, 2022, पीपी. 45-52.

13. शौरन, भारती और जैन, नीतू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एचआर लीडरशिप की भूमिका, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'रेसिलिएंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज इन टर्बुलेंट मैनेजमेंट टाइम्स' में प्रकाशित, 2022, आईएसबीएन नंबर 978-81-955661-2-9, पीपी. 93-96.
14. जैन, नीतू और सिंह, कन्हैया, भारत में समावेशी विकास का बदला हुआ परिप्रेक्ष्य : आत्मनिर्भरता की ओर एक मिशन, ड्राइवर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, नवंबर, 2022, पीपी 226-240.

सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

1. साईबालाजी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज द्वारा 21 जनवरी, 2023 को आयोजित व्यवधान के युग में स्थिरता और नवाचार की भूमिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'विविधता और समावेशी प्रैक्टिसेस के प्रति डॉ. अंबेडकर के योगदान' पर एक पेपर प्रस्तुत किया।
2. नैक (एनएएसी) और एरियल यूनिवर्सिटी, इजराइल के सहयोग से आईपीईएम, गाजियाबाद द्वारा 25 मार्च, 2023 को आयोजित 'एजुकेशन जेनरेशन नेक्स्ट : रिवाइमिंग हायर एजुकेशन सिस्टम-विजन, इनसाइट्स एंड इंप्लीकेशंस' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इक्विटी, समानता और शिक्षा की पहुंच' पर पेपर प्रस्तुत किया गया।
3. आईसीएसएसआर और आईआईपीए द्वारा 9 फरवरी, 2023 को आयोजित 'पचहत्तर पर भारत की कूटनीति' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत के लिए डॉ. अंबेडकर जैसे कर्मयोगियों का निर्माण @ 2047' विषय पर पेपर प्रस्तुत किया गया।
4. आईपीईएम, गाजियाबाद द्वारा एनएएसी और एरियल यूनिवर्सिटी, इजराइल के सहयोग से 25 मार्च 2023 को आयोजित 'एजुकेशन जेनरेशन नेक्स्ट : रिवाइमिंग हायर एजुकेशन सिस्टम-विजन, इनसाइट्स एंड इंप्लीकेशंस' पर एक अंतर्राष्ट्रीय

सम्मेलन में 'सहिष्णु, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज बनाना : अंबेडकर मार्ग' पर पेपर प्रस्तुत किया गया।

5. आईसीएफआई विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा 24 मार्च, 2023 को आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'कर्मचारियों की कार्य व्यस्तता बढ़ाने में मार्गदर्शन की भूमिका' पर पेपर प्रस्तुत किया गया।
6. आईसीएफआई विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा 24 मार्च, 2023 को आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार : पूर्ववृत्त और परिणाम' पर पेपर प्रस्तुत किया गया।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि) - भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

1. बीएचयू, वाराणसी में 22 अप्रैल, 2022 को आयोजित एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में माननीय मंत्री और राज्यपाल, यूपी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक कार्य योजना (2022-2023)** का चयन किया गया।
2. तनाव प्रबंधन पर पाठ्यक्रम मिशन कर्मयोगी के आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। यह आईजीओटी.12500 लोगों पर शीर्ष तीन पाठ्यक्रमों (450 पाठ्यक्रमों में से) में से एक है। इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया है। लगभग 9500 प्रतिभागियों ने यह पाठ्यक्रम पूरा किया है। इसे 1600 प्रतिभागियों से समीक्षाएँ प्राप्त हुईं, जिनकी रेटिंग 5 में से 4.6 थी।
3. 15 से 16 दिसंबर, 2022 तक 'रिपोजिशनिंग इंडिया@2047 : रिविजिटिंग एसडीजी फॉर

नेशन बिल्डिंग' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संयोजक। 5 अलग-अलग ट्रैक और मेमोरियल व्याख्यानों में लगभग 58 पेपर प्रस्तुत किए गए।

4. 'ट्राइवर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत' पर पुस्तक पढ़ी, जो 16 दिसंबर, 2023 को जारी की गई थी।
5. 'समकालीन भारत में कानूनी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकास और शिक्षाशास्त्र' और विभिन्न गतिविधियों पर संयुक्त रूप से एक दिवसीय **राष्ट्रीय सम्मेलन** आयोजित करने के लिए फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
6. आईआईपीए में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धानखड़ से संयुक्त रूप से '**शैक्षणिक उत्कृष्टता-2022**' का पुरस्कार प्राप्त किया।
7. इंटरनेशनल रिसर्च एसोसिएशन, लंदन द्वारा '**इंडियन वूमेन अचीवर अवार्ड 2022**' प्राप्त हुआ।
8. केस अध्ययन केंद्र के संकाय प्रभारी
9. भा.लो.प्र.सं. में आयोजित केस स्टडी प्रतियोगिता के सदस्य सचिव
10. भा.लो.प्र.सं. में सामाजिक न्याय में डॉ. अम्बेडकर पीठ के संकाय प्रभारी।
11. 26 नवंबर, 2022 को 'राष्ट्रीय संविधान दिवस' मनाया जाएगा
12. नशामुक्त भारत अभियानका 4 अगस्त, 2022 को आयोजन किया गया।
13. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा 2022 में प्रायोजित '**सीएपीएफ में संघर्षण और आत्महत्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय**' शीर्षक वाली परियोजना के परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला गया। महानिदेशक (बीपीआर

एंड डी) ने कार्यान्वयन के लिए एक नीति के रूप में सभी केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस आयुक्तों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के महानिदेशकों, सीएपीएफ के महानिदेशकों को रिपोर्ट प्रसारित की।

14. **सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय** (आईसीएसएसआर प्रायोजित) के सहयोग से 14-16 मार्च, 2023 तक 'भारत में राजनीतिक दलों और पार्टी प्रणाली में बदलते रुझान' पर **तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी** आयोजित करने के लिए समन्वय किया गया।

(बी)भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- सदस्य, शैक्षिक और कौशल विकास सेवा अनुभागीय समिति, भारतीय मानक ब्यूरो
- राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क के आजीवन सदस्य
- आईएसएबीएस के एसोसिएट सदस्य

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई : हरियाणा और गोवा

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- मेरे जीवन की उपलब्धियों हेतु संसद टीवी पर प्रदर्शित।
- अगस्त, 2022 में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में **फिल्म निर्माताओं के एक सत्र की अध्यक्षता** की।
- मई, 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग की जूरी
- कुछ अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के पेपर समीक्षक।

व्याख्यान के लिए एनएसीआईएन, एनएडीटी, एनआईसीएफ और किरोड़ीमल कॉलेज द्वारा आमंत्रित।

साकेत बिहारी

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

बी. पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

- शीर्षक: राष्ट्रीय स्तर की निगरानी
- अवधि: 30 दिन
- फंडिंग एजेंसी: एनएलएम प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय
- प्रारंभ की तिथि: फरवरी, 2023
- समापन की तिथि: मार्च, 2023
- उद्देश्य : ग्रामीण विकास योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया का आकलन करना
- कार्यप्रणाली: प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया। अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करके आयोजित किया गया था।

डी. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

- 1: शीर्षक : आरा और पटना शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन योजना
- अवधि: 24 महीने
- फंडिंग एजेंसी: बीएसडीएमए, पटना
- प्रारंभ की तिथि: सितंबर, 2021
- समापन की प्रस्तावित तिथि : 23 सितंबर, 2023
- स्थिति: योजना प्रस्तुत की और समीक्षा, जारी
1. I. शीर्षक : ग्रामीण विकास विभाग में विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों द्वारा सलाहकार नियुक्ति के मामले की जांच करना।
- अवधि: 75 दिन
- फंडिंग एजेंसी: ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार
- प्रारंभ की तिथि: 27 मई, 2023
- समापन की प्रस्तावित तिथि: 8 अगस्त, 2023.
- स्थिति: डेटा संग्रहण का कार्य जारी है

ई. प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

- I. शीर्षक: भारत रत्न : राजेन्द्र प्रसाद के प्रेरक कार्य
- II. प्रकाशक: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
- III. स्थान: दिल्ली
- IV. प्रकाशन की तिथि: 2023

(बी) कागजात और लेख

- I. शीर्षक: भारत में सांस्कृतिक राजधानी और स्कूल की सफलता
- II. जर्नल: बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
- III. वॉल्यूम: XIX
- IV. नंबर: 2
- V. दिनांक: जुलाई-दिसंबर, 2022

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

- (ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि) – भागीदारी का विवरण और प्रकृति। संपादक : (1) लोक प्रशासन, (2) सदस्य संपादकीय बोर्ड : लोक प्रशासन में दस्तावेजीकरण, आईआईपीए, नई दिल्ली
- (बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता) : नहीं

जे. शाखाओं के साथ जुड़ाव

सौंपी गई शाखा : झारखंड

के. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

पीएच.डी. थीसिस का मूल्यांकन किया, कुमाऊं विश्वविद्यालय, स्लीपी हॉलो, नैनीताल-263001, उत्तराखंड

एल. किसी भी अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर नहीं दिया गया है।

48वें अप्पा कार्यक्रम के तहत दो एम.फिल शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण किया।

रोमा देबनाथ

ए. शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित) चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

- I. शीर्षक: खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) इकाइयों/संस्थानों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन और केवीआई क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों/संस्थानों द्वारा उत्पन्न उत्पादन, बिक्री और रोजगार का अनुमान
- II. शीर्षक: गाजियाबाद में महिला सुरक्षा ऑडिट
अवधि: 1 वर्ष
फंडिंग एजेंसी: राष्ट्रीय महिला परिषद
- III. शीर्षक: न्याय विभाग के अंतर्गत कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई); 2021-2023
अवधि: दो वर्ष
फंडिंग एजेंसी: कानून और न्याय मंत्रालय विभाग का न्याय
कार्यप्रणाली: परिवर्तन का सिद्धांत बनाना

बी. प्रकाशन

(सी) कागजात और लेख

- देबनाथ, एम. रोमा और ढींगरा, ए., (2022), 'स्वास्थ्य क्षेत्र और विशाल डेटा का अनुप्रयोग : भारत का एक केस स्टडी'। अर्थशास्त्र और प्रबंधन की यूरोपीय समीक्षा, वॉल्यूम 6, नंबर 1, 45-65, <http://10.29015/cerem.923>, ISSN: ISSN 2543-9472; eISSN 2544-0365. ISSN 2543-9472 eISSN2544-0365

VI. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक :

- आईआईपीए में 'भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है' शीर्षक से वार्षिक सम्मेलन पत्र प्रस्तुत किया।

डी. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

- I. समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।
 - भा.लो.प्र.सं. 2047 विजन समिति के सदस्य
- II. भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)
 - प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षकों का बोर्ड

ई. शाखाओं के साथ जुड़ाव

साँपी गई शाखा: पश्चिम बंगाल और मेघालय गतिविधियों में भागीदारी :

- I. प्रशिक्षण:
- II. अनुसंधान/केस अध्ययन: हाँ
- III. सेमिनार/सम्मेलन: हाँ

एफ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

1. डाक विभाग द्वारा इंडिया विजन 2047 के लिए संयुक्त कार्य समूह के सदस्य

2. डीएमईओ विशेषज्ञ समूह के सदस्य
3. ओल्ड गोवा स्थित जीआईपीएआरडी, इल्ला फार्म में 10 से 20 जनवरी, 2023 तक गोवा सरकार के योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय (डीपीएसई), के समूह ए और समूह बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम' को संबोधित करने के लिए जीआईपीएआरडी द्वारा आमंत्रित किया गया।
4. एनएसएसटीए, ग्रेटर नोएडा में 01 मार्च से 16 मार्च, 2023 के दौरान आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान देने के लिए एनएसएसटीए द्वारा आमंत्रित किया गया।
5. एनआईसीएफ द्वारा आयोजित सेमिनार में अतिथि संकाय। दिनांक 19.12.2022 को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार' पर सभा को संबोधित किया।
6. प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षकों का बोर्ड, 29 मार्च, 2023।

सपना चड़्डा

(i) अनुसंधान

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी ए)

(वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है)

क्रमांक	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूर्ण/चल रहा है
1.	एमएसएमई (विकास) अधिनियम, 2006 में बदलाव की आवश्यकता का अध्ययन करना और एमएसएमई के लिए एक व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करना	एमएसएमई	पूर्ण
2.	आईआईएसईआर कोलकाता द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट 2021-22	आईआईएसईआर कोलकाता	पूर्ण
3.	कानूनी मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट 2021-22	कानूनी कार्य विभाग, भारत सरकार	पूर्ण
4.	आयकर अपील न्यायाधिकरण द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट, 2021-22	आयकर अपील न्यायाधिकरण	पूर्ण

5.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट 2021-22	एमजीएचवी, वर्धा	पूर्ण
6.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट 2021-22	गृह मंत्रालय, भारत सरकार	पूर्ण
7.	जनकपुरी पश्चिम से राहत गंज/आराम गंज रोशनआरा रोड, पुल बंगश आर.के. आश्रम कॉरिडोर तक डीएमआरसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	पूर्ण
8.	ग्राम खानपुर में डीएमआरसी परियोजना एयरो-सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर चरण-IV के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	पूर्ण
9.	आईएसटीएम 2021-22 द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट	आईएसटीएम	पूर्ण
10.	वीपी कार्यालय द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष ऑडिट 2021-22	वीपी कार्यालय	पूर्ण

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी बी)

क्रमांक	शीर्षक	द्वारा प्रायोजित	अनुदान	स्थिति	पूर्ण होने की तारीख
1.	राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार		पूर्ण	जून, 2022

चल रही अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी ए)

क्रमांक	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूर्ण/चल रहा है
1.	पुलिस स्टेशन सोनिया विहार, दिल्ली के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	चल रहे
2.	विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र और पंपिंग स्टेशन (एसटीपी) के निर्माण के लिए बख्तावर पुर गांव में राजस्व संपदा में भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	चल रहे
3.	अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) के निर्माण के लिए ग्राम ताजपुर खुर्द की राजस्व संपदा में भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	चल रहे

4.	भारत में घर खरीदने वालों पर रियल एस्टेट नियामक अधिनियम की प्रभावशीलता का एक प्रभाव आकलन अध्ययन	आईसीएसएसआर	चल रहे
5.	राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए गाजियाबाद शहर का महिला सुरक्षा ऑडिट	राष्ट्रीय महिला आयोग	चल रहे
6.	दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम परियोजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और मूल्यांकन।	न्याय विभाग भारत सरकार	चल रहे

अनुसंधान मार्गदर्शन

क्रमांक	नमांकितों की संख्या	प्रस्तुत थीसिस	उपाधि प्रदान की गई
1.	श्री मनीष कुमार अग्रवाल रोल नंबर 4802	भारतीय दूरसंचार क्षेत्र - भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार नियम, 2016 का आकलन	
2.	सुश्री जूलिया महापात्र रोल नंबर 4823	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : क्या अब सुधार का समय आ गया है?	

क्षमता निर्माण पहल (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन) (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लेखित)

प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

उत्तर पूर्व भारत में उपभोक्ता संरक्षण-मुद्दे और चुनौतियाँ- (सं.) जी.पी. प्रसीन, सुरेश मिश्रा और सपना चड्ढा (प्रिंट में)

(बी) कागजात/लेख/पुस्तक में अध्याय

- के.के. पांडे, कुसुम लता, सचिन चौधरी और अमित कुमार सिंह (एड) पीपल सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया, आईआईपीए नई दिल्ली (प्रकाशन के लिए स्वीकृत) में सपना चड्ढा और सुरेश मिश्रा “ दिल्ली में अनौपचारिक साप्ताहिक बाजार-उपभोक्ताओं के खरीदारी व्यवहार का एक अध्ययन ”
- सपना चड्ढा और अमित कुमार सिंह, आवास क्षेत्र में विवाद समाधान तंत्र - नागरलोक में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभाव का एक अध्ययन (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)।

3. सपना चड्ढा और ईशा कौशल ‘ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों की भूमिका - एक आकलन ’ में नीतू जैन (संस्करण) ‘ रिपोजिशनिंग इंडिया@2047: रिविजिटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर नेशन बिल्डिंग ’ (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)।

4. प्रस्तुत अध्याय जिसका शीर्षक है ‘ उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद दायित्व व्यवस्था : हालिया विकास, किरण गुप्ता, पार्थप्रतिम मित्र, और प्रकाश शमा (एड) उपभोक्ता कानून में उभरते रुझान, थॉमसन रॉयटर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)।

5. सपना चड्ढा, सतत उपभोग-उपभोक्ता वकालत समूह न्यूजलेटर में उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी की खोज, वॉल्यूम 1, अंक 4, 2022 पृष्ठ 4 पर.

(सी) सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रस्तुत पेपर - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019-मुद्दों और चिंताओं पर 30 मई, 2022 को एसजीटी

यूनिवर्सिटी और कंज्यूमर वॉयस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक आकलन।

2. हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन, गुजरात और उपभोक्ता एडवांकेसी समूह द्वारा 29 अगस्त, 2022 को उपभोक्ता जागरूकता और संरक्षण में प्रतिमान बदलाव पर राष्ट्रीय वेबिनार में ई कॉमर्स और उपभोक्ता संरक्षण पर प्रस्तुति।
3. एनएलआईयू भोपाल द्वारा 4-5 नवंबर, 2022 को उपभोक्ता संरक्षण कानून : चुनौतियां और अवसर पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रभाव-एक आकलन पर पेपर प्रस्तुत किया गया।
4. 6-7 दिसंबर, 2022 को भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रोफेसर सुरेश मिश्रा के साथ 'दिल्ली में अनौपचारिक साप्ताहिक बाजार - उपभोक्ताओं के खरीद व्यवहार का एक अध्ययन' पर पेपर प्रस्तुत किया।
5. 6-7 दिसंबर, 2022 को भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. अमित कुमार सिंह के साथ 'आवास क्षेत्र में विवाद समाधान तंत्र - रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभाव का एक अध्ययन' पर पेपर प्रस्तुत किया।
6. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की भूमिका पर पेपर प्रस्तुत किया गया -15-16 दिसंबर, 2022 को आयोजित होने वाले 'रिपोजिशनिंग इंडिया @ 2047 : राष्ट्र निर्माण के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर दोबारा गौर' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में ईशा कौशल के साथ एक आकलन।
7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रस्तुत पेपर - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर राष्ट्रीय वेबिनार में एक आकलन: 9 मार्च, 2023 को अजमल लॉ कॉलेज, असम और उपभोक्ता वकालत समूह द्वारा आयोजित एक विश्लेषणात्मक चर्चा।

(iv) अन्य गतिविधियाँ

1. उपभोक्ता संरक्षण कानून : चुनौतियां और अवसर पर 4-5 नवंबर, 2022 को दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्र (सत्र 3 और 4) की सह-अध्यक्षता की गई।
2. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम द्वारा 30 अगस्त, 2022 को आयोजित आईटीएस अधिकारियों के लिए 01 अगस्त से 11 नवंबर, 2022 तक फाउंडेशन कोर्स में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर दो सत्र आयोजित किए गए।
3. 31 मार्च, 2023 को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम द्वारा 27 फरवरी - 9 जून, 2023 तक आईटीएस ग्रुप 'ए' और आईआरआरएस ग्रुप 'ए' के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए फाउंडेशन कोर्स में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर दो सत्र आयोजित किए गए।
4. डीएआरपीजी, भारत सरकार के लिए तैयार की गई आचार संहिता संस्थान के लिए आपके द्वारा किया गया कोई अन्य प्रमुख योगदान।
 - एनपीपीए 2023 में अनुबंध के आधार पर वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (कानूनी) की भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सदस्य, साक्षात्कार पैनल।
 - सदस्य, राजभाषा कार्यवाहन समिति, आईआईपीए
 - सदस्य, केस स्टडी मूल्यांकन समिति, आईआईपीए
 - आईआईपीए कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा के लिए संकाय प्रभारी

ममता पठानिया

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लेखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी ए)

क्रमांक	शीर्षक	फंडिंग एजेंसी	पूर्ण होने की तिथि
1.	एनसीएच के माध्यम से एकीकृत शिकायत समाधान प्रणाली (सह-परियोजना निदेशक)	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार	जून, 2022

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

प्रस्ताव प्रस्तुत/जारी है

- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए आचार संहिता और डीएआरपीजी को सौंपा गया मसौदा संहिता।
- पेन्शन और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार से भारत के प्रशासनिक इतिहास परियोजना पर कार्य करना, (चालू)।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना का मूल्यांकन, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को प्रस्तुत किया गया।
- केंद्र सरकार के चुनिंदा मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों में नागरिक चार्टरों की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए अध्ययन, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को प्रस्तुत किया गया।
- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को प्रस्तुत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन ढांचे की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईआईपीए में एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना।
- लोक प्रशासन पर कार्यकारी कार्यक्रम का प्रस्ताव पंजाब विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया (प्रस्ताव समीक्षाधीन है)
- सार्वजनिक प्रशासन और एमसीटीपी पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बीआईपार्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया- भा.लो.प्र.सं. को कुल 1.5 करोड़ रुपये (लगभग) राजस्व अर्जित करने वाले पांच कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।
- सितंबर तक BIPARD के तीन और कार्यक्रम पाइपलाइन में हैं। आईआईपीए को प्रति कार्यक्रम 35 लाख (लगभग) रु. 1.5 करोड़ (लगभग) का कुल राजस्व प्राप्त हुआ।
- एनआईसीएफ, राकांपा, अमेजॉन के साथ समझौता ज्ञापन शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईआईपीए को कार्यक्रमों की श्रृंखला की पेशकश की गई, जिससे आईआईपीए को अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ।
- एनटीआईपीआरआईटी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिससे अब आईआईपीए के साथ आगे के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बनी है।

(सी) अनुसंधान मार्गदर्शन

क्रमांक	नमांकितों की संख्या	प्रस्तुत थीसिस	डपाधि प्रदान की गई
1.	स्वचालित वाहन: भारत में आपराधिक कानून के लिए विश्लेषण की आवश्यकता, 48वां अप्पा, श्री मधु सूदन सिंघल	हाँ	-
2.	रक्षा कर्मियों की वित्तीय साक्षरता: वित्तीय तत्परता से वित्तीय कल्याण तक, एयर कमांडर दीपक कुमार वत्स (वीएम)	हाँ	-

प्रकाशन

पुस्तकें/मोनोग्राफ

- 'डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण भारत में इसका प्रभाव' शीर्षक वाला अध्याय प्रस्तुत किया गया, ममता पठानिया, किरण गुप्ता, पार्थ प्रतिम मित्र और प्रकाश शमा (एड), द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द कंज्यूमर लॉ, थॉमसन रॉयटर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रकाशन के लिए स्वीकृत)

कागजात और लेख

- स्ट्रीट फूड विक्रेता: भारत में खाद्य सुरक्षा मानक और स्वच्छता व्यवहार-चुनिंदा शहरों का एक अध्ययन, ममता पथनिया, सुरेश मिश्रा, 'पीपुल सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया' (एड) प्रोफेसर के.के. पांडे भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली 2023 (प्रेस में)

(डी) पुस्तक समीक्षाएँ

एच.सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक:

- स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर एक पेपर प्रस्तुत किया गया: भारत में खाद्य सुरक्षा मानक और स्वच्छता व्यवहारों-भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में चुनिंदा शहरों का एक अध्ययन, 6-7 दिसंबर, 2022.
- डॉ. राजिंदर प्रसाद नेशनल कन्वेंशन ऑन रिपोजिशनिंग इंडिया @ 2047: राष्ट्र निर्माण के लिए सतत विकास लक्ष्यों में संशोधन, 15-16 दिसंबर, 2022 में सतत उपभोग: एक बेहतर कल की ओर पर एक पेपर प्रस्तुत किया।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय,

संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- उपभोक्ता संरक्षण पर ऑनलाइन डिप्लोमा : कानून और नीति (दिसंबर 2022-अप्रैल 2023)- संस्थान के पहले डिप्लोमा के पहले बैच ने सफलतापूर्वक पूरा किया।
- सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आईआईपीए के सिविल सेवा परामर्श कार्यक्रम 'प्रयास के प्रमुख सदस्यों में से एक-
- एसजीओएस नौ विज़न इंडिया @ 2047 पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सलाह देने के लिए आईआईपीए के कार्य समूह के सदस्य।
- एनसीएच आईआईपीए, नई दिल्ली के माध्यम से एकीकृत शिकायत निवारण के सह-परियोजना निदेशक (जून 2022 तक)।
- संस्थान द्वारा समय-समय पर गठित आंतरिक समितियों के सदस्य।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- डीएआरपीजीके विज़न इंडिया @ 2047 रोडमैप फॉर गवर्नेंस, डीएआरपीजी, भारत सरकार पर कार्य समिति के सदस्य।
- अपना भारत विज़न @ 2047 तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभाग के सलाहकार सदस्य।
- सदस्य, राष्ट्रीय दर्पण समिति (एनएमसी), भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली की उपभोक्ता नीति समिति (सीओपोएलसीओ)।
- सदस्य, एरिया एडवाइजरी बोर्ड (एएबी) और बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस), एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (एआईपीपी), एमटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश।
- सदस्य, उपभोक्ता जागरूकता पर ऑडियो-विजुअल और प्रिंट क्रिएटिव के लिए स्क्रिप्ट पर विचार करने के लिए स्क्रिप्ट समिति (जागो ग्राहक जागो

के बैनर तले), उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए), भारत सरकार।

- यूपीएससी और विभिन्न राज्यों के कई लोक सेवा आयोगों की समीक्षा और मूल्यांकन पैनल पर।

जे. शाखाओं के साथ जुड़ाव

- सौपी गई शाखा : तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश

के. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- पैनलिस्ट/संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित :
11. लोक प्रशासन और शासन विषय पर 29 सितंबर, 2022 को 'अभ्यास' कार्यक्रम के लिए ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया।
 12. फिलीपींस सरकार के अधिकारियों के लिए सतत विकास के लिए 'नेतृत्व, प्रबंधन और शासन प्रैक्टिसेस' पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'नागरिक-केंद्रित शासन' पर मुख्य वक्ता 9 फरवरी, 2022.
 13. डॉ. आर. एस. टोलिया प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा 1 जुलाई 2022 को आयोजित 'कल्याणकारी राज्य की उत्पत्ति और अवधारणा और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों की भूमिका, कल्याण योजनाओं और उनकी निगरानी और मूल्यांकन में अभिसरण पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता।
 14. आईजीओटी प्लेटफॉर्म के लिए सेवा वितरण प्रबंधन पर तैयार मॉड्यूल।
 15. 2 अगस्त, 2022 को (प्राइड) संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण प्रभाग में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के मार्शल्लो/सुरक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में 'संगठनात्मक व्यवहार और नैतिकता' पर मुख्य वक्ता।

16. 13 सितंबर, 2022 को मानक भवन, नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के '2022-27 के लिए मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (एसएनएपी) के हितधारक परामर्श में मानकीकरण और उपभोक्ता जागरूकता' पर मुख्य वक्ता।
17. गुरु-दक्षता में 'कार्यस्थल पर नैतिकता' पर मुख्य वक्ता : जीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 17.09.2022 को 5वां संकाय प्रेरण कार्यक्रम (ऑनलाइन) आयोजित किया गया।
18. 17 नवंबर, 2022 को हिपा में आईपीएस, आईपीओएस और आईआरएएस अधिकारियों के लिए विशेष फाउंडेशन कार्यक्रम में 'प्रशासनिक सुधार' पर मुख्य वक्ता।
19. 25 नवंबर, 2022 को यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रूसा 10वें फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में 'कार्यस्थल पर नैतिकता' पर मुख्य वक्ता।
20. यूजीसी-मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित गुरु-दक्षता : छोटे फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (ऑनलाइन) में दिनांक 12.01.2023 को 'कार्यस्थल पर नैतिकता' पर मुख्य वक्ता
21. 18 जनवरी, 2023 को एनआईसीएफ, घिडोरनी, नई दिल्ली दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा संचार मंत्रालय के समूह ए अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तत्वावधान में व्यवहारिक योग्यता के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला में 'शासन में नैतिकता' पर मुख्य वक्ता।
22. एनआईसीएफ, घिडोरनी, नई दिल्ली दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा 27 फरवरी, 2023 को आयोजित दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तत्वावधान में व्यवहारिक योग्यता के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला में 'शासन में नैतिकता' पर मुख्य वक्ता।
23. एनआईसीएफ, घिडोरनी, नई दिल्ली दूरसंचार

विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा 22 मार्च, 2023 को आयोजित दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी के तत्वाधान में व्यावहारिक योग्यता के लिए तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में एनआईसीएफ में 'शासन में नैतिकता' पर मुख्य वक्ता।

एल. किए गए किसी भी अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर नहीं दिया गया है।

'सार्वजनिक सेवाओं में नैतिकता' पर एक अवधारणा नोट तैयार किया गया, जो डीएआरपीजी, भारत सरकार को 28 जुलाई, 2022 को प्रस्तुत किया गया।

24. भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में 'शिक्षण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में केस विधि' विषय पर 5 दिसंबर, 2022 को आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

25. 6 और 7 दिसंबर, 2022 को भारत, सीयूएस, भा.लो.प्र.सं. में पीपुल्स सेंट्रिक अर्बन गवर्नेंस (पीसीयूजी) पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

26. 'रिपोजिशनिंग इंडिया @ 2047 : रिविज़िटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर नेशन बिल्डिंग' विषय पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। (15-16 दिसंबर, 2022).

श्यामली सिंह

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

ए. शीर्षक: गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

बी. अवधि: तीन वर्ष

सी. फंडिंग एजेंसी: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी)

डी. प्रारंभ करने की तिथि: जुलाई, 2020

ई. पूर्ण होने की तिथि: जून, 2023

एफ. समापन की प्रस्तावित तिथि. जून, 2023

जी. स्थिति : जारी है

प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

I. शीर्षक: शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों के लिए पुस्तिका

II. प्रकाशक: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक प्रशासन

III. स्थान: नई दिल्ली

IV. प्रकाशन की तिथि: 2022

I. शीर्षक:

II. प्रकाशक:

III. जगह:

IV. प्रकाशन की तिथि: 2022

(बी) कागजात और लेख

I. शीर्षक: आर्द्रभूमियों का शहरीकरण और पुनरुद्धार

II. जर्नल: आईआईपीए डाइजेस्ट

III. दिनांक: सितंबर, 2022

(सी) कोई अन्य प्रकाशन

I. शीर्षक: जल सुरक्षा और आजीविका प्रवचन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को उजागर करना

II. पुस्तक में अध्याय: आत्मनिर्भर भारत के चालक।

III. स्थान: नई दिल्ली

IV. दिनांक: 2022

V. शीर्षक: पारिस्थितिकी तंत्र को समझना: एक बाल केंद्रित प्रतिमान

VI. जर्नल में अध्याय: 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस

VII. स्थान: असम

VIII. दिनांक : 2022

सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: समावेशी और टिकाऊ शहरी स्थान बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार: कश्मीर के विशेष संदर्भ में भारत में शहरीकरण और शहरी नियोजन
- II. आयोजन एजेंसी: कश्मीर विश्वविद्यालय
- III. स्थान एवं दिनांक: कश्मीर (13-14 मार्च, 2023)
- IV. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: जलवायु परिवर्तन के नजरिये से शहरी चुनौतियाँ
- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: राष्ट्रीय सेमिनार: भा.लो.प्र.सं., सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस (सीआईआरएस) और आईसीएसएसआर के बीच 75वें संयुक्त सहयोग पर भारत की कूटनीति
- II. आयोजन एजेंसी: इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आईसीएसएसआर
- III. स्थान एवं दिनांक: नई दिल्ली, 9-10 फरवरी, 2023
- IV. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: भारत की पर्यावरण कूटनीति
- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: सर्वोत्तम नवीन शिक्षण रणनीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICON& BITS-2023)
- II. आयोजन एजेंसी: बिट्स पिलानी
- III. स्थान और दिनांक: बिट्स पिलानी (ऑनलाइन), 9-11 फरवरी, 2023
- IV. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: क्लाइमेट स्कूल - एक क्षमता निर्माण रणनीति
- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- II. आयोजन एजेंसी: भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
- III. स्थान एवं दिनांक: नई दिल्ली, 6-7 दिसंबर, 2022

IV. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: शहरी नियोजन में जलवायु लचीलेपन का निर्माण

- I. सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक: ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और उपयोगिता प्रदर्शनी
- II. आयोजन एजेंसी: एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान
- III. स्थान एवं दिनांक: बैंकॉक (ऑनलाइन) (26-28 अक्टूबर, 2022)
- IV. प्रस्तुत पेपर का शीर्षक: जलवायु प्रशासन: क्षेत्रीय दृष्टिकोण

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सूखा प्रशासन केंद्र के समन्वयक
- नमामि गंगे द्वारा प्रायोजित 'गंगा नदी के हितधारकों के लिए मिश्रित क्षमता निर्माण कार्यक्रम' के परियोजना अन्वेषक

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा नियुक्त: असम शाखा समन्वयक

गदाधर महापात्र

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लेखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं श्रेणी (ए) वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है)

VI. शीर्षक: 'असंगठित श्रमिकों पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन'

VII. अवधि: 3 महीने

VIII. फंडिंग एजेंसी: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

IX. प्रारंभ करने की तिथि: 01.02.2023

X. समापन की तिथि: 31.3.2023

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएँ (श्रेणी बी)

VII.. शीर्षक: वन अधिकार अधिनियम, 2006 (जमीनी हकीकत का आकलन

IX. अवधि;

X. फंडिंग एजेंसी:

XI. अनुदान:

XII. प्रारंभ करने की तिथि:

XIII. पूरा होने की तिथि:

(बी) कागजात और लेख एक (01)

I. शीर्षक: एकीकृत रबर विकास परियोजनाएं और जनजातीय आजीविका पर इसका प्रभाव: त्रिपुरा के विशेष संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र का मामला

II. जर्नल: ट्रांससिएंस वैश्विक अध्ययन का एक जर्नल है।

III. वॉल्यूम: वॉल्यूम 13

IV. संख्या: अंक सं. 1

V. दिनांक: 2022

(सी) कोई अन्य प्रकाशन

I. शीर्षक: वन अधिकार अधिनियम के प्रभाव का आकलन करने के लिए भा.लो.प्र.सं. टीम ने गोमती का दौरा किया।

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: त्रिपुरा टाइम्स प्रिंटमीडिया

III. स्थान: अगरतला

IV. दिनांक: 26 मार्च, 2023

I. शीर्षक: वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर भा.लो. प्र.सं. प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन: जमीनी हकीकत

का आकलन' और एलुरु जिले, आंध्र प्रदेश का फील्ड दौरा।

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: एबीएन न्यूजप्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Url: <https://epaper.andhrajyothy.com/>)

III. स्थान: एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश

IV. दिनांक: 1 अप्रैल, 2023

I. शीर्षक: वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर भा. लो.प्र.सं. प्रभाव अध्ययन: जमीनी हकीकत का आकलन और नंद्याल जिले, आंध्र प्रदेश का फील्ड दौरा

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: हंस समाचार सेवा, तिरुपति प्रिंट मीडिया

III. स्थान/तिरुपति जिला, आंध्र प्रदेश

IV. दिनांक: 29 मार्च, 2023.

I. शीर्षक: वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर भा.लो. प्र.सं. प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन: जमीनी हकीकत का आकलन और गरियाबंद जिला, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय दौरा

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: हरिभूमि समाचारपत्र प्रिंट मीडिया

III. स्थान: गरियाबंद, छत्तीसगढ़

IV. दिनांक: 26 मार्च, 2023

I. शीर्षक: लातेहार, झारखंड में जनजातीय समुदायों पर वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: खबर मंत्र प्रिंट समाचार पत्र, लातेहार

III. स्थान: लातेहार, झारखंड

IV. दिनांक: 20 सितंबर, 2022

I. शीर्षक: सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में जनजातीय समुदायों पर वन अधिकार अधिनियम का प्रभाव

II. पुस्तकों/जर्नल में अध्याय: संवाद न्यूज एजेंसी, सोनभद्र

III. स्थान: सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

IV. दिनांक: 15 सितंबर, 2022

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय (वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23) के तहत नोडल व्यक्ति-प्रमुख संसाधन केंद्र- भा.लो.प्र.सं।
- टीम सदस्य, जनजातीय अध्ययन और अन्वेषण केंद्र, भा.लो.प्र.सं।
- श्री अरविंद वर्मा (रोल नंबर 4836) का पर्यवेक्षित एम.फिल शोध प्रबंध। मुस्कान के साथ मुखौटा: दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत के डाकघरों में भावनात्मक श्रम और जॉब बर्नआउट एवं जॉब संतुष्टि के साथ इसके संबंध का एक अनुभवजन्य अध्ययन (लोक प्रशासन में दर्शनशास्त्र के परास्नातक), 48 वें अप्पा प्रतिभागी, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली (मौखिक परीक्षा आयोजित की गई और उम्मीदवार को जुलाई, 2023 को मास्टर्स डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया)।
- 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 'महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व वाले विकास' विषय पर आयोजित होने वाले सदस्य वार्षिक सम्मेलन के लिए वार्षिक निबंध प्रतियोगिता दिशानिर्देश तैयार किए।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन में समीक्षा संपादक-फ्रंटियर्स इंटरनेशनल जर्नल (5.2 इम्पैक्ट फैक्टर, 3.8 साइटस्कोर), 24 जुलाई, 2022 से। फ्रंटियर्स मीडिया एसए, एवेन्यू डू ट्रिब्यूनल-फेडरल 34 1005 लॉजेन स्विट्ज़रलैंड।
- डॉ. गदाधर महापात्र पीएचडी उम्मीदवार सुश्री अर्निमा

भार्गव (नामांकन संख्या 16261319002), एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (एआईएसएस), एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के बाहरी सह-मार्गदर्शक हैं। थीसिस का शीर्षक: बीटी कपास बीज फार्मों में बाल श्रम का स्थितिजन्य विश्लेषण: गुजरात का एक अध्ययन। पंजीकरण की तिथि: 1 जनवरी, 2021, (थीसिस अप्रैल 2023 में प्रस्तुत की गई)।

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा नियुक्त भा.लो.प्र.सं., भुवनेश्वर की क्षेत्रीय शाखा के सदस्य।

किसी अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर नहीं दिया गया है।

- 6 से 7 मार्च, 2023 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित 'सुशासन प्रैक्टिसेस' पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भा.लो.प्र.सं. द्वारा नामांकित किया गया और मैंने भोपाल में सम्मेलन में सफलतापूर्वक भाग लिया।
- कन्वेंशन सेंटर, आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव, 2013' में आमंत्रित और भाग लिया। मैंने 11 जून, 2023 को आयोजित प्रशिक्षण सम्मेलन में भाग लिया।

मनन द्विवेदी

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी)

ए) (वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित अनुसंधान दोनों पर लागू होता है)

IX. शीर्षक: भारत की विदेश नीति: अतीत और वर्तमान शासन के बीच तुलना

X. अवधि: दो वर्ष

XIII. फंडिंग एजेंसी: आईसीएसएसआर

प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

I. शीर्षक: मनन द्विवेदी, भारत की विदेश नीति, अने बुक्स, 2023

मनन द्विवेदी, माइग्रेशन इन कोविड टाइम्स, अने बुक्स, 2023

(बी) कागजात और लेख

मनन द्विवेदी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच अंतर, विश्व मामले, 2022

मनन द्विवेदी, अमेरिकी मामलों पर पायनियर में दस ओप एड (घरेलू और विदेश नीति दोनों क्षेत्र)

गवर्नेस नाउ में तीन पेपर।

ऑर्गेनाइज़र, विओन न्यूज और टीवी नौ में दो पेपर।

मनन द्विवेदी, द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, हिमाचल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 2023

एच. सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर

‘भारत कोरिया संबंध’ पर आरएएसके अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए गए पेपर।

‘आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध’ विषय पर उसानास फाउंडेशन के महाराणा प्रताप संवाद में एक पैनलिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया पेपर।

अनुसंधान पद्धति पर एमिटी विश्वविद्यालय के वैश्विक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अफ्रीका में संघर्ष समाधान पर पेपर प्रस्तुत किया गया।

आई. भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)– भागीदारी का विवरण और प्रकृति।– पिछले छह महीनों से आईजेपीए के संपादकों में से एक

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

मोतीलाल नेहरू कॉलेज के सदस्य, डीयू के शासी निकाय, विदेश सेवा संस्थान के साथ अतिथि संकाय और इंडियन सोसायटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ।

जे. शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: झारखंड, मॉडल जिलों पर उनके मोनोग्राफ का पर्यवेक्षण

पवन कुमार तनेजा

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

क्र.सं.	नाम	द्वारा प्रायोजित	अध्ययन दल	स्थिति
1.	उत्तर प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन: सुशासन सूचकांक (जीजीआई) की नकल करना	उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार	डॉ. पवन के. तनेजा प्रो. चारु मल्होत्रा	पूरी धानराशि प्राप्त हो गई, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है
2.	खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) इकाइयों/संस्थानों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन और केवीआई क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों/संस्थानों द्वारा उत्पन्न उत्पादन, बिक्री और रोजगार का अनुमान	पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार	डॉ. पवन के. तनेजा डॉ. रोमा देबनाथ	डेटा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

केस स्टडी तैयार की गई

यूपी सुशासन सूचकांक के लिए 75 केस स्टडीज तैयार कीं।

प्रकाशन

(ए) पुस्तकें

आई. मिश्रा एस., सिंह एस., तनेजा पी.के. (प्रकाशन में) 'आत्मनिर्भर भारत उभरते परिप्रेक्ष्य', भा.लो.प्र.सं. प्रकाशन, नई दिल्ली

(बी) कागजात और लेख

- I. तनेजा, पी., जैन, ए., जोशी, एम. और कंसल, एम. (2022), 'भारत में अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: रिपोर्टिंग वास्तविकता, मुद्दे और आगे बढ़ने का रास्ता', मेडिटरी अकाउंटेंसी रिसर्च, वॉल्यूम 30 नंबर 3, पीपी. 472-494- <https://doi.org/10-1108/MEDAR&11&2020&1063>.
- II. वशिष्ठ, ए., कुकरेती, आई. और तनेजा, पी.के., 2022. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन: मुद्दे और आगे का रास्ता। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 68 (2), जून, 2002 पीपी 257-270.
- III. तनेजा पी.के. सिंह, एस., मिश्रा, एस. (आगामी), 'आत्मनिर्भर सिद्धांत और भारत में इसका अनुप्रयोग' अध्याय 1, मिश्रा एस., सिंह एस., तनेजा पी.के. (प्रकाशन में) 'आत्मनिर्भर भारत: उभरते परिप्रेक्ष्य', भा.लो.प्र.सं. प्रकाशन, नई दिल्ली।

(सी) कोई अन्य प्रकाशन

तनेजा पी.के. और त्रिपाठी एस.एन. (2022), आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भा.लो.प्र.सं. के 65वें सदस्यों के वार्षिक सम्मेलन- 2021 की कार्यवाही, भा. लो.प्र.सं. प्रकाशन, नई दिल्ली

(डी) पुस्तक समीक्षाएँ

- 'सुशासन के लिए ई-गवर्नमेंट संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण: बैक-ऑफिस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आईटी सिस्टम्स' सईद अजेलमाड, सीआरसी प्रेस, टेलर और फ्रांसिस ग्रुप द्वारा।
- एमडीपीआई के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में समीक्षक:

'हाई-स्पीड रेल, बाजार प्रतिस्पर्धा और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी: चीन में साक्ष्य' पर पेपर के लिए स्थिरता।

- सेज पब्लिकेशन द्वारा 'सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन' पाठ्य पुस्तक।

सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में 17 जनवरी, 2023 को 'राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक' के दौरान 'कार्यक्रम के परिणामों में सुधार के लिए समस्या समाधान और निर्णय लेने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण' का उद्घाटन भाषण।
- यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ द्वारा 31 मार्च, 2023 को आयोजित डिजिटल युग में शासन सुधार: बहुविषयक परिप्रेक्ष्य पर राष्ट्रीय सेमिनार में 'अमृत काल में शासन सुधार 'ब्रिगिंग सिटिजन एंड गवर्नमेंट क्लोजर' मुख्य भाषण।
- कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के 'चिंतन शिविर' में आइस ब्रेकिंग सत्र 17-18 फरवरी 2023, सीएसओआई, विनय मार्ग, नई दिल्ली।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 12 सितंबर, 2022 को आयोजित सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर कार्यशाला में विशेषज्ञ समूह का हिस्सा।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि) - भागीदारी का विवरण और प्रकृति।

- I. सदस्य, आर्थिक विकास एवं प्रबंधन अध्ययन केंद्र
- II. सदस्य, भा.लो.प्र.सं. की वार्षिक निबंध प्रतियोगिता समिति
- III. भा.लो.प्र.सं. केस स्टडी प्रतियोगिता के मेंटर

IV. सदस्य, भा.लो.प्र.सं. विजन/2047 दस्तावेज और प्रस्तुति टीम

V. भा.लो.प्र.सं. में विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आई-टीईसी) कार्यक्रम के समन्वयक।

VI. राष्ट्रीय नीति और सामरिक अध्ययन संस्थान, नाइजीरिया के बीच समन्वित दौरा और समझौता ज्ञापन

VII. बेलारूस के राजदूत की समन्वित यात्रा और लोक प्रशासन अकादमी, बेलारूस के साथ समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की गई।

(बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

I. भारत सरकार के 12 मंत्रालयों/विभागों के साथ भारत शासन विजन @2047 पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह नौ के साथ काम किया।

II. सदस्य, अध्ययन बोर्ड, लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीति विभाग, असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम

III. भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक द्वारा 18 सितंबर 2022 को आयोजित 'लीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में 'लीन सप्लाय चेन और लीन मूल्यांकन ढांचे' पर सत्र।

IV. अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद में बुधवार, 07 दिसंबर, 2022 को 25 देशों के प्रतिभागियों के लिए परियोजना प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से 'वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और रिसोर्स लेवलिंग' पर बातचीत।

V. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद में शुक्रवार, 02 दिसंबर, 2022 को 25 देशों के प्रतिभागियों के लिए परियोजना प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से 'परियोजना लक्ष्य, दायरा और सफलता मानदंड' पर बातचीत।

VI. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद में 4 नवंबर, 2022

को 'एक्सेल का उपयोग करके वित्तीय निर्णय लेने' पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम में बातचीत।

VII. इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा द्वारा 29 सितंबर, 2022 को आयोजित 'मध्य-स्तरीय अधिकारियों (ईई और एसई) के लिए प्रबंधन विकास' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 'प्रभावी नेतृत्व कौशल, समय प्रबंधन और प्रभावी बैठकें' पर बात करें।

VIII. बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली में सिस्टम टूल्स और संचालन अनुसंधान पर एक सत्र में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

IX. बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट विभाग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर एक सत्र में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

X. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली में सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट (एचआर और फाइनेंस) में सर्टिफिकेट कोर्स में 'बिजनेस मैनेजमेंट के बुनियादी सिद्धांत' विषय पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया।

शाखाओं के साथ जुड़ाव

सौंपी गई शाखा: केरल

किसी अन्य शैक्षणिक अथवा की गई संबंधित गतिविधि का विवरण

उपर्युक्त को शामिल नहीं किया गया है।

- 3-4 मार्च, 2022 को खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव पर राष्ट्रीय स्तर की हितधारक कार्यशाला वित्त पोषित की गई।
- जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय को तीन वर्ष के लिए 49 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ भा.लो.प्र.सं. में सतत तटीय विकास और नीतिगत मुद्दों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर सक्रिय विचार चल रहा है।
- डॉ. सचिन चौधरी के साथ एमएसएमई पर अध्ययन के लिए विश्व बैंक को 6.5 करोड़ का प्रस्ताव सौंपा। प्रस्ताव का चयन नहीं हुआ।

सुरभि पांडे

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लिखित)

सेमिनार/सम्मेलन का आयोजन

I. 14सी, एमएचए के सहयोग से साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया: राष्ट्रीय टीवी और पीएमई-विद्या पर प्रसारित किया गया:

जनवरी 2023 में पूरे एक महीने तक प्रत्येक बुधवार को सीआईईटी, एनसीआईआरटी के सहयोग से साइबर जागृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम ई-विद्या और राष्ट्रीय टीवी के कई चैनलों पर उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ का प्रसारण किया गया। उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डार्क वेब, आईओटी, क्लाउड और क्रिप्टो धोखाधड़ी पर चर्चा की गई।

II. कार्यशालाएँ एवं सम्मेलन आयोजित किए

ए. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया और गवर्नेंस (ऑनलाइन) पर कार्यशाला दिनांक 28.03.2023 को आयोजित की गई।

बी. बलात्कार के मामलों के त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और ई-पाक्सो न्यायालय पर माननीय उच्च न्यायालयों और सभी राज्यों के नोडल जिला स्तरीय न्यायाधीशों और न्यायालय प्रबंधकों, डीओजे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरकार के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

सी. निर्भया फंड के तहत ईआरएसएस 112 सेवाओं के कार्यान्वयन की चर्चा पर ओडिशा राज्य के 30 जिलों और कटक के नोडल कार्यालय के साथ सम्मेलन में भाग लिया।

डी. भारत के क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रायोजित सीटीआई और एटीआई के लिए शासन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला, जिसमें माननीय राज्य मंत्री और आईटी मंत्री प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति थे।

ई. भारत में सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और साइबर अपराधों की रोकथाम के उपायों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। आईटी उद्योग, मेलवेयर का पता लगाने वाले, वकील, शिक्षा जगत, बैंकिंग, फिनटेक और सरकारी सेवाओं के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला 14सी, एमएचए, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

एफ. डब्ल्यू एस डिवीजन, ईआरएसएस पर गृह मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करना, सुरक्षित शहर, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित दिल्ली पुलिस योजना और क्षमता निर्माण के सहयोग से निर्भया फंड भा. लो.प्र.सं. के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाओं पर पांच दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन।

जी. 11 अप्रैल, 22 को भारत में साइबर इको सिस्टम के विकास और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर उपायों पर एक दिवसीय कार्यशाला। 14सी, एमएचए द्वारा वित्त पोषित। पूरे भारत के 80 वरिष्ठ एल ई ए अधिकारियों ने भाग लिया।

एच. आईआरएस (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) अधिकारियों के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीन दिवसीय कार्यशाला।

III. भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में विशेष व्याख्यान/वार्ता का आयोजन किया गया

ए. मैंने न्यायाधीशों, सीमा शुल्क और अप्पा अधिकारियों के लिए आमंत्रित प्रेरक वक्ता शिव खेड़ा को आमंत्रित किया है।

व्यावसायिक क्षेत्रों पर सत्र/चर्चा में भागीदारी

I. साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, डार्क वेब, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, फोरेंसिक टूल्स और लीडरशिप एवं सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों और समसामयिक मुद्दों पर विशेष व्याख्यान दिए और विभिन्न सत्रों में भाग लिया।

ए. 21वीं सदी के डिजिटल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा उपायों की थीम पर कतर जम्मू में आयोजित राष्ट्र ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनईजीसी) में मुख्य वक्ता।

बी. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के लिए विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में एआई और एमएल पर मुख्य वक्ता।

सी. राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब में वरिष्ठ अभियोजकों के साथ सोशल मीडिया साक्ष्य और अभियोजन पर मुख्य वक्ता।

डी. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गृह मंत्रालय के साथ साइबर सुरक्षा पर चर्चा।

ई. गुजरात और राजस्थान राज्यों के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए उड़ान 15 के तहत बड़े पैमाने पर समाज और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता।

एफ. केआईएसएस, ओडिशा के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ साइबर स्वच्छता कार्यक्रम।

जी. माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल के लिए पाठ्यक्रम समीक्षा और शोध पत्र संपादित।

एच. एटीआई नैनीताल प्रशासन अकादमी के लिए ई-गवर्नेंस और डेटा एनालिटिक्स सत्र आयोजित किए गए।

आई. सीएपीटी भोपाल पुलिस अकादमी में डार्क वेब और क्रिप्टो जांच पर नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक से बातचीत की।

जे. परिवर्तन प्रबंधन और पारस्परिक कौशल (एनएसीएलआईएन 2022) पर पूरे भारत और डेलनेट से जुड़े कुछ देशों के वरिष्ठ लाइब्रेरियन के साथ बातचीत की।

के. आईएसटीएम में बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई और लीडरशिप सॉफ्ट स्किल सत्र पर उप निदेशकों और अमेरिका के साथ बातचीत की।

एल. राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब में वरिष्ठ अभियोजकों के साथ सोशल मीडिया साक्ष्य और अभियोजन पर सत्र आयोजित किए।

एम. आईएफएसओ, एनसीएफएल, एमएचए द्वारा में डार्क वेब और ओएसआईएनटी टूल पर कई आईओ और इंस्पेक्टरों को प्रशिक्षित किया।

एन. ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के स्कूलों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम।

टो. गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के संकाय के साथ अनुसंधान और परियोजना पद्धति।

पी. 'सी' पीढ़ी के साथ साइबर जागरूकता पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत।

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए और बी)

क्र.सं.	पूर्ण परियोजना	मंत्रालय
1.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की योजना''	न्यायविभाग
2.	राज्य स्तर पर ओडिशा ईआरएसएस 112 योजना का मूल्यांकन	राज्य स्तर
3.	एसओ/एसओ के डॉकस्टा कार्यक्रम का प्रभाव आकलन	भारतीय क्षमता निर्माण आयोग
4.	दिल्ली पुलिस की रात्रि गश्त प्रक्रिया का थर्ड पार्टी ऑडिट	दिल्ली पुलिस
5.	पुलिसिंग की प्रभावशीलता और परिणामों पर पुलिस आयुक्तालय का प्रभाव (बीपीआर एंड डी)	बीपीआर एंड डी, एमएचए
6.	निर्भया फंड, गृह मंत्रालय के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजनाओं/योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन	गृह मंत्रालय
7.	दिल्ली राजनीतिक विकास और प्रशासनिक संरचना की ई-कॉफी टेबल बुक का डिजाइन, जीएडी, एनसीटी दिल्ली	जी ए डी एनसीटी दिल्ली
8.	सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आईएसएस अधिकारियों की सीधी भर्ती की सिफारिश करने वाली समिति की रिपोर्ट	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

केस स्टडी तैयार की गई

निर्भया फंड, गृह मंत्रालय के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाओं पर केस स्टडी विकसित की गई

प्रकाशन

- I. आईजेपीए के आगामी खंड द्वारा रोबो जजों पर वर्किंग पेपर।
- II. निर्भया योजना पर केस स्टडी विकसित की गई।
- III. शीर्षक “रीयल-टाइम गवर्नेंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी: इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईजेपीए) द्वारा एक भारतीय परिदृश्य, वॉल्यूम 68 अंक 3, सितंबर, 2022.

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

(ए) समझौता ज्ञापन (एमओयू) समन्वित और हस्ताक्षरित/चल रही प्रक्रिया।

- ए. उत्तर प्रदेश के लगभग 3000 न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए यूपी राज्य के कानून विभाग और माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के साथ वर्ष 2021-2023 तक एमडीपी समझौता ज्ञापन।
- बी. प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सहयोग के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और भा.लो.प्र.सं. के बीच एमओयू तैयार और समन्वित किया गया।
- सी. भा.लो.प्र.सं. के साथ समन्वित टी आरआईएफ, भारत डिजाइन लैब।
- डी. कानूनी मामलों के विभाग (डीओएलए), कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली) के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन।
- ई. उभरते तकनीकी प्रशिक्षण और परियोजना कार्य पर भा.लो.प्र.सं. और वाधवानी फाउंडेशन के बीच समन्वित समझौता ज्ञापन।

एफ. क्षमता निर्माण और अनुसंधान कार्य में लद्दाख प्रशासन और सीओई हेतु भा.लो.प्र.सं. के लिए समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया गया।

जी. आईएसटीएम और भा.लो.प्र.सं. के बीच हस्ताक्षरित होने वाला मसौदा समझौता ज्ञापन।

I. पुरस्कार और मान्यता

- ए. वर्ष 2021-2022 के लिए भा.लो.प्र.सं. संकाय द्वारा रु.5,000/-के नकद पुरस्कार के साथ पूरा किए गए शोध अध्ययनों की अधिकतम संख्या के लिए श्री टी.एन.चतुर्वेदी स्मृति प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। यह पुरस्कार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. से प्राप्त हुआ।
- बी. डेलनेट से प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
- सी. विज्ञान भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उद्घाटन भाषण के लिए भारत के जनगणना आयोग, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, भारत के गृह मंत्रालय और भारत सरकार से सराहना मिली।
- डी. एनएलयू पटियाला में साइबर सुरक्षा सत्र के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
- बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

II. समिति सदस्य

- i. ई-गवर्नेंस 2022 मांगने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार समिति सदस्य
- ii. एनईजी - 2022 के तहत सम्मानित चयनित ई-गवर्नेंस पहल पर विकसित केस स्टडीज पर इनपुट -
- iii. साइबर अन्वेषक के लिए बीपीआर7डी का साक्षात्कार पैनल।
- iv. चयन समिति के सदस्य एनसीजीजी में सलाहकार के रूप में एक सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे।
- v. बीआईएसमानक समिति के सदस्य।

vi. एमएचए (गृह मंत्रालय) साइबर विशेषज्ञ समिति के सदस्य।

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: उत्तर प्रदेश

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

I. व्यावसायिक क्षेत्रों/मीडिया/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैनल चर्चा में भागीदारी

- ए. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिजिटल- अमेरिका और कनाडा के दर्शकों के लिए लैंगिक समानता विषय पर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- बी. फिक्की:- उद्योग और मंत्रालयों के साथ मेरे सह पैनलिस्ट के साथ साइबर स्पेस में सुरक्षा और व्यवधान के रूप में उभरती प्रौद्योगिकियों पर टॉक शो की अध्यक्षता और संचालन किया।
- सी. एनसीईआरटी के पीएम ई-विधा चैनल-सेफ डिजिटल गेमिंग पर शो आयोजित किया गया।
- डी. संसद टीवी:- 'अर्थनीति' नामक शो में क्रिप्टोकॉरेसी और एक्सचेंजों पर टॉक शो।
- ई. संसद टीवी:- साइबर सुरक्षा पर टॉक शो।
- एफ. संसद टीवी:- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिजिटल- लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विषय पर टॉक शो।
- जी. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध पर गूगल द्वारा प्रायोजित शक्तिकॉन और अमृता

यूनिवर्सिटी टॉक शो, क्राउड स्ट्राइक और एडब्ल्यूएस।

एच. टॉक शो के साथ

आई. पल्लवबागला एंकर के साथ खुलके राउंड टेबल शो- आप अपने निजी डेटा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

अनुसंधान मार्गदर्शन

- जे. एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन आधारित मैप सर्च पर एएजे तक टीवी एंकर जितेंद्र के साथ राय साझा की गई।
- के. सामाजिक उद्देश्य: 'दैनिक जीवन में साइबर स्वच्छता की अवधारणा और उपयोग' पर संबोधित। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के सशक्तिकरण विभाग के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली के सहयोग से अप्रैल महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया है। वर्चुअल मोड के माध्यम से डीआईएसएलआई और डीटीआईएसएल के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के साथ ज्ञान साझा करना एक शानदार अनुभव था।
- एल. साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर कॉन्फिडस के लिए टॉक शो।

अमित कुमार सिंह

शिक्षण/प्रशिक्षण (अनुलग्नक एफ.2 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची में उल्लेखित)

क्र.सं.	नामांकित संख्या	प्रस्तुत थीसिस	उपाधि प्रदान की गई
1.	नीलेश सिंह	भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता का महत्वपूर्ण विश्लेषण (2000-01 से 2020-21 तक)	पुरस्कार

पूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी ए)

क्र.सं.	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूर्ण/चल रहा है
1.	नई दिल्ली में राहत गंज/आराम गंज, रोशनआरा रोड, पुल बंगश में संपत्ति संख्या 8736-सी के भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन	जीएनसीटीडी, दिल्ली	पूर्ण

2.	ग्राम खानपुर, नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)।	जीएनसीटीडी, दिल्ली	पूर्ण
3.	भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार	पूर्ण
4.	उत्तरी दिल्ली में अलीपुर में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन	जीएनसीटीडी, दिल्ली	प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

चल रही अनुसंधान परियोजनाएं (श्रेणी बी)

क्र.सं.	नाम	द्वारा प्रायोजित	पूर्ण/चल रहा है
1.	‘रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत विवाद समाधान तंत्र का प्रभाव आकलन’ पर शोध अध्ययन	आईसीएसएसआर	चल रही
2.	दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कापसहेड़ा में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन	जीएनसीटीडी, दिल्ली	चल रही
3.	नई दिल्ली में सभापुर, सहादरा में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन	जीएनसीटीडी, दिल्ली	चल रही
4.	बीएफएआईआर कार्यक्रम का स्वतंत्र सत्यापन	वित्त विभाग, पंजाब सरकार	चल रही
5.	यूपी के गाजियाबाद शहर का महिला सुरक्षा ऑडिट	एनसीडब्ल्यू, नई दिल्ली	चल रही

प्रकाशन

- सिंह ए.के. (2022), स्मार्ट सिटी मिशन: आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सफलता की कहानियां, नगरलोक वॉल्यूम एलआईवी, अंक 2, अप्रैल-जून, 2022.
- सिंह ए.के. (2022), प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन- भारतीय शहरों से चुनिंदा केस अध्ययन, नगरलोक खंड। एलआईवी, अंक 3, जुलाई-सितंबर 2022.
- ‘भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन’ पर सीयूएस, भा.लो.प्र.सं. के अन्य संकाय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘वर्षा जल संचयन में **सामुदायिक भागीदारी**: दिल्ली के एक केस स्टडी’ पर पेपर प्रस्तुत किया गया (6 दिसंबर, 2022).
- ‘भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन’ पर सीयूएस, भा.लो.प्र.सं. के अन्य संकाय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में ‘आवास क्षेत्र में विवाद समाधान तंत्र- **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016** के प्रभाव का एक अध्ययन’ पर पेपर प्रस्तुत किया गया। (6 दिसंबर, 2022).
- ‘नेशनल कन्वेंशन ऑन रिविजिटिंग सस्टेनेबल’ में ग्रामीण विकास में **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)** की भूमिका पर पेपर प्रस्तुत

सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में प्रस्तुत किया गया पेपर।

- ‘भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन’ पर सीयूएस, भा.लो.प्र.सं. के अन्य संकाय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन (6 दिसंबर, 2022).

किया गया। राष्ट्रीय निर्माण के लिए विकास लक्ष्य (15-16 दिसंबर, 2022)

- एमओएचयूए द्वारा शहरी क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाना- जलवायु स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ना विषय पर 26-27 सितंबर, 2022 को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।
- 28 सितंबर, 2022 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जीआईजेड, एमओएचयूए और एनआईयूए द्वारा जलवायु क्षमताओं के लिए प्रशिक्षण बढ़ाने पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।
- 27 जनवरी, 2023 को जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर वेबिनार में भाग लिया।

भा.लो.प्र.सं. के भीतर शैक्षणिक कार्य के अन्य रूपों के साथ जुड़ाव

- (ए) समिति/अन्य (प्रभाग और योजना एवं सलाहकार समिति की सदस्यता, समन्वयक, संपादकीय, संयोजक, आदि)- भागीदारी का विवरण और प्रकृति।
- (बी) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से जुड़ाव (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)
- सदस्य: ई-न्यूजलेटर, 'नगरलोक' का संपादकीय बोर्ड

- नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स, इंडिया (एनएजीआई) के आजीवन सदस्य

शाखाओं के साथ जुड़ाव

शाखा सौंपी गई: मिज़ोरम

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्यों का विवरण

- बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बोध गया द्वारा विभिन्न विषयों के लिए अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित।

किसी अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण ऊपर नहीं दिया गया है।

- 'भारत में जन केंद्रित शहरी प्रशासन' पर सीयूएस, भा.लो.प्र.सं. के अन्य संकाय सदस्यों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन (6 दिसंबर, 2022).
- एमसीटीपी और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया।
- पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से एमओएचयूए, भारत सरकार के लिए विभिन्न मुद्दों पर डेटा संग्रह।

अनुलग्नक एफ.6

वर्ष 2022-2023 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण

क्रमांक	शाखा का नाम	वित्तीय सहायता	ब्याज का हिस्सा	डीडीजी अनुसंधान अध्ययन के लिए अनुदान	कुल
	क्षेत्रीय शाखाएँ				
1	असम	35000	1405	0	36405
2	बिहार	35000	5782	12500	53282
3	दिल्ली	35000	13815	0	48815
4	गोवा	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	0	0
6	हरियाणा	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	35000	5294	12500	52794
9	झारखंड	0	0	0	0
10	कर्नाटक#	10000	1680	12500	24180
11	केरल	35000	2816	12500	50316
12	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	35000	3404	12500	50904
13	महाराष्ट्र	35000	5465	12500	52965
14	मणिपुर	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	0	0
16	मिजोरम	35000	801	0	35801
17	ओडिशा	0	1464	12500	13964
18	पुडुचेरी	35000	700	12500	48200
19	पंजाब और चंडीगढ़	35000	1019	0	36019
20	राजस्थान	35000	3530	12500	51030
21	तमिलनाडु	35000	3322	0	38322
22	तेलंगाना और ए.पी.	35000	2805	0	37805
23	उत्तर प्रदेश	35000	9105	12500	56605
24	उत्तराखंड	0	0	0	0
25	पश्चिम बंगाल	35000	1479	0	36479

क्रमांक	स्थानीय शाखाएँ	वित्तीय सहायता	ब्याज का हिस्सा	डीडीजी अनुसंधान अध्ययन के लिए अनुदान	कुल
1	आगरा	0	0	0	0
2	औरंगाबाद	0	0	0	0
3	बरेली	20000	279	0	20279
4	बदायूँ	20000	1477	0	21477
5	बर्दवान	20000	434	0	20434
6	कोयंबटूर	0	0	0	0
7	कुड्डालोर	20000	1121	0	21121
8	कटक	0	0	0	0
9	धारवाड़	20000	444	0	20444
10	डिंडीगुल	0	0	0	0
11	गुलबर्गा*	35000	279	0	35279
12	हावड़ा	20000	430	0	20430
13	इंदौर	0	0	0	0
14	जबलपुर	0	0	0	0
15	जमशेदपुर	0	0	0	0
16	कानपुर*	40000	1666	0	41666
17	करीमनगर	20000	289	0	20289
18	मदुरै	0	0	0	0
19	मैसूर	0	0	0	0
20	मेरठ	0	0	0	0
21	मुजफ्फरपुर	0	434	0	434
22	नागपुर	0	0	0	0
23	नासिक	0	0	0	0
24	पटियाला	0	0	0	0
25	पाटलिपुत्र	20000	289	0	20289
26	पुणे	0	0	0	0
27	सेलम	0	0	0	0
28	सैदापेट	0	0	0	0
29	सांगली	0	0	0	0
30	सिरोही	0	0	0	0
31	तंजावुर	0	0	0	0
32	तिरुचिरापल्ली	0	0	0	0
33	तिरुनेलवेली	0	0	0	0

34	तिरुपति	20000	1153	0	21153
35	तिरुपत्तूर	20000	498	0	20498
36	वडोदरा	20000	353	0	20353
37	वल्लभ विद्यानगर	0	0	0	0
38	वेल्लोर	0	0	0	0
39	विल्लुपुरम	20000	544	0	20544
40	विरुधुनगर	0	0	0	0
41	विशाखापत्तनम	20000	1025	0	21025
42	वारंगल	0	0	0	0
	कुल	870000	74601	125000	1069601

वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार धनराशि।

* पिछले वर्षों की वित्तीय सहायता की धनराशि शामिल है।

अनुलग्नक एफ.7

**वर्ष 31.03.2023 को भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय/स्थानीय
शाखाओं से जुड़े संकाय सदस्य**

क्रमांक	क्षेत्रीय/स्थानीय शाखा नाम का नाम	संकाय सदस्यों के नाम
1.	असम	डॉ. श्यामली सिंह
2.	बिहार	डॉ. नुपूर तिवारी
3.	दिल्ली	डॉ. सुरेश मिश्रा
4.	गुजरात	डॉ. अशोक विशनदास
5.	हरियाणा	डॉ. नीतू जैन
6.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. साकेत बिहारी
7.	जम्मू-कश्मीर	डॉ. अशोक विशनदास
8.	झारखंड	डॉ. मनन द्विवेदी
9.	कर्नाटक	डॉ. सपना चड्ढा
10.	केरल	डॉ. पवन के. तनेजा
11.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	डॉ. कुसुम लता
12.	महाराष्ट्र	प्रो. विनोद के शर्मा
13.	मणिपुर	डॉ. सचिन चौधरी
14.	मेघालय	डॉ. रोमा देबनाथ
15.	मिजोरम	डॉ. अमित सिंह
16.	ओडिशा	डॉ. गदाधर महापात्र
17.	पुदुचेरी	डॉ. चारू मल्होत्रा
18.	पंजाब और चंडीगढ़ (यू.टी)	प्रो. के.के. पांडेय
19.	राजस्थान	डॉ. सुरेश मिश्रा
20.	तमिलनाडु	डॉ. ममता पठानिया
21.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डॉ. ममता पठानिया
22.	उत्तर प्रदेश	डॉ. सुरभि पांडेय
23.	उत्तराखंड	डॉ. वी.एन. आलोक
24.	पश्चिम बंगाल	डॉ. रोमा देबनाथ

अनुलग्नक एफ.8

संकाय और वरिष्ठ अधिकारी (दिनांक 31.03.2023 तक)

श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, आईएएस (सेवानिवृत्त) महानिदेशक

श्री अमिताभ रंजन, कुल सचिव

प्रोफेसर		
1.	प्रो. वी.के. शर्मा	आपदा प्रबंधन में प्रोफेसर
2.	प्रो. के.के. पाण्डेय	शहरी प्रबंधन में प्रोफेसर
3.	प्रो. सुरेश मिश्रा	लोक प्रशासन में प्रोफेसर (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता के साथ)
4.	प्रो. अशोक कुमार विशनदास	अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र में प्रोफेसर
5.	प्रो. वी.एन. आलोक	शहरी वित्त में प्रोफेसर
6.	प्रोफेसर चारु मल्होत्रा	ई-गवर्नेंस एवं आईसीटी में प्रोफेसर
7.	प्रो. नूपुर तिवारी	चेयर प्रोफेसर (डॉ. बी.आर. अम्बेडकर चेयर)
एसोसिएट प्रोफेसर		
1.	डॉ. कुसुम लता	शहरी और क्षेत्रीय योजना में एसोसिएट प्रोफेसर
2.	डॉ. सचिन चौधारी	लोक प्रशासन में एसोसिएट प्रोफेसर
3.	डॉ. नीतू जैन एसोसिएट	व्यवहार विज्ञान में प्रोफेसर
4.	डॉ. साकेत बिहारी	विकास अध्ययन में एसोसिएट प्रोफेसर
5.	डॉ. रोमा देबनाथ	अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में एसोसिएट प्रोफेसर
सहायक प्रोफेसर		
1.	डॉ. सपना चड्ढा	संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून में सहायक प्रोफेसर
2.	डॉ. ममता पठानिया	लोक प्रशासन में सहायक प्रोफेसर
3.	डॉ. श्यामली सिंह	पर्यावरण प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन में सहायक प्रोफेसर
4.	डॉ. गदाधर महापात्र	समाजशास्त्र में सहायक प्रोफेसर
5.	डॉ. मनन द्विवेदी	अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन में सहायक प्रोफेसर
6.	डॉ. पवन कुमार तनेजा	ऑपरेशन रिसर्च में सहायक प्रोफेसर
7.	डॉ. सुरभि पांडे	आईटी एवं ई-गवर्नेंस में सहायक प्रोफेसर
8.	डॉ. अमित कुमार सिंह	शहरी विकास में सहायक प्रोफेसर

प्रशासन		
1.	श्री मिथुन बरुआ	उप. कुलसचिव (शैक्षणिक सेवाएँ)
2.	श्री ओ. पी. चावला	उप. कुलसचिव (वित्त एवं प्रशासन)
3.	श्रीमती अल्का जिंदल	अधीक्षक (प्रशिक्षण)
4.	श्री एम.एस. बिष्ट	अधीक्षक (सदस्यता)
5.	श्री अनिल कुमार शर्मा	अधीक्षक (अप्पा)
प्रकाशन		
1.	सुश्री मेघना चुक्कथ	सहायक प्रकाशन अधिकारी
पुस्तकालय		
1.	श्री हुकम चंद यादव	कार्यवाहक लाइब्रेरियन
2.	श्रीमती मीना मिश्रा	प्रोफेशनल सहायक (सीनियर स्केल)
3.	श्री हेमन्त खरे	प्रोफेशनल सहायक (सीनियर स्केल)
4.	श्रीमती शक्ति चौहान	प्रोफेशनल सहायक (सीनियर स्केल)
5.	श्री नरेंद्र कुमार	प्रोफेशनल सहायक (सीनियर स्केल)
6.	श्रीमती सुनीता गौतम	प्रोफेशनल सहायक (सीनियर स्केल)
अनुसंधान समन्वय		
1.	श्री राकेश जोशी अधीक्षक	(आरसी यूनिट एवं सीयूएस)
रखरखाव		
1.	श्री के एस रंगा	अधिशासी अभियंता
2.	श्री अशोक शर्मा	विद्युत पर्यवेक्षक

अनुलग्नक एफ.9

शहरी अध्ययन केंद्र की गतिविधियां (अप्रैल 2022-मार्च 2022)

वर्ष 2022-23 के दौरान सीयूएस ने शीर्ष स्तर पर एक प्रबुद्ध मंडल (थिंक टैंक) और ज्ञान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप अनुसंधान, क्षमता निर्माण और सलाहकार सेवा की एक टाइपोलॉजी के माध्यम से अपनी पहुंच और कवरेज का विस्तार किया है। अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के अलावा, गतिविधियों में केंद्र, राज्यों और शहरों से संबंधित शहरी क्षेत्र के संस्थानों की क्षमता निर्माण और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के तहत कार्यक्रमों के कई सरकारी विभागों/एजेंसियों और अधिकारियों तक भारत सरकार के शहरी एजेंडे का विस्तार/साझा करना शामिल है।

शहरी अध्ययन केंद्र (सीयूएस) द्वारा की गई गतिविधियाँ:

- ए. 694 प्रतिभागियों के लिए 16 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ
- बी. भारत सरकार, राज्यों और यूएलबी के लिए 14 अनुसंधान और सलाहकार/ज्ञान केंद्र सेवाएँ।
- सी. प्रकाशन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ (त्रैमासिक जर्नल, पेपर, टीवी वार्ता/चर्चाएँ, सेमिनार में भागीदारी)

ए. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

सोलह घटनाओं में शामिल हैं:

- (I) नौ सम्मेलन/कार्यशालाएं, वेबिनार और समन्वय बैठकें, और
- (ii) शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर सात अनुकूलित और मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम,

सम्मेलन/कार्यशालाएं, वेबिनार और समन्वय बैठकें

तालिका-1 में दिए गए आठ आयोजनों में भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन और महानगरीय लचीलेपन (मेट्रोपॉलिटन रेंजिलिएंस): भारतीय और वैश्विक पर वेबिनार शामिल हैं। अमृत महोत्सव के अवसर पर शिक्षाविदों और अभ्यासकर्ताओं को अमृत काल के लिए 75-सूत्रीय शहरी एजेंडे के साथ 75 शोध पत्र साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 6-7 दिसंबर, 2022 को सम्मेलन आयोजित किया गया था। (बॉक्स-1) सम्मेलन में उद्घाटन और समापन सत्र के अलावा पूर्ण और 10 समानांतर/ब्रेकअवे सत्र भी थे, जिसमें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ विचार-विमर्श के लिए स्वर और दिशा तय करेंगे।

बॉक्स-1

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की मुख्य विशेषता

सम्मेलन का उद्घाटन माननीय सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार श्री मनोज जोशी, आईएएस द्वारा किया गया और माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जी ने समापन भाषण दिया। प्रो. ओम प्रकाश माथुर, गैर-निवासी वरिष्ठ फेलो, ग्लोबल सिटीजइंस्टीट्यूट, टोरंटो विश्वविद्यालय ने आधार व्याख्यान दिया। पूर्ण सत्र में सुश्री डी. थारा (आईएएस), अतिरिक्त सचिव, एमओएचयूए, सुश्री रूपा मिश्रा (आईएएस), संयुक्त सचिव, सुश्री पारुल अग्रवाल, कंट्री प्रोग्राम मैनेजर, भारत, यूएन हैबिटेट, श्री वी. सुरेश, पूर्व अध्यक्ष, हुडको, श्री चेतन वैद्य, पूर्व निदेशक, एसपीए, श्री हितेश वैद्य, निदेशक, एनआईयूए शामिल थे।

महानगरीय लचीलेपन (मेट्रोपॉलिटन रेंजिलिएंस) पर वेबिनार को सेंट्रल मैड्रिड के पूर्व मेयर प्रोफेसर पेद्रो ऑर्टिजने संबोधित किया और अध्यक्षता डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास (आईएएस) ने की।

तीन गोलमेज बैठकों में शहरी बुनियादी ढांचे और वित्त, भूमि प्रबंधन, दिल्ली हवाई अड्डे की सफल पीपीपी, सेंट्रल विस्टा परियोजना, मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार जैसे समकालीन प्रासंगिकता के विषय शामिल थे।

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार को सीयूएस द्वारा समर्थन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संयुक्त सचिव (एसबीएम-शहरी 2.0) के साथ एक आभासी गोलमेज बैठक भी आयोजित की गई।

तालिका-1 सम्मेलन/कार्यशालाएं, वेबिनार और समन्वय बैठकें

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	नगरपालिका सेवाओं के लिए यू-20 एजेंडा पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला	22-24 मार्च, 2023	67
2.	भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन	6-7 दिसंबर, 2022	147
3.	शहरी बुनियादी ढांचे और वित्त पर पैनल चर्चा	24-नवंबर-2022	40
4.	भूमि प्रबंधन पर गोलमेज	10 नवंबर, 2022	40
5.	पीपीपी की सफलता पर दिल्ली हवाई अड्डे पर विशेष गोलमेज- तब और अब (मुख्य वक्ता- श्री के. नारायण राव, समूह उप प्रबंध निदेशक, जीएमआर समूह)	29-सितंबर-2022	40
6.	सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विशेष गोलमेज (मुख्य वक्ता - डॉ. बिमल पटेल)	8-सितंबर-2022	52
7.	भारत में मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार पर तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला	5-7 सितंबर, 2022	11
8.	संयुक्त सचिव (एसबीएम) और उनकी टीम के साथ एसबीएम 2.0 में सीयूएस भूमिका पर वर्चुअल राउंड टेबल	5-मई-2022	10
9.	मेट्रोपॉलिटन रेजिलिएशन पर वेबिनार: भारत और वैश्विक	1-अप्रैल-2022	56

शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर अनुकूलित और मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

आठ कार्यक्रम शहरी सेवाओं, प्रशासन और कानूनी कौशल और संरचित अध्ययन यात्राओं जैसे विशिष्ट

विषयों पर डिजाइन, विकसित और वितरित किए गए थे। (तालिका-2 एवं बॉक्स-2)

- जम्मू और कश्मीर के यूएलबी के महापौरों, अध्यक्षों, वरिष्ठ पार्षदों और आयुक्त के लिए तीन कार्यक्रम।

बॉक्स-2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की मुख्य विशेषताएं

मुख्य अतिथि/संसाधन व्यक्तियों में माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, सुश्री डी. थारा, अपर सचिव, सुश्री शालिनी पांडे, निदेशक (एनयूएलएम) और श्री बिनय कुमार झा, निदेशक (एसबीएम), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. एस.एन. पांडे, प्रो. वी.के. धार, श्री आनंद टंडन, सीईओ, एनआईयूएम, हैदराबाद, श्री शैलेश पाठक, निदेशक और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, श्री पुष्कल उपाध्याय (आईडीएएस), वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, श्री पलाश श्रीवास्तव, डिप्टी सीईओ, आईआईएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, डॉ. ए.के. सेन, श्री राजीव शर्मा, संकाय, एचएसएमआई, श्री आर. श्रीनिवास, पूर्व वरिष्ठ नगर योजनाकार, टीसीपीओ इत्यादि शामिल थे।

दिल्ली, एनडीएमसी, एमसीडी में कम आय वाली आवास परियोजनाओं का फील्ड दौरा भी किया गया।

- स्मार्ट सिटी, एसबीएम, शहरी बुनियादी ढांचे, नगरपालिका वित्त पर चंडीगढ़ देहरादून और विशाखापट्टनम में तीन संरचित शहरी अध्ययन दौरें।
- प्रशासनिक और कानूनी मामलों पर सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

तलिका- 2

शहरी विकास और संबंधित मुद्दों पर अनुकूलित और मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का विशाखापट्टनम का शहरी अध्ययन दौरा	18-नवंबर-22	40
2.	शहरी शासन एवं प्रबंधन पर पांच दिवसीय कार्यक्रम	नवंबर, 2022	40
3.	श्रीनगर नगर निगम के लिए शहरी प्रशासन पर ईआर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम	अक्टूबर 19-21, 2022	19
4.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का देहरादून नगर निगम का शहरी अध्ययन दौरा	9-अक्टूबर-22	40
5.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का चंडीगढ़ नगर निगम का शहरी अध्ययन दौरा	7-अक्टूबर-22	40
6.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	25-27 मई, 2022	30
7.	जम्मू और कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शहरी शासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	11-13 मई, 2022	22

बी. भारत सरकार, राज्यों और यूएलबीएस के लिए अनुसंधान और सलाहकार/ज्ञान केंद्र सेवाएं

भारत सरकार, राज्यों और यूएलबीएस के लिए अनुसंधान और सलाहकार/ज्ञान केंद्र सेवाएं हिस्से के रूप में 14 शोध अध्ययन और तकनीकी प्रस्ताव, रिपोर्ट, दस्तावेज इत्यादि तैयार किए गए थे।

अनुसंधान

- जनकपुरी पश्चिम से राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश में आर.के. आश्रम कॉरिडोर तक डीएमआरसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन (अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत)।
- नई दिल्ली में 'गांव खानपुर, नई दिल्ली' में भूमि

अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत)।

- पीएमस्वनिधि- इक्विटी और विकास के लिए एक मॉडल।
- अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए ताजपुर खुर्द गांव में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)।
- सभापुर, शहादरा, नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)।
- शहरी आजीविका पर मोनोग्राफ।
- वर्षा जल संचयन में सामुदायिक गतिशीलता पर मोनोग्राफ: दिल्ली का एक केस अध्ययन।

(viii) शहरी मामलों पर भारत सरकार की पहल पर नियमित त्रैमासिक अनुसंधान। (नगरलोक: अप्रैल-जून, 2022, जुलाई-सितंबर, 2022 और अक्टूबर-दिसंबर, 2022)

(ix) जल आपूर्ति और स्वच्छता पर मध्य प्रदेश के इंजीनियरों के लिए टीएनए।

(x) भारत में जन केंद्रित शहरी शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए पूर्व-भूमिका की। मंत्रालयों/राज्यों और अन्य शहरी संस्थानों को सौंपे गए तकनीकी प्रस्ताव, जिन पर बातचीत चल रही है, उनमें शामिल हैं:

(xi) एसबीएम 2.0 (शहरी) के तहत सीयूएस/भा.लो.प्र.सं. में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) और गतिविधियों की स्थापना का प्रस्ताव।

(xii) भा.लो.प्र.सं. में एसबीएम 2.0-शहरी (एनआईआईईएस) पर स्वतंत्र व्यक्तिगत विशेषज्ञों के नेटवर्क के लिए प्रस्ताव और एसबीएम 2.0 में शहरी चुनिंदा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/आकांक्षी जिलों और पिछड़े यूएलबी के शहरों से पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण।

(xiii) एसबीएम-यू 2.0 के तहत विषय वस्तु विशेषज्ञों, मेंटरशिप कार्यक्रम और फोकस पिछड़े यूएलबी के लिए क्षमता निर्माण के लिए व्यावसायिक सहायता का प्रस्ताव।

(xiv) जम्मू-कश्मीर सरकार की के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला का प्रस्ताव।

भारत सरकार, राज्यों और यूएलबी के लिए सलाहकार/ज्ञान केंद्र सेवाएँ

(i) एलसीएमए, जम्मू-कश्मीर द्वारा गठित डल और अन्य झीलों पर बॉर पर विशेषज्ञ समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए इनपुट (चालू)।

(ii) श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित टीपी योजना के लिए इनपुट (जुलाई-अक्टूबर, 2022)

(iii) जम्मू, जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित टीपी योजना

के लिए इनपुट (जून-सितंबर, 2022)

(iv) जनवरी, 2023 में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन के लिए शहरी बुनियादी ढांचे और वित्तपोषण पर इनपुट।

(v) एमओएचयूए द्वारा सौंपे गए विशिष्ट कार्य

ए) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सौंपे गए आधार (कागजात पीएमएसवीएनिधि और एनयूएलएम) और तकनीकी कागजात।

बी) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण नीति तथा कार्यान्वयन पर आठ राज्यों को राज्य स्तरीय समर्थन

सी) संसद प्रश्नों के लिए इनपुट।

डी) विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर सीयूएस द्वारा भारत सरकार को आवधिक रिपोर्टिंग

ई) 26-27 सितंबर, 2022 को शहरी क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाना- जलवायु स्मार्ट शहरों की ओर बढ़ाना विषय पर एमओएचयूए द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में सीयूएस टीम की भागीदारी।

एफ) 28 सितंबर, 2022 को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जीआईजेड, एमओएचयूए और एनआईयूए द्वारा जलवायु क्षमताओं के लिए प्रशिक्षण बढ़ाने पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सीयूएस टीम की विशेष भागीदारी।

जी) 27 जनवरी, 2023 को जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर वेबिनार में भागीदारी

एच) एमओएचयूए के यू-20 आयोजन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों में भागीदारी

आई) एनआईयूए द्वारा आयोजित आईएसएसी-2022 पुरस्कार (थीम कोविड इनोवेशन अवार्ड्स) के मूल्यांकन के लिए विषयगत सलाह

जे) एमओएचयूए को राष्ट्रीय शहरी आपदा प्रबंधन अध्ययन के लिए इनपुट (3 फरवरी, 2023)

के) यू-20 शहर शेरपा बैठक में भागीदारी (9 फरवरी, 2023)

सी. प्रकाशन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ (त्रैमासिक जर्नल, डाइजेस्ट का विशेष अंक, पेपर, टीवी वार्ता, सेमिनार में भागीदारी)

सीयूएस को विभिन्न प्रकाशनों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का श्रेय प्राप्त है।

प्रकाशन

- ए) नगरलोक का प्रकाशन (अक्टूबर-दिसंबर, 2022)
- बी) भारत की संघीय संरचना में शहरी स्थानीय सरकारों पर सीएलजीएफ जर्नल में पेपर: स्थिति और अवसर (कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ लोकल गवर्नेंस, अंक 27 2022, 21 दिसंबर, 2022)
- सी) मोरबी से सीखें लेख: स्थानीय सरकार को नियत करें पर लेख (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 नवंबर, 2022)
- घ) पीएमस्वनिधि पर नीति समीक्षा लेख- इक्विटी और विकास के लिए एक मॉडल (शेल्टर, वॉल्यूम 23 नंबर 2, अक्टूबर, 2022)
- ई) नगरलोक का प्रकाशन (जुलाई-सितंबर, 2022)
- एफ) नगरलोक का प्रकाशन (अप्रैल-जून, 2022)
- जी) संरचनात्मक सुधारों के लिए एमसीडी के एकीकरण पर लेख (द पायनियर, 10 मई, 2022)
- एच) नगरलोक का प्रकाशन (जनवरी-मार्च, 2022)
- आई) फास्टेस्ट मूवर इंडियन मेगासिटी-2021 में अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल: प्रक्रिया और सबक
- जे) सूचीबद्ध शहरों के विकास में हृदय का आकलन

अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

- 1. बिपार्ड, गया में शहरी विकास पर बिहार के पीसीएस अधिकारियों के लिए व्याख्यान इनपुट (13-15 फरवरी, 2023)।
- 2. आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के प्रमुख सचिवों की विशेष बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे और निवेश पर प्रस्तुति (26 नवंबर, 2022)।

- 3. एमओएचयूए के विशिष्ट मुद्दों पर चार पेपर, टिप्पणियाँ और अवलोकन
- 4. वर्तमान शहरी क्षेत्र के मुद्दों पर दैनिक समाचार पत्रों में पांच संकाय पत्र प्रकाशित
- 5. नगरलोक के संपादकीय बोर्ड की बैठक 30 सितंबर, 2022 को आयोजित की गई।
- 6. सीयूएस संकाय ने राज्यसभा और लोकसभा टीवी में (i) नोएडा सुपरटेक ट्विन-टावर विध्वंस, (ii) जीवन सुगमता सूचकांक, और (iii) शहरी बजट-2023-24 पर टीवी चर्चाओं में भाग लिया।
- 7. संकाय सदस्यों को श्रीनगर में टीपी योजना के विकास पर जम्मू-कश्मीर सरकार की विशेषज्ञ समिति, हुडको की एचएसएमआई की पुनर्गठन समिति, आईटीपीआई में परीक्षकों के बोर्ड, एनसीआर योजना बोर्ड, एएमडीए (नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों का संघ) और नगरलोक, एशियन रिव्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड वगैरह में शामिल किया गया है।
- 8. सीयूएस फैंकल्टी को हुडको बेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड-2023 के लिए जूरी में नामांकित किया गया है।
- 9. इसके अलावा, सीयूएस संकाय ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (एचएसएमआई), स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए संकाय इनपुट भी प्रदान किए। इन कार्यक्रमों ने आगे प्रसार के लिए सिखाने और सीखने का अवसर प्रदान किया।
- 10. संकाय ने समसामयिक शहरी मुद्दों पर कई सेमिनारों/कार्यशालाओं और टीवी चर्चाओं में सहभागिता की।

अनुलग्नक एफ.10

संकाय सदस्यों/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भुगतान किए गए
मानदेय एवं वेतन का विवरण (2022-23)

क्र.सं.	नाम	वेतन	मानदेय	कुल
1	श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी	2376000	0	2376000
2	श्री अमिताभ रंजन	3071192	0	3071192
3	प्रो. वी.के. शर्मा	1660169	39831	1700000
4	प्रो. के.के. पांडे	2040000	100139	2140139
5	प्रो. सुरेश मिश्रा	2000000	0	2000000
6	प्रो. अशोक कुमार विशनदास	2000833	113054	2113887
7	प्रो. वी.एन. आलोक	3231389	0	3231389
8	प्रो. चारु मल्होत्रा	2808067	0	2808067
9	प्रो. नूपुर तिवारी	3334332	0	3334332
10	डॉ. कुसुम लता	3073590	156356	3229946
11	डॉ. नीतू जैन	3322131	0	3322131
12	डॉ. सचिन चौधरी	3394312	100139	3494451
13	डॉ. साकेत बिहारी	2730154	785515	3515669
14	डॉ. रोमा देबनाथ	3176287	63868	3240155
15	डॉ. सपना चड्ढा	2198898	205265	2404163
16	डॉ. श्यामली सिंह	1845069	30391	1875460
17	डॉ. ममता पठानिया	1897776	0	1897776
18	डॉ. पवन कुमार तनेजा	2897076	63868	2960944
19	डॉ. गदाधर महापात्र	1737860	64132	1801992
20	डॉ. मनन द्विवेदी	2002745	0	2002745
21	डॉ. सुरभि पांडे	1289831	259116	1548947
22	डॉ. अमित कुमार सिंह	1056000	136088	1192088
23	श्री मिथुन बरुआ	2007232	0	2007232
24	श्री ओम प्रकाश चावला	692500	0	692500
	कुल	55843443	2117762	49814281

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सदस्यों के लिए

योग्य राय

हमने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ('आईआईपीए') के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक की तुलनपत्र और समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का विवरण, प्राप्तियां और भुगतान, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल हैं।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार सेक्शन में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण यह जानकारी देते हैं साथ में वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 तक संस्थान की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दर्शाते हैं और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय और प्राप्तियां और भुगतान का विवरण देते हैं। (आईसीएआई)

योग्य राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण सेक्शन के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इकाई से स्वतंत्र हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि,

- क) प्राप्त अनुदान/स्वामित्व वाले योगदान से प्राप्त परिसंपत्तियों के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने की आवश्यकता है। चालू वर्ष में प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। इसके अभाव में, यदि कोई विसंगति हो तो हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। हमारा सुझाव है कि प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन के चक्र के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए।
- ख) वर्ष के दौरान, विशेष रूप से उन वस्तुओं के उपयोग के उद्देश्य से जिनके लिए यह आईआईपीए स्थापित किया गया है, आईआईपीए आरक्षित निधि और अनुसंधान अक्षय निधि में क्रमशः रु.5.52 करोड़ और रु.61.37 लाख हैं।
- ग) लंबे समय से किराए के मद में एनआईडीएम से रु. 2.17 करोड़ की वसूली होनी है। इसे यथाशीघ्र पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रबंधन द्वारा संदिग्ध वसूली का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।
- घ) रु.62.74 लाख की वसूली योग्य अनुदान की आरंभिक शेष धनराशि निम्नलिखित कार्यक्रम में प्रदर्शित की जा रही हैं। इस धनराशि को जल्द से जल्द वसूली किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

अनुदान/कार्यक्रम से संबंधित है	मामलों की संख्या	प्राप्य अनुदान (लाख रुपये में)
अन्य कार्यक्रम	2	15.43
अन्य अनुसंधान परियोजनाएँ	28	42.70
कुल		58.13

- ड) आयकर कार्यालय से कर की पर्याप्त धनराशि वसूली योग्य है। हमारा सुझाव है कि टीडीएस की कम दर के लिए आयकर विभाग से मंजूरी ली जानी चाहिए।
- च) वर्तमान परिसंपत्तियों में 'मैसर्स ट्रेवियनस्पायर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड' से प्राप्त 46.61 लाख रुपये शामिल हैं। इस धनराशि का भुगतान 45वीं एपीपीपीए विदेश यात्रा के कारण किया गया था जो कि कोविड-19 महामारी के कारण रद्द हो गई थी, इसकी जांच और समायोजन की आवश्यकता है।
- छ) वर्तमान परिसंपत्ति में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 63.72 लाख रुपये की प्राप्य धनराशि शामिल है। इसे यथाशीघ्र पुनर्प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आयु वर्ग	मात्र (लाख में)
2016-17 तक	32.65
2018-19 के लिए	28.41
2020-21 के लिए	2.66
कुल योग	63.72

- ज) यूको बैंक में प्राप्त 160 लाख रुपये के कुल क्रेडिट को बैंक द्वारा दिए गए क्रेडिट की प्रकृति के अभाव में वित्तीय पुस्तकों में नहीं माना गया है।
- झ) राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई) आईआईपीए और एनटीआरआई के बीच हुए किराया समझौते के अनुसार किराए का भुगतान नहीं कर रहा है। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़े हुए हिस्से से संबंधित कुल बकाया 35.83 लाख रुपये और 79.85 लाख रुपये है।

सुझाव

- क) अपरिवर्तित शेष की यथाशीघ्र समीक्षा की जानी चाहिए।
- ख) जीएसटी से दावा योग्य जीएसटी इनपुट क्रेडिट को जीएसटी पोर्टल के अनुसार उपलब्ध जीएसटी इनपुट क्रेडिट के साथ मिलान किया जाना चाहिए।
- ग) एआईएस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों का समय-समय पर मिलान वित्तीय पुस्तकों के साथ किया जाना चाहिए।
- घ) सभी खातों के लिए वर्ष के अंत में बैंक बैलेंस प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होता है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में इकाई को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के

आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन अथवा तो इकाई को समाप्त करने अथवा बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, अथवा ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

जिन पर शासन का प्रभार है, वे इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा।

गलतबयानी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यद्विगत रूप से अथवा समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- ii) हमारी राय में, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाता (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) रखी गई हैं।
- iii) इन रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलनपत्र तथा प्राप्तियां और भुगतान खाते, बही खाता (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) के अनुरूप हैं।
- iv) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर नोट्स (अनुसूची-बी) के साथ पढ़े गए उक्त खाते आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं : -

क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2023 तक निधि के मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति); और

ख) आय और व्यय के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटा (वित्तीय प्रदर्शन)।

ग) प्राप्ति और भुगतान के मामले में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए धन प्रवाह।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट एफआरएन नंबर 00257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल भागीदार

एम. नं. 083899

16 डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

यूडीआईएन : 23083899बीजीएक्सयूजीए4719

दिनांक : 22/09/2023

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 तक तुलनपत्र

	अनुसूची	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
देयताएं			
परिसंपत्ति निधि	1	22,81,92,609	17,66,93,888
परिसंपत्ति निधि एफसीआरए	1	-	8,42,449
संचित अधिशेष (घाटा)		(1,38,97,42,305)	(1,40,13,75,355)
सदस्यता निधि सहित पूंजीगत निधि	2	20,80,48,370	12,69,36,658
अप्रयुक्त अनुदान	3	21,29,35,902	18,40,54,869
- सामान्य निधि	21,15,29,447		
- विदेशी निधि	14,06,455		
प्रावधान :			
- देय उपदान		6,85,00,000	7,17,00,000
- देय छुट्टी नकदीकरण		7,04,00,000	6,62,00,000
- पेन्शन देय		1,45,69,00,000	1,43,35,00,000
वर्तमान देनदारियाँ	4	6,36,90,070	9,84,62,813
कुल		91,89,24,646	75,70,15,322
परिसंपत्ति			
स्थायी परिसंपत्ति निधि- अनुदान में से (सकल)	5	22,81,92,609	17,66,93,888
स्थायी परिसंपत्ति निधि-स्वयं निधि	5	56,80,742	44,46,397
परिसंपत्ति निधि एफसीआरए	5	-	8,42,449
निवेश	6	34,22,40,506	26,91,28,057
अनुदान प्राप्य	3	5,36,42,090	5,15,37,040
वर्तमान परिसंपत्ति	7	19,84,89,880	14,26,67,929
नकद एवं बैंक शेष	7	9,06,78,819	11,16,99,562
कुल		91,89,24,646	75,70,15,322

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं नोट्स

13

अनुसूचियाँ 1 से 13 खातों का अभिन्न अंग हैं

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,

पंचशील पार्क, शिवालिंक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

यूडीआईएन नंबर 23083899बीजीएक्सयूजीए4719

दिनांक : 22/09/2023

स्थान : नई दिल्ली

कार्यकारी परिषद के लिए

एस.एन. त्रिपाठी

महानिदेशक

(सदस्य सचिव)

के.के.पांडेय

(सदस्य-कार्यकारी

परिषद)

अमिताभ रंजन

कुलसचिव

(मुख्य लेखा

अधिकारी)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

	अनसूची	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
आय			
डीओपीटी से सहायता अनुदान - वेतन		10,99,93,000	11,20,00,000
डीओपीटी से सहायता अनुदान-सामान्य		9,00,00,000	8,25,50,000
सदस्य सदस्यता	8	12,03,987	8,62,922
प्रकाशनों की बिक्री		8,72,219	3,28,250
ओवरहेड सहित अनुसंधान कार्यक्रमों से शुद्ध आय			
प्रभार		1,59,46,884	2,28,67,235
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्क		9,44,68,841	6,10,98,213
अन्य कमाई :			
- किराया आय	10	7,11,72,349	8,94,15,983
- विविध प्राप्तियां	9	1,27,90,777	55,08,519
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क प्राप्य		3,82,48,857	28,15,000
कुल		43,46,96,914	37,74,46,122
व्यय			
वेतन एवं भत्ते	11	11,47,30,787	1,30,68,187
कैम्पस रखरखाव	12	3,90,25,842	2,37,90,213
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	13	1,05,04,574	51,69,104
पुस्तकालय, आवधिक और बाइडिंग शुल्क		15,59,993	3,34,156
प्रशिक्षण कार्यक्रम		6,80,32,042	5,04,49,396
प्रकाशन		8,47,432	6,95,775
शाखाएँ प्रचार गतिविधियाँ		10,69,601	8,93,183
सीजीएचएस को भुगतान की गई धनराशि		14,44,592	50,86,808
मूल्यहास	5	13,16,994	8,31,665
पेंशन	11	8,31,00,000	7,88,00,000
उपदान	11	64,70,553	60,09,597
छुट्टी नकदीकरण	11	31,30,472	35,15,710
निवेश पर भुगतान किए गए प्रीमियम का परिशोधन		34,90,874	30,39,118
दरें एवं कर		30,216	-
आईआईपीए आरक्षित निधि		5,52,33,959	3,35,54,624
अनुसंधान अक्षय निधि		61,37,107	37,28,292
पूर्व अवधि/जीएसटी भुगतान		25,38,826	-
दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति दायित्व			
उपदान	11	(32,00,000)	33,00,000
छुट्टी नकदीकरण	11	42,00,000	46,00,000
पेंशन व्यय	11	2,34,00,000	21,36,00,000
		42,30,63,864	55,04,65,828
वर्ष के लिए व्यय पर आय का आधिक्य		1,16,33,050	(17,30,19,454)
पिछले वर्ष के व्यय से अधिक आय		(1,40,13,75,355)	(1,22,83,55,901)
शेष धनराशि को तुलनपत्र में अग्रेषित किया गया		(1,38,97,42,305)	(1,40,13,75,355)
खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं नोट्स	13		

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता

	अनुसूची	वर्ष 2022-23 (₹)	वर्ष 2021-22 (₹)
प्राप्तियां			
आरंभिक जमा :			
नकद एवं बैंक शेष	7	11,16,99,562	5,30,41,651
रखरखाव अनुदान और आंतरिक प्राप्तियाँ	ए	45,26,02,520	37,93,89,533
ऋण, अग्रिम और अन्य प्राप्तियाँ	बी	35,81,84,435	44,77,31,216
अनुसंधान परियोजनाओं आदि के लिए अनुदान, सहायता पूंजी अनुदान को छोड़कर	3	27,69,23,716	15,40,02,658
	कुल	1,19,94,10,233	1,03,41,65,058
भुगतान			
रखरखाव अनुदान और आंतरिक प्राप्तियों के प्रति व्यय	ए	45,25,43,710	37,96,23,869
निधि, जमा और अग्रिम से भुगतान	बी	40,90,84,660	38,81,18,180
अनुसंधान परियोजनाओं आदि के लिए अनुदान के विरुद्ध व्यय	3	24,71,03,043	15,47,23,447
जमा शेष :			
नकद एवं बैंक शेष	7	9,06,78,819	11,16,99,562
	कुल	1,19,94,10,233	1,03,41,65,058

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,
पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017
यूडीआईएन नंबर 23083899बीजीएक्सयूजीए4719
दिनांक : 22/09/2023
स्थान : नई दिल्ली

कार्यकारी परिषद के लिए

एस.एन. त्रिपाठी
महानिदेशक
(सदस्य सचिव)

के.के.पांडेय
(सदस्य-कार्यकारी
परिषद)

अमिताभ रंजन
कुलसचिव
(मुख्य लेखा अधिकारी)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-1

परिसंपत्ति राशि

	01.04.2022 तक शेष धनराशि (₹)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (₹)	वर्ष के दौरान समायोजन/उपयोग (₹)	31.03.2023 तक शेष धनराशि (₹)
आईआईपीए कोर	14,76,04,526	5,80,07,405	-	20,56,11,931
सीयूएस	47,01,622	1,91,850	-	48,93,472
एपीपीपीए	1,22,53,625	12,51,360	91,500	1,34,13,485
सीसीएस	31,54,902	-	11,11,136	20,43,766
एनसीएच	82,95,387	-	82,95,387	-
नमामि गंगे	6,83,826	4,12,770	-	10,96,596
एनटीआरआई	-	11,33,359		11,33,359
उप योग	17,66,93,888	6,09,96,744	94,98,023	22,81,92,609
एफसीआरए	8,42,449	-	8,42,449	-
उप योग	8,42,449	-	8,42,449	-
कुल	17,75,36,337	6,09,96,744	1,03,40,472	22,81,92,609

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-2

पूँजीगत राशि

	01.04.2022 तक शेष धनराशि	ब्याज/ अंशदान	उपयोग की गई राशि	31.03.2023 तक शेष धनराशि
(ए)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	1,10,673	7,405	1,095	1,16,983
भूपेन्द्र हूजा मेमोरियल निधि	51,001	4,397	1,191	54,207
परामर्श सहायता निधि	16,78,602	1,21,137	66,848	17,32,891
आईआईपीए रिजर्व निधि	3,41,23,887	6,04,07,158	4,79,578	9,40,51,467
अवसंरचना विकास निधि	5,31,10,535	55,49,795	10,62,260	5,75,98,070
एसटीडीआर पर ब्याज	-	74,42,654	5,25,559	69,17,095
नायदुम्मा मेमोरियल साइंस फाउंडेशन	11,97,459	41,374	5,048	12,33,785
प्रो. एस.सरोजा मेमोरियल निधि	5,99,687	-	-	5,99,687
अनुसंधान अक्षयनिधि	90,77,125	77,81,404	85,070	1,67,73,459
श्रीमती कुसुम ताई शंकर राव चव्हाण स्मारक निधि	1,67,122	7,122	-	1,74,244
कर्मचारी हितैषी निधि	5,78,694	37,749	13,405	6,03,038
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार	1,08,960	9,956	10,406	1,08,510
पी.के. उमाशंकर स्मारक निधि	11,99,109	88,895	2,190	12,85,814
यू.सी. अग्रवाल मेमोरियल फंड	24,46,172	1,65,000	12,785	25,98,387
उप-योग	10,44,49,026	8,16,64,046	22,65,435	18,38,47,637
(बी)				
(सदस्यता पूँजी निधि)				
कॉर्पोरेट सदस्यता पूँजी निधि	40,56,485	1,70,414	3,28,872	38,98,027
आजीवन सदस्यता पूँजी निधि	1,84,31,146	28,44,463	9,72,903	2,03,02,706
उप-योग	2,24,87,631	30,14,877	13,01,775	2,42,00,733
कुल	12,69,36,657	8,46,78,923	35,67,210	20,80,48,370

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-3

अप्रयुक्त अनुदान शेष

	01.04.2022 तक अप्रयुक्त शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ (₹)	कुल (₹)	भुगतान/ समायोजन (₹)	वर्ष के लिए देय (₹)	31.03.2023 तक अप्रयुक्त (₹)
(ए) सामान्य निधि						
शहरी अध्ययन केंद्र के लिए आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय से अनुदान (रु.166390/- की प्राप्त विविध प्राप्तियों सहित) (अनुलग्नक-2 देखें)	(114)	3,23,66,390	3,23,66,276	3,06,21,520	17,44,471	285
एपीपीपीए	6,66,00,612	2,86,51,120	9,52,51,732	68,86,387	1,35,794	8,82,29,551
उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	21,22,124	-	21,22,124	-	-	21,22,124
सीसीएस फेज-II (प्रकाशन सहित)	(92,66,779)	-	(92,66,779)	43,71,948	-	(1,36,38,727)
उपभोक्ता अध्ययन केंद्र (योजना)	11,67,393	-	11,67,393	-	-	11,67,393
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	66,593	-	66,593	-	-	66,593
आईसीजीआरएस-एनसीएच	(1,69,97,978)	1,56,15,864	(13,82,114)	1,16,61,972	-	(1,30,44,086)
पूँजीगत सहायता अनुदान	-	12,01,00,000	12,01,00,000	12,01,00,000	-	-
जनजातीय अनुसंधान एवं अन्वेषण केंद्र (सीओटीआरईएक्स)	29,75,001	-	29,75,001	1,63,059	-	28,11,942
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई)	(15,74,834)	2,52,32,099	2,36,57,265	1,15,19,924	91,309	1,20,46,032
एपीपीपीए के विदेश/क्षेत्र दौरों के लिए अन्य अनुदान	3,56,98,869	86,00,000	4,42,98,869	61,09,728	-	3,81,89,141
अन्य कार्यक्रम	(21,12,519)	1,42,49,157	1,21,36,638	1,03,96,445	2,86,821	14,53,372
फैलोशिप के लिए	4,98,678	1,45,000	6,43,678	5,23,871	-	1,19,807
आईसीएसएसआर से अनुदान						
अन्य अनुसंधान परियोजनाएँ	5,07,84,864	3,17,56,771	8,25,41,635	4,38,66,623	7,86,295	3,78,88,717
अनुसंधान-1 परियोजनाएं	4,75,213	-	4,75,213	-	-	4,75,213
कुल ए :	13,04,37,123	27,67,16,401	40,71,53,524	24,62,21,477	30,44,690	15,78,87,357
जोड़ें : डेबिट बैलेस	5,15,37,040	-	-	-	-	5,36,42,090
यानी अनुदान प्राप्य :						
31.03.2022 तक अप्रयुक्त अनुदान शेष :	18,19,74,163	27,67,16,401	40,71,53,524	24,62,21,477	30,44,690	21,15,29,447
(बी) ब्याज सहित विदेशी अनुदान						
कुल योग ए+बी	18,40,54,869	27,69,23,716	40,94,41,545	24,71,03,043	30,44,690	21,29,35,902

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-4

चालू देयताएँ

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
कैंटीन ठेकेदार/मेस शुल्क	1,95,940	1,33,557
सहायक स्टाफ और संकाय को देय धनराशि	86,607	23,416
विविध लेनदार	16,47,268	14,18,145
अन्य देनदारियां :		
एल एंड डीओ और कैंपस रखरखाव को देय	99,70,581	79,41,572
परियोजनाओं से संबंधित देनदारियां	1,25,06,132	1,03,12,038
अन्य	1,75,65,211	4,70,61,839
अन्य जमा	26,49,408	23,00,762
व्यय देय	1,39,44,351	1,54,41,095
शुल्क एवं कर (सेवाकर/जीएसटी/टीडीएस)	51,24,572	1,38,30,389
कुल	6,36,90,070	9,84,62,813

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-5

स्थायी परिसंपत्तियाँ

	01.04.2022 तक लागत (₹)	परिवर्धन (₹)	कम बिक्री/ समायोजन (₹)	मूल्यहास (₹)	31.3.2023 तक लागत (₹)
ए) अनुदान से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियाँ					
भूमि एवं भवन	4,22,79,424	2,46,92,253	1,06,73,723	-	5,62,97,954
फर्नीचर तथा जुड़नार	2,11,85,668	96,45,616	-	-	3,08,31,284
ए.सी. उपकरण एवं वाटर कूलर	42,04,417	60,52,481	-	-	1,02,56,898
फिल्म प्रोजेक्टर और स्टेज उपकरण	49,45,394	-	-	-	49,45,394
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	1,81,12,226	23,43,883	-	-	2,04,56,109
छात्रवास एवं भोजनालय उपकरण	24,93,671	-	-	-	24,93,671
कार्यालय उपकरण	2,69,72,049	-	-	-	2,69,72,049
डीजी सेट	-	92,12,835	-	-	92,12,835
आंतरिक संवाद	19,75,935	-	-	-	19,75,935
पुस्तकालय उपकरण	26,85,529	-	-	-	26,85,529
लाइब्रेरी पुस्तकें (कोर)	2,27,50,213	1,29,073	-	-	2,28,79,286
सौर परिवार	-	31,35,520	-	-	31,35,520
डिजिटलीकरण (ऑडियो और वीडियो)	-	1,37,29,527	-	-	1,37,29,527
उप योग	14,76,04,526	6,89,41,188	1,06,73,723	-	20,58,71,991
सीयूएस - फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	30,78,119	1,91,850	-	-	32,69,969
सीयूएस - लाइब्रेरी पुस्तकें	16,23,503	-	-	-	16,23,503
उप योग	47,01,622	1,91,850	-	-	48,93,472
एपीपीपीए - लाइब्रेरी पुस्तकें	43,07,273	-	-	-	43,07,273
एपीपीपीए - फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	79,46,352	12,51,360	3,51,560	-	88,46,152
उप योग	1,22,53,625	12,51,360	3,51,560	-	1,31,53,425
सीसीएस - फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	17,44,265	-	-	-	17,44,265
सीसीएस- लाइब्रेरी पुस्तकें	2,99,501	-	-	-	2,99,501
एनसीएच - फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	94,06,523	-	94,06,523	-	-
उप योग	1,14,50,289	-	94,06,523	-	20,43,766
नमामि गंगे-इंफ्रास्ट्रक्चर/कार्यालय उपकरण	6,83,826	4,12,770	-	-	10,96,596
एनटीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर	-	11,33,359	-	-	11,33,359
उप योग	6,83,826	15,46,129	-	-	22,29,955
महायोग	17,66,93,888	7,19,30,527	2,04,31,806	-	22,81,92,609

	01.04.2022 तक लागत (₹)	परिवर्धन (₹)	कम बिक्री (₹)	मूल्यहास (₹)	31.3.2023 तक लागत (₹)
बी) स्थायी परिसंपत्तियां-स्वयं निधि					
फर्नीचर, फिक्स्चर, ए.सी. उपकरण आदि।	9,30,606	-	-	93,060	8,37,546
डेटा प्रोसेसिंग उपकरण	4,11,427	12,94,280	-	6,00,038	11,05,669
कार्यालय उपकरण	17,51,712	12,57,059	-	4,20,998	25,87,773
वाहन	13,52,652	-	-	2,02,898	11,49,754
कुल	44,46,397	25,51,339	-	13,16,994	56,80,742
महा योग एबी	18,11,40,285	7,44,81,866	2,04,31,806	13,16,994	23,38,73,351
सी) स्थायी परिसंपत्तियां- एफसीआरए					
एफसीआरए - फर्नीचर, फिक्स्चर और कार्यालय उपकरण	8,42,449	-	8,42,449	-	-
उप योग	8,42,449	-	8,42,449	-	-
महा योग	18,19,82,734	7,44,81,866	2,12,74,255	13,16,994	23,38,73,351

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-6

निवेश

	01.04.2022 तक शेष धनराशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान भुनाया गया	31.03.2023 तक शेष धनराशि
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	1,00,058	58,095	53,747	1,04,406
भूपेन्द्र हूजा मेमोरियल निधि	41,656	43,735	41,656	43,735
परामर्श सहायता निधि	17,06,773	17,29,061	16,44,688	17,91,146
कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी निधि	38,57,665	4,89,210	4,65,955	38,80,920
अवसरचर्चा विकास निधि	5,16,14,379	3,33,89,477	3,03,65,054	5,46,38,802
जीवन पूंजी सदस्यता निधि	1,56,29,300	21,69,472	1,61,416	1,76,37,356
नायुदुम्मा मेमोरियल साइंस फाउंडेशन	8,23,243	-	-	8,23,243
प्रो. एस. सरोजा मेमोरियल निधि	5,00,000	-	-	5,00,000
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	1,84,32,603	42,33,240	17,07,998	2,09,57,845
श्रीमती कुसुम ताई चव्हाण मेमोरियल निधि	1,41,046	-	-	1,41,046
कर्मचारी हितैषी निधि	4,37,379	3,17,050	3,01,785	4,52,644
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार निधि	96,868	26,968	24,417	99,419
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल निधि	11,14,419	1,20,129	1,14,419	11,20,129
यू.सी. अग्रवाल स्मारक निधि	22,89,010	-	-	22,89,010
यू.सी.ओ के साथ एफडीआर	13,08,43,658	15,43,00,805	13,08,43,658	15,43,00,805
आईआईपीए रिजर्व फंड निवेश	4,15,00,000	4,19,60,000	-	8,34,60,000
कुल	26,91,28,057	23,88,37,242	16,57,24,793	34,22,40,506

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-7

वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
विविध देनदार		
आयोजित टीपी से प्राप्य धनराशि	3,89,60,413	1,36,99,673
अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए ईएमडी	1,02,44,800	45,42,200
उप योग	4,92,05,213	1,82,41,873
अन्य परिसंपत्तियां		
प्राप्य टीडीएस/टीसीएस	2,35,43,343	1,65,04,621
जीएसटी/जीएसटी प्राप्य पर टीडीएस	2,91,312	26,57,154
कर्मचारियों/विक्रेताओं को ऋण एवं अग्रिम	48,19,363	32,23,861
जमा (बीएसईएस, डीडीए आदि के साथ) और अन्य प्राप्य	17,94,249	6,42,210
एनआईडीएम से प्राप्य किराया (20%)	2,17,37,800	2,17,37,800
एफडी/बॉन्ड पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	41,97,765	19,25,011
अग्रिम कर	93,01,187	93,01,187
पूर्वदात बीमा	59,693	42,072
प्रीपेड व्यय/निवेश पर प्रीपेड	1,12,17,221	1,01,36,743
प्राप्य धनराशि		
सी.पी. निधि	97,85,000	97,85,000
प्राप्य किराया	4,88,65,989	4,24,79,836
प्राप्य जीएसटी	89,00,101	13,21,592
अन्य	47,71,644	46,68,969
उप योग	14,92,84,667	12,44,26,056
नकद एवं बैंक शेष (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)		
कैश इन हैंड	-	-
अग्रदाय राजस्व स्टाम्प	200	200
उप योग	200	200
अनुसूचित बैंकों में बैलेंस		
यूको बैंक के चालू खातों में	15,10,182.00	25,07,683
यूको बैंक बचत खाता	5,99,19,562	9,85,20,982
भारतीय स्टेट बैंक	2,62,546	2,62,547
यूको बैंक-एफसीआरए - बचत खाता	14,06,455	20,80,706
यूको बैंक पीएफएमएस खाता	7,64,461	6,00,935
यूको बैंक परियोजना खाता	16,30,386	15,60,414
यूको बैंक-उपभोक्ता पीएफएमएस खाता	33,43,872	30,76,821
यूको बैंक-सीयूएस पीएफएमएस खाता	2,83,668	1,48,036
यूको बैंक-एनटीआरआई पीएफएमएस खाता	1,77,64,646	2,06,147
यूको बैंक-केआरसी पीएफएमएस खाता	27,92,641	27,35,091
यूको बैंक-सीएनए होल्डिंग खाता	10,00,200	-
उप योग	9,06,78,619	11,16,99,362
कुल	9,06,78,819	11,16,99,562
महा योग	28,91,68,699	25,43,67,491

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-8

सदस्यता अंशदान/सदस्यता निधि पर ब्याज

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
सब्स.-एसोसिएट	8,800	15,200
सब्स.-कॉर्पोरेट	40,000	30,000
सब्स.-विद्यार्थी सदस्यता	28,200	7,200
सब्स.-साधारण	16,100	6,400
ब्याज पर :		
कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी कोष	1,70,414	2,04,122
आजीवन सदस्यता पूंजी निधि	9,40,473	6,00,000
कुल	12,03,987	8,62,922

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-9

विविध प्राप्तियाँ

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
ब्याज पर :		
- अल्पावधि जमा	85,75,656	22,81,927
अन्य प्राप्तियाँ	4,22,931	16,03,686
सेवा शुल्क	32,35,240	10,46,706
सदस्यता प्रपत्रों की बिक्री	4,500	6,000
सीजीएचएस वसूली	5,52,450	5,70,200
कुल	1,27,90,777	55,08,519

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-10

किराए से आय

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
छात्रावास से किराया	1,26,89,757	41,81,826
आवासीय क्वार्टरों से किराया	2,77,750	2,70,779
एनटीआरआई (मोटा) से किराया	5,60,72,250	7,90,04,250
सीसीपीए से किराया	13,99,860	53,87,339
यूको बैंक से किराया	3,84,732	3,84,732
अन्य किराया	3,48,000	1,87,057
कुल	7,11,72,349	8,94,15,983

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-11

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
ए) वेतन और भत्ते - कोर		
लेखा एवं पेन्शन प्रकोश्ट	76,26,180	80,79,146
प्रशासन	2,00,49,745	2,09,93,923
कंप्यूटर केंद्र	11,99,771	13,36,896
संकाय और संबद्ध कर्मचारी	3,57,84,385	3,54,99,810
छात्रावास	8,07,338	7,47,859
पुस्तकालय	1,41,46,910	1,31,59,504
रखरखाव	1,18,82,860	1,25,38,287
सदस्यता	37,19,457	34,68,332
शैक्षणिक गतिविधियों का कार्यालय	1,30,50,725	1,15,06,181
प्रकाशन	64,00,251	57,38,249
आर एंड सी इकाई	63,165	-
	11,47,30,787	11,30,68,187
बी) सेवानिवृत्ति लाभ	10,97,70,553	30,98,25,307
कुल (ए+बी)	22,45,01,340	42,28,93,494

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-12

कैम्पस रखरखाव

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
मरम्मत एवं रखरखाव	84,54,830	22,11,962
छात्रावास सामान्य रखरखाव	25,45,838	15,64,330
किराया, दरें और कर	61,93,613	10,20,558
पानी और बिजली शुल्क	53,05,833	51,90,588
सुरक्षा व्यवस्था	44,66,383	42,40,616
हाउसकीपिंग शुल्क		
छात्रावास	47,12,769	37,48,627
मुख्य भवन	73,46,576	58,13,532
कुल	3,90,25,842	2,37,90,213

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-13

प्रशासनिक एवं विविध व्यय

	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
यात्रा खर्च		
1. संकाय/संस्थान और कर्मचारियों के लिए	2,44,545	3,014
2. ई.सी. और उसकी समितियों की बैठक के लिए	3,11,765	15,063
3. शाखाओं के पदाधिकारियों एवं अन्य के लिए	1,26,663	-
विज्ञापन व्यय	17,077	-
कर्मचारियों को सुविधाएं	1,18,774	1,48,525
वार्षिक रिपोर्ट	48,036	1,30,268
बैंक शुल्क	34,331	55,920
निबंध/केस अध्ययन पुरस्कार	25,287	41,000
एजीएम के लिए खर्च	2,53,445	33,357
सम्मेलन हेतु व्यय	1,12,800	13,905
लेखापरीक्षकों को शुल्क	1,30,000	1,30,000
विशेषज्ञों को मानदेय	1,24,400	2,36,500
मेस कैटीन के लिए आईजीएल गैस	4,04,897	2,50,848
कानूनी खर्चे	52,800	39,600
स्थानीय यात्रा खर्चे	1,04,456	25,938
बैठक संबंधी खर्चे	67,014	1,19,065
विविध खर्चे	19,15,287	17,26,723
मोटर कार खर्चे	4,50,908	2,17,646
डाक एवं टेलीग्राम	1,17,814	43,027
डिजिटल सामग्री की तैयारी	34,29,850	7,10,980
छपाई और स्टेशनरी	7,94,437	4,66,365
मरम्मत, रखरखाव, फोटोकॉपी मशीन/एएमसी	10,48,409	3,26,824
टेलीफोन खर्चे	5,71,579	4,34,536
कुल	1,05,04,574	51,69,104

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची ए

भारत सरकार से सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियों की प्राप्ति और भुगतान खाता

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
प्राप्तियां:		
डीओपीटी से सहायता अनुदान - वेतन	10,99,93,000	11,20,00,000
डीओपीटी-जनरल से सहायता अनुदान	9,00,00,000	8,25,50,000
डीओपीटी-कैपिटल से सहायता अनुदान	12,01,00,000	8,91,50,000
सदस्यता अंशदान	12,03,987	8,62,922
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्क	9,44,68,841	6,10,98,213
ओवरहेड शुल्क सहित अनुसंधान कार्यों से शुद्ध आय	1,59,46,884	2,28,67,235
उपयोगकर्ता शुल्क	1,43,67,367	50,24,394
प्रकाशनों की बिक्री	8,72,219	3,28,250
विविध प्राप्तियां	56,50,222	55,08,519
कुल	45,26,02,520	37,93,89,533
भुगतान:		
वेतन एवं भत्ते	12,50,66,128	12,03,77,108
पेंशन	8,31,00,000	7,88,00,000
पूँजीगत व्यय	12,01,00,000	8,91,50,000
आईआईपीए भवन आदि		
प्रशिक्षण कार्यक्रम	6,82,54,175	5,02,27,263
प्रकाशनों	8,47,432	6,95,775
पुस्तकालय की किताबें, पत्रिकाएँ, बाइंडिंग और उपकरण शुल्क	15,59,993	3,34,156
शाखाएँ संवर्धन गतिविधियाँ	10,69,601	8,93,183
कैम्पस रखरखाव	3,76,28,223	2,49,03,497
प्रशासनिक एवं विविध खर्च	1,00,06,627	53,70,038
स्वयं की निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	25,51,339	7,46,923
सीजीएचएस को भुगतान की गई धनराशि	14,44,592	50,86,808
जीएसटी/प्रीमियम खर्च	9,15,600	30,39,118
कुल	45,25,43,710	37,96,23,869
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	58,810	(2,34,336)
पिछले वर्ष के भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	(7,82,854)	(5,48,518)
भुगतान से अधिक प्राप्तियों का कुल आधिक्य	(7,24,044)	(7,82,854)

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान वेतन/सामान्य/पूँजीगत धनराशि रु.32,00,93,000/- प्राप्त हुई थी, वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग किया गया है। इसके अलावा, इस संस्थान ने वर्ष 2022-23 के दौरान रु.13,25,09,520/- का आंतरिक राजस्व उत्पन्न किया है और रु.7,82,854/- रुपये के भुगतान पर प्राप्तियों की अधिकता को पिछले वर्ष, यानी वर्ष 2021-22 से आगे बढ़ाया गया है। जैसा कि प्राप्तियां और भुगतान खातों की अनुसूची संख्या ए में दर्शाया गया है, दिनांक 31-3-2023 को प्राप्तियों से अधिक भुगतान की शेष राशि रु.7,24,044/- को अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समायोजन के लिए ले जाया गया है।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,

पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास,

नई दिल्ली-110017

स्थान : नई दिल्ली

कार्यकारी परिषद के लिए

एस.एन. त्रिपाठी

महानिदेशक

(सदस्य सचिव)

के.के. पांडेय

(सदस्य-कार्यकारी

परिषद)

अमिताभ रंजन

कुलसचिव

(मुख्य लेखा अधिकारी)

यूडीआईएन नंबर

23083899बीजीएक्सयूजीए4719

दिनांक : 22/09/2023

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची बी

निधि, जमा और अग्रिम, किराये की आय की प्राप्ति और भुगतान खाता

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
प्राप्तियां:		
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	6,006	4,221
भूपेन्द्र हूजा मेमोरियल निधि	2,079	2,019
परामर्श सहायता निधि	84,373	78,774
आईआईपीए रिजर्व निधि	51,73,199	-
अवसंरचना विकास निधि	42,33,245	17,39,305
न्यादुम्मा मेमोरियल निधि	-	46,715
प्रो. एस. सरोजा मेमोरियल निधि	38,243	25,947
अनुसंधान बंदोबस्ती निधि	16,42,214	3,14,558
श्रीमती कुसुमताई मेमोरियल निधि	7,122	7,721
कर्मचारी हितैषी निधि	36,597	48,491
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार निधि	7,000	4,935
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल निधि	88,210	87,939
यूसी अग्रवाल मेमोरियल निधि	1,65,000	1,79,010
कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी निधि	1,70,414	2,04,122
आजीवन सदस्यता पूंजी निधि (उप)	28,44,463	16,59,998
एसटीडीआर पर ब्याज	46,11,927	55,54,249
किराये की आय - एमओटी, सीसीपीए, यूसीओ इत्यादि	2,07,69,092	4,21,49,623
स्टाफ/संकाय से अग्रिम वसूली योग्य	2,14,34,011	2,02,64,037
स्टाफ को देय धनराशि	63,191	74,114
बैंक में सावधि जमा	16,57,24,793	17,42,44,729
जीएसटी इनपुट संचयी	-	2,58,152
शुल्क और कर (जीएसटी)	1,16,97,489	2,85,50,891
वर्तमान संपत्ति अन्य	4,47,76,547	20,69,219
एचबीए पर अर्जित ब्याज	-	74,191
मेस शुल्क	62,383	1,04,478
अन्य जमा (देयता)	13,23,935	12,31,394
अन्य देनदारियां	4,37,58,976	9,48,79,206
अन्य देनदारियाँ (विविध लेनदार)	28,73,805	2,44,81,525
विविध देनदार	51,55,000	1,51,58,205
प्राप्य टीडीएस	-	1,16,78,540
पेन्शन/जीपीएफ/सीपीएफ से प्राप्त धनराशि	-	1,04,76,689
टीडीएस	2,14,35,121	-
अन्य	-	1,20,78,219
महा योग	35,81,84,435	44,77,31,216

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
भुगतान		
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	-	508
कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी निधि	1,70,414	2,04,122
आजीवन सदस्यता पूंजी निधि (उप)	9,47,461	6,00,000
आईआईपीए रिजर्व निधि	4,79,578	17,60,624
अवसंरचना विकास निधि	-	-
अनुसंधान अक्षयनिधि	25,616	77,753
कर्मचारी हितैषी निधि	5,000	18,000
न्यादुम्मा मेमोरियल निधि	-	-
टी.एन. चतुर्वेदी निधि	9,130	-
पी.के. उमाशंकर मेमोरियल निधि	-	-
यूसी अग्रवाल मेमोरियल निधि	5,000	-
स्टाफ को देय धनराशि	-	2,52,000
स्टाफ/संकाय से अग्रिम वसूली योग्य	2,30,29,513	2,13,37,173
वर्तमान परिसंपत्ति अन्य	37,39,351	92,71,613
जमा (परिसंपत्ति)	11,52,039	-
वर्ष के दौरान देय खर्च	55,75,899	77,12,254
बैंक में सावधि जमा	23,88,37,242	20,05,96,732
जीएसटी इनपुट संचयी/प्राप्य	-	40,89,942
शुल्क और कर (जीएसटी)	2,99,96,657	1,54,79,475
मेस शुल्क	-	2,98,436
अन्य जमा (देयता)	9,75,289	14,45,288
अन्य देनदारियाँ	6,64,64,508	9,69,23,592
अन्य देनदारियाँ (विविध लेनदार)	26,44,682	14,18,145
विविध देनदार	56,64,600	17,70,500
टीडीएस/टीसीएस प्राप्य	70,38,722	1,50,56,543
जीएसटी पर टीडीएस	8,91,120	5,70,867
अग्रिम कर	-	86,77,613
सीपीएफ/जीपीएफ से प्राप्य राशि	-	5,57,000
टीडीएस	2,14,32,839	-
महा योग	40,90,84,660	38,81,18,180

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1
(संदर्भ अनुसूची-3)

अनुसंधान परियोजनाओं की रसीदें एवं भुगतान खाता (देय सहित)
(एफसीआरए अनुदान को छोड़कर)

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
प्राप्तियां :		
पूँजीगत सहायता अनुदान	12,01,00,000	8,91,50,000
शहरी अध्ययन केंद्र के लिए आवासन और शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से अनुदान (प्रकाशन की बिक्री सहित)	3,23,66,390	3,40,99,705
एपीपीपीए विदेश एवं क्षेत्र दौरा	86,00,000	53,57,424
अन्य कार्यक्रम	1,42,49,157	93,26,500
उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	-	1,32,76,739
अन्य अनुसंधान परियोजना/अध्ययन	3,17,56,771	4,88,34,249
आईसीएसएसआर फैलोशिप अनुदान	1,45,000	7,09,999
एपीपीपीए I	2,86,51,120	1,74,45,340
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	-	2,11,142
आईसीजीआरएस-एनसीएच	1,56,15,864	2,25,91,560
कॉट्रेक्स	-	-
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई)	2,52,32,099	21,50,000
कुल	27,67,16,401	24,31,52,658
भुगतान :		
पूँजीगत सहायता अनुदान	12,01,00,000	8,91,50,000
शहरी अध्ययन केंद्र	3,23,65,991	3,07,34,200
एपीपीपीए विदेश एवं क्षेत्र दौरा	61,09,728	42,35,053
अन्य कार्यक्रम	1,06,83,266	67,44,408
उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	43,71,948	99,28,127
अनुसंधान परियोजना/अध्ययन	4,46,52,918	5,45,82,749
आईसीएसएसआर फैलोशिप खर्च	5,23,871	2,89,999
एपीपीपीए I	70,22,181	67,81,740
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	-	2,11,142
आईसीजीआरएस-एनसीएच	1,16,61,972	4,29,13,112
कॉट्रेक्स	1,63,059	1,39,046
राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान (एनटीआरआई)	1,16,11,233	37,24,834
व्यय से अधिक प्राप्ति	2,74,50,234	(62,81,752)
कुल	27,67,16,401	24,31,52,658

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-2 (संदर्भ अनुसूची-3)

शहरी अध्ययन केंद्र के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
प्राप्तियां :		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,22,00,000	3,40,00,000
विविध प्राप्तियां	1,66,390	99,705
कुल	3,23,66,390	3,40,99,705
भुगतान :		
वेतन एवं भत्ते	2,37,42,322	2,43,34,154
आधारभूत संरचना	3,47,850	4,19,516
यात्रा खर्चे	3,76,503	5,45,811
पुस्तकालय पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	3,33,669	3,31,169
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3,65,964	6,50,000
विविध एवं आकस्मिक खर्चे	1,62,126	1,63,009
छपाई और स्टेशनरी	37,558	74,688
कैम्पस रखरखाव	9,72,724	6,74,625
प्रकाशन की छपाई	1,26,155	1,42,106
पानी और बिजली	6,57,794	5,85,795
अनुसंधान/केस अध्ययन	14,32,474	1,92,999
ओवरहेड शुल्क	26,30,438	26,20,328
श्रव्य-दृश्य उपकरण एवं प्रशिक्षण व्यय	11,80,414	-
	3,23,65,991	3,07,34,200
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	399	33,65,506
पिछले वर्ष के भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	(114)	(33,65,620)
कुल	285	(114)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-3 (संदर्भ अनुसूची-3)

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के लिए उपभोक्ता कार्य मंत्रालय से
अनुदान की प्राप्तियां एवं भुगतान खाता

प्राप्तियां :

वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
		1,32,76,739
कुल	-	1,32,76,739

भुगतान :

संचार

1,230 1,48,985

आधारभूत संरचना

80,000 2,08,980

पुस्तकालय पुस्तकें

- 94,354

विविध खर्च

5,489 1,20,722

वेतन एवं भत्ते

16,78,973 74,69,921

प्रकाशनों

- 2,744

शोध अध्ययन

11,07,705 8,845

सेमिनार/कार्यशाला

2,00,000 -

प्रशिक्षण कार्यक्रम

3,00,000 -

यात्रा व्यय

2,086 10,026

ओवरहेड शुल्क

9,96,465 18,63,550

43,71,948 99,28,127

वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ

(43,71,948) 33,48,613

पिछले वर्ष के भुगतान से अधिका प्राप्तियाँ

(92,66,780) (1,26,15,392)

कुल (1,36,38,728) (92,66,780)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-4
(संदर्भ अनुसूची-3)

एनसीएच के माध्यम से एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण
प्रणाली हेतु उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

	वर्ष 2022-23 के लिए (₹)	वर्ष 2021-22 के लिए (₹)
प्राप्तियां :		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,53,48,790	2,10,38,000
विविध प्राप्तियां	2,67,074	15,53,560
कुल	1,56,15,864	2,25,91,560
भुगतान :		
एससीएच सहित संचार खर्च	25,62,327	1,01,35,435
एससीएच सहित बुनियादी ढाँचा व्यय	2,23,528	15,88,570
श्रमशक्ति	52,99,351	2,28,48,390
विविध खर्च	48,666	83,725
एससीएच सहित मुद्रण एवं स्टेशनरी	55,899	75,042
कर्मचारी कल्याण	1,35,229	2,83,916
प्रशिक्षण	1,90,000	60,000
एससीएच सहित यात्रा खर्च	4,208	4,744
वेबसाइट खर्च	24,237	36,800
संस्थागत शुल्क	31,18,527	77,96,490
	1,16,61,972	4,29,13,112
वर्ष के दौरान भुगतान से अधिक प्राप्तियाँ	39,53,892	(2,03,21,552)
पिछले वर्ष की प्राप्तियों से अधिक भुगतान	(1,69,97,977)	33,23,575
कुल	(1,30,44,085)	(1,69,97,977)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-14

खातों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स

1. पृष्ठभूमि

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का उद्घाटन 29 मार्च, 1954 को हुआ था। इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य ऐसी शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करना था जिससे सरकार और अन्य सार्वजनिक सेवा संगठनों में अधिकारी नेतृत्व गुणों और प्रबंधकीय क्षमताओं में वृद्धि हो सके और सिविल सेवाओं की औपनिवेशिक मानसिकता को बदलें।

2. लेखांकन की विधि

संस्थान का वित्तीय विवरण 'प्रोद्भवन आधार' पर तैयार किया गया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। दिल्ली कार्यालय में लेनदेन के संबंध में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

क) स्थायी परिसंपत्तियां

- 31 मार्च 2012 तक, स्वयं के स्रोतों से अर्जित परिसंपत्ति को तुलन पत्र में संपत्ति निधि खाते में संबंधित प्रविष्टि के साथ लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2012-13 में लेखांकन प्रणाली को नकद से संचय में परिवर्तित करने के समय, स्वयं के स्रोत से अर्जित संपत्ति को पूंजीगत वस्तु के रूप में माना गया है और स्थायी परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकृत किया गया है। पूंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 5 वर्ष मानी गई है अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से स्वयं के स्रोत से अर्जित संपत्ति को पूंजीकृत कर दिया गया है। भूमि, भवन और पुस्तकों का मूल्य 31 मार्च, 2013 तक वित्तीय रिकॉर्ड से लिया गया है।
- प्रायोजित परियोजनाओं और कार्यक्रम के अनुदान प्राप्त निधि से बनाई गई परिसंपत्ति, जहां ऐसी परिसंपत्ति का स्वामित्व संस्थान में निहित है, उसको परिसंपत्ति निधि के अनुरूप क्रेडिट के साथ संस्थान की स्थायी परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। हालाँकि, ऐसी परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहास का दावा नहीं किया जाता है जो निधियों से अर्जित किये गये हैं।
- स्थायी संपत्तियों को अधिग्रहण की लागत (आवक माल दुलाई, शुल्क, कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित) से संचित मूल्यहास घटाकर बताया जाता है।

ख) सहायता अनुदान

- सहायता अनुदान वेतन और आवर्ती व्यय के लिए प्राप्त सामान्य को प्राप्त होने पर आय माना जाता है।
- पूंजीगत व्यय के लिए सहायता अनुदान जैसे स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- निर्दिष्ट असाइनमेंट के लिए सहायता अनुदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए प्राप्त अनुदान और अप्रयुक्त अनुदान को आगे बढ़ाया जाता है और तुलनपत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि व्यय प्राप्त अनुदान से अधिक है तो उसे अनुदान प्राप्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

- अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने पर अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों पर अधिशेष/घाटे को आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है।
 - चल रही प्रायोजित परियोजनाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रम के संबंध में, ऐसी परियोजना का व्यय ऐसी निर्दिष्ट परियोजना से डेबिट किया जाता है। परियोजनाओं से वसूले गए ओवरहेड प्रभार को संस्थान की आय माना जाता है।
- ग)** प्राप्त जीवन/कॉर्पोरेट सदस्यता शुल्क को आय के रूप में नहीं माना जाता है और इसके बजाय इसे विशिष्ट निधि यानी जीवन/कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- घ)** जीवन/कॉर्पोरेट सदस्यता पूंजी निधि के प्रति किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज को संबंधित निधि में अंतरित कर दिया जाता है और इसे आय के रूप में नहीं माना जाता है, जबकि सामान्य निधि पर प्राप्त ब्याज का 50 प्रतिशत आय में अंतरित किया जाता है और शेष 50% शाखाओं को देय के रूप में दिखाया जाता है।
- ङ.)** गृह निर्माण और अन्य अग्रिमों के लिए कर्मचारियों को दिए गए ब्याज वाले अग्रिमों पर आय का हिसाब संचय के आधार पर किया जाता है, हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन की पूरी चुकौती के बाद शुरू होती है।
- च)** पूंजीगत निधि से संबंधित आय और व्यय संबंधित पूंजी निधि में क्रेडिट/डेबिट किए जाते हैं।
- छ)** दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को आयकर महानिदेशक से प्राप्त कर छूट प्रमाण पत्र के मद्देनजर आयकर के लिए किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।
- ज)** विदेशी मुद्रा लेनदेन का हिसाब-किताब लेनदेन की तिथि पर प्रचलित दर पर किया जाता है। हालाँकि, वर्ष के अंत में मौद्रिक लेनदेन वर्ष के अंत की दर पर बताए गए हैं।
- i)** विभिन्न गतिविधियों से आय और व्यय को छोड़कर, संचय के आधार पर हिसाब लगाया गया है
- सदस्यता शुल्क प्राप्तियां, जिसका हिसाब-किताब प्राप्त होने पर किया जाता है।
 - छात्रवास के कमरों से प्राप्त प्राप्तियों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।
 - छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है।
 - शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में मानी जाती है।
 - प्रवेश फॉर्म की बिक्री नकद आधार पर की जाती है।
 - प्रकाशनों की बिक्री पर रॉयल्टी प्राप्त हुई।

3. स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास

- प्राप्त अनुदान/प्रायोजित निधि से अर्जित परिसंपत्तियों के अलावा अन्य पर मूल्यहास, आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर लिखित पद्धति के तहत लगाया गया है।
- वाहन 15%
- कार्यालय उपकरण 15%
- कंप्यूटर 40%
- फर्नीचर 10%
- 30 सितंबर के बाद अर्जित परिसंपत्ति के मामले में लागू दर का 50% मूल्यहास लगाया जाता है।

- रु. 5,000/- से कम लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है।

ख) खातों के लिए नोट्स

- वित्तीय विवरण के प्रयोजन के लिए, स्थायी परिसंपत्तियों के बुक बैलेंस को स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत माना गया है।
- कर्मचारियों को दिए गए खर्चों के लिए अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं। वित्तीय विवरण के प्रयोजन के लिए, वित्तीय पुस्तकों के अनुसार वसूली योग्य धनराशि को प्राप्य माना गया है। स्टाफ सदस्यों/संकाय सदस्यों से शेष धनराशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- भुगतान के समय टीडीएस काटा गया है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है, जहां भी आवश्यक हो, फिर से तैयार किया गया है और फिर से व्यवस्थित किया गया है।

कार्यकारिणी परिषद के लिए

एस.एन. त्रिपाठी
महानिदेशक
सदस्य सचिव

के.के. पांडेय
सदस्य
कार्यकारिणी परिषद

अमिताभ रंजन
कुल सचिव
(मुख्य लेखा परीक्षक अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीए4719

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यों को

पेंशन निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान- पेंशन निधि का संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

- रु. 5.04 करोड़ के बांड में निवेश के संरक्षक की ओर से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। हमारा सुझाव है कि केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बाद होल्डिंग की पुष्टि की जानी चाहिए।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- (ii) हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) रखे गये हैं जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;
- (iii) इस रिपोर्ट में बताए गए तुलनपत्र तथा आय और व्यय खाते, बही खाते (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) के अनुरूप हैं।
- (iv) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर नोट्स (अनुसूची-3) के साथ पठित उक्त खाते, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:-

क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2023 तक निधि के मामलों की स्थिति; और

ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

साझेदार

एम. नंबर 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीडी4087

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

स्थान: नई दिल्ली

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

	अनुसूची	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
देयताएं			
कोर्पस	1	13,24,15,198	11,70,28,353
दीर्घकालिक देयताएं		1,45,69,00,000	1,43,35,00,000
वर्तमान देयताएं		72,65,322	-
कुल		1,59,65,80,520	1,55,05,28,353
परिसंपत्ति			
निवेश	2	6,64,98,774	5,70,43,774
टीडीएस प्राप्य		22,184	9,989
एसबीआई में शेष धनराशि		7,15,03,562	5,99,74,590
भा.लो.प्र.सं. से प्राप्य राशि		1,45,69,00,000	1,43,35,00,000
प्रीपेड प्रीमियम		16,56,000	-
कुल		1,59,65,80,520	1,55,05,28,353

लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स 3

अनुसूचियाँ 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
(चर्चित लेखापाल)

एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

कार्यकारिणी परिषद के लिए

(सुनील अग्रवाल)

साझेदार

एम.नम्बर 083899

16 डी.डी.ए. फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर,

पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीडी4087

दिनांक 22 सितंबर, 2023

सदस्य सचिव

कुल सचिव

मुख्य लेखा अधिकारी

अध्यक्ष

महानिदेशक

सदस्य

कार्यकारी परिषद

सदस्य

भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी

संघ

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (₹)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
डीओपीटी से मिली धनराशि	8,31,00,000	7,88,00,000
भा.लो.प्र.सं. से प्राप्त धनराशि	1,80,93,235	1,30,84,219
ब्याज आय		
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	42,66,467	48,97,317
बचत ब्याज	3,13,933	5,09,477
कुल - ए	10,57,73,635	9,72,91,013
व्यय		
(जैसा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)		
पेंशन का कम्प्यूटेड मूल्य	40,01,951	70,08,521
मासिक पेंशन का भुगतान	8,63,97,977	7,20,27,453
बैंक प्रभार	47	-
प्रीमियम/डीमैट शुल्क	5,43,368	-
कुल - बी (ए.बी.)	9,09,43,344	7,90,35,974
वर्ष के लिए अधिशेष (घाटा)/पिछले वर्ष से अधिशेष	1,48,30,291	1,82,55,039
तुलनपत्र (बैलेंस शीट) में ले जाया गया लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स अनुसूचियाँ 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी (चर्चित लेखापाल) एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339	2,13,25,086	30,70,047
	3,61,55,377	2,13,25,086

कार्यकारिणी परिषद के लिए

(सुनील अग्रवाल)	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	सदस्य
साझेदार	कुल सचिव	महानिदेशक	कार्यकारी परिषद
एम.नम्बर 083899	मुख्य लेखा अधिकारी		
16 डी.डी.ए. फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर, पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़, मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017			सदस्य भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ
स्थान: नई दिल्ली			
यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीडी4087			
दिनांक 22 सितंबर, 2023			

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-1

कोर्पस

		31-03-2023 को समाप्त वर्ष (₹)	31-03-2022 को समाप्त वर्ष (₹)
सरकारी अनुदान		5,50,71,000	5,50,71,000
एरियर के लिए अनुदान प्राप्त हुआ		73,27,000	73,27,000
नियोक्ता के हिस्से का अंतरण सीपीएफ से - बी/एफ	1,72,70,529		
जोड़ें: प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पेन्शन अंशदान जोड़ें: आय एवं व्यय खाते से अंतरित	1,65,91,292	3,38,61,821	3,33,05,267
		3,61,55,377	2,13,25,086
कुल		13,24,15,198	11,70,28,353

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-2

निवेश

	31-03-2023	31-03-2022
	तक	तक
	(₹)	(₹)
(ए) विशेष जमा योजना एसबीआई आईपी एस्टेट	68,774	68,774
एसबीआई में एफडीआर	50,00,000	50,00,000
(बी) केंद्र सरकार प्रतिभूति		
8.15% भारत सरकार एफसीआई विशेष बांड 2022	-	5,45,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	5,15,000	5,15,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	20,00,000	20,00,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	10,25,000	10,25,000
8.26% भारत सरकार 2027	40,00,000	40,00,000
8.64% यूनियन बैंक प्रेप. बॉन्ड	1,00,00,000	1,00,00,000
8.25% बैंक अकाल बड़ौदा प्रेप. बॉन्ड	1,10,00,000	1,10,00,000
9.15% पीएनबी प्रेप. बॉन्ड	2,00,00,000	2,00,00,000
8.74% बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रेप. बॉन्ड 2027	1,00,00,000	-
कुल (ए+बी)	6,36,08,774	5,41,53,774
(सी) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आदि बांड्स		
(40% श्रेणी)		
9.45% एसबीआई लोअर टियर II 2026	28,90,000	28,90,000
कुल (सी)	28,90,000	28,90,000
कुल (ए+बी+सी)	6,64,98,774	5,70,43,774

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यों को सामान्य भविष्य निधि

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान- सामान्य भविष्य निधि का संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का ऑडिट किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा ऑडिट हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

हम इसकी रिपोर्ट करते हैं:-

बी) 7.06 करोड़ रुपये के बांड में निवेश के संरक्षक की ओर से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। हमारा सुझाव है कि केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बाद होल्डिंग की पुष्टि की जानी चाहिए।

सी) जीपी फंड के तहत विशेष जमा योजना की 87.24 लाख रुपये की शेष धनराशि को अद्यतन पासबुक के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- (ii) हमारी राय में, जहां तक उन बही खातों की हमारी जांच से पता चलता है, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते रखे गये हैं;
- (iii) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलनपत्र और आय एवं व्यय खाता, बही खाते के अनुरूप है;
- (iv) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर नोट्स (अनुसूची- 3) के साथ पढ़े गए उक्त खाते, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:-

क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2023 तक निधि के मामलों की स्थिति; और

ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

साझेदार

एम. नंबर 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीसी6235

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि
31 मार्च, 2023 तक तुलन-पत्र

	अनुसूची	31.3.2023 तक (₹)	31.3.2022 तक (₹)
देयताएं			
संचित पात्रता	1	10,47,42,676	10,02,49,437
अवितरित ब्याज (ब्याज अंशदान में घटा)		(59,05,600)	(59,10,867)
वर्तमान देयताएँ		-	10,410
(आय एवं व्यय खाता के अनुसार)			
कुल		9,88,37,077	9,43,48,980

परिसंपत्ति

निवेश	2	8,06,94,356	8,19,49,356
एसबीआई में शेष धनराशि		1,48,17,778.01	87,16,843
सदस्यता हेतु अग्रिम		1,73,676.00	5,31,514
प्राप्य टीडीएस		1,91,268.00	1,91,268
सीपी निधि से प्राप्य धनराशि		29,60,000.00	29,60,000
कुल		9,88,37,077	9,43,48,980

लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स
अनुसूचियाँ 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,

पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन नं.: 23083899बीजीएक्सयूजीसी6235

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

सदस्य-सचिव
कुलसचिव
(मुख्य लेखा अधिकारी)

सदस्य
भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ

कार्यकारी परिषद के लिए

सदस्य
(कार्यकारी परिषद,
भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(महानिदेशक,
भा.लो.प्र.सं.)

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (₹)	31-03-2022 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	71,17,616	74,63,114
कुल	71,17,616	74,63,114
व्यय		
(i) सदस्यों के अंशदान में जमा किया गया ब्याज	71,07,441	59,03,073
(ii) बैंक प्रभार	-	0
(iii) प्रीमियम	-	0
(iv) डीमैट शुल्क	4,816	0
(v) आयकर के लिए प्रावधान	90	10,410
पिछला वर्ष कम/अधिक	1	10
कुल	71,12,348	59,13,493
वर्ष के लिए अधिशेष/घाटा	5,268	15,49,621
पिछले वर्ष अवितरित ब्याज	(59,10,867)	(74,60,487)
कुल अवितरित ब्याज को बैलेंस शीट में अग्रेनीत किया गया	(59,05,600)	(59,10,867)

लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स
अनुसूचियाँ 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

3

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,
पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास,

नई दिल्ली-110017

स्थान : नई दिल्ली

यूडीआईएन:

23083899बीजीएक्सयूजीसी6235

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

सदस्य-सचिव

कुलसचिव

(मुख्य लेखा अधिकारी)

सदस्य

(कार्यकारी परिषद,

भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य

भा.लो.प्र.सं.

कर्मचारी संघ

कार्यकारी परिषद के लिए

अध्यक्ष

(महानिदेशक)

भा.लो.प्र.सं.

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-1

संचित सदस्यों की पात्रता

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
	(₹)	(₹)
आरभिक जमा	10,02,49,437	10,88,41,945
वर्ष के दौरान अंशदान	1,42,17,900	1,35,49,200
ब्याज जमा किया गया	71,07,441	66,65,285
	12,15,74,778	12,90,56,430
घटाएं:		
सदस्यों के खातों का निपटान	1,08,43,102	1,95,09,993
अंतिम वापसी (निकाली गई)	59,89,000	92,97,000
कुल	10,47,42,676	10,02,49,437

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-2

निवेश

	31.03.2023	31.03.2022
	तक	तक
	(₹)	(₹)
(ए) विशेष जमा योजना एसबीआई आईपी एस्टेट	87,24,356	87,24,356
(बी) अन्य निवेश		
8.15% भारत सरकार एफसीआई विशेष बांड 2022	-	12,55,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	9,70,000	9,70,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	20,00,000	20,00,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बांड 2024	30,00,000	30,00,000
8.98% पीएफसी प्रेप. बॉन्ड	1,00,00,000	1,00,00,000
9.50% एसबीआई प्रेप. बॉन्ड	70,00,000	70,00,000
9.45% एसबीआई प्रेप. बॉन्ड	1,00,00,000	1,00,00,000
8.95% आईआरएफसी बॉन्ड 2025	40,00,000	40,00,000
9.35% पीजीसी बॉन्ड 2023	40,00,000	40,00,000
8.28% नाबार्ड 2028	1,00,00,000	1,00,00,000
8.25% बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेप. बॉन्ड	1,10,00,000	1,10,00,000
9.15% पीएनबी प्रेप. बॉन्ड	1,00,00,000	1,00,00,000
कुल	8,06,94,356	8,19,49,356

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यों को

अंशदायी भविष्य निधि- भा.लो.प्र.सं

हमने 31 मार्च, 2023 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान- अंशदायी भविष्य निधि का संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं अथवा नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

(ए) संस्थान के पास रु.1.02 करोड़ की स्क्रिप्स भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थीं। हमारा सुझाव है कि केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बाद होल्डिंग की पुष्टि की जानी चाहिए।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खाते (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) रखे गये हैं जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;
- इस रिपोर्ट में बताए गए तुलनपत्र तथा आय और व्यय खाते, बही खाते (बुक्स ऑफ अकाउंट्स) के अनुरूप हैं।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, खातों पर नोट्स (अनुसूची-3) के साथ पठित उक्त खाते, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:-

क) तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च, 2023 तक निधि के मामलों की स्थिति; और

ख) आय और व्यय खाते के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

ग) प्राप्तियों एवं भुगतान के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निधि प्रवाह।

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन - 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

साझेदार

एम. नंबर 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, शिवालिक मोड़,

मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली-110017

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23083899बीजीएक्सयूजीसी6235

दिनांक: 22 सितंबर, 2023

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2023 तक तुलनपत्र

	अनुसूची	31.03.2023 तक (₹)	31.03.2022 तक (₹)
देयताएं			
संचित बैलेंस	1	25,75,663	16,79,763
अवितरित ब्याज		(2,28,553)	(9,73,937)
जी.पी. को देय राशि धननिधि		29,60,000	29,60,000
भा.लो.प्र.सं. को देय धनराशि		97,85,000	97,85,000
	कुल	1,50,92,110	1,34,50,826
परिसंपत्ति			
निवेश	2	1,21,60,000	1,16,60,000
एसबीआई में बैलेंस		29,32,110	17,90,826
	कुल	1,50,92,110	1,34,50,826

लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स
अनुसूचियाँ 1 से 3 खातों का अभिन्न अंग हैं
हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल

भागीदार

एम. नं. 083899

16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,

पंचश्रील पार्क, शिवालिंक मोड़,

मालवीय नगर के पास,

नई दिल्ली-110017

स्थान : नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

कुलसचिव,

भा.लो.प्र.सं.

(मुख्य लेखा अधिकारी)

सदस्य

(कार्यकारी परिषद,

भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य

भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ

कार्यकारी परिषद

के लिए

अध्यक्ष

(महानिदेशक,

भा.लो.प्र.सं.)

यूडीआईएन नंबर: 23083899बीजीएक्सयूजीसी6235

दिनांक: 22/09/2023

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय तुलनपत्र

	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (₹)	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	8,75,197	7,35,904
	8,75,197	7,35,904
व्यय		
ए. के लिए क्रेडिट ब्याज		
- सदस्यों का अंशदान	86,199	36,660
- नियोक्ता का अंशदान	39,701	19,170
बी. बैंक, डिमेट एवं डाक प्रभार	3,913	
	1,29,813	55,830
वर्ष हेतु अधिशेष (सरप्लस)/ घाटा	7,45,384	6,80,075
पिछले वर्ष से अवितरित ब्याज तुलन	(9,73,937)	(16,54,012)
पत्र में ले जाया गया	(2,28,553)	(9,73,937)

लेखांकन नीतियां और खातों पर नोट्स
अनुसूचियाँ 1 से 4 खातों का अभिन्न अंग है

3

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएसए और एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
एम. नं. 083899
16, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर,
पंचशील पार्क, शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास,
नई दिल्ली-110017

सदस्य-सचिव
कुलसचिव,
भा.लो.प्र.सं.
(मुख्य लेखा अधिकारी)

सदस्य
भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी
संघ

कार्यकारी परिषद
के लिए

सदस्य
(कार्यकारी परिषद,
भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(महानिदेशक,
भा.लो.प्र.सं.)

यूडीआईएन नंबर: 23083899बीजीएक्सयूजीसी6235
दिनांक: 22/09/2023
स्थान : नई दिल्ली

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-1

	सदस्य का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	31.03.2023 को कुल	31-03-2022 को कुल
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
संचित पात्रता				
आरंभिक बैलेंस	10,39,245	6,40,518	16,79,763	8,07,433
वर्ष के दौरान अंशदान	5,00,000	2,70,000	7,70,000	8,16,500
ब्याज जमा किया गया	86,199	39,701	1,25,900	55,830
कुल:	16,25,444	9,50,219	25,75,663	# 16,79,763
घटाएँ: अंतिम भुगतान	-	-	-	-
	16,25,444	9,50,219	25,75,663	16,79,763

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

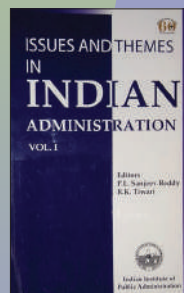
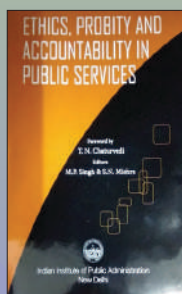
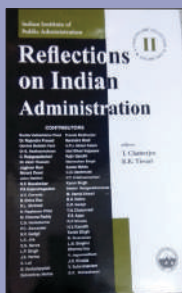
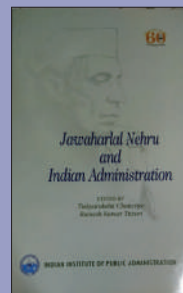
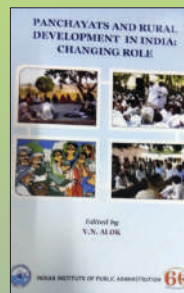
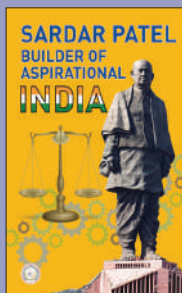
अनुसूची-2

निवेश

	31.03.2023	31.03.2022
	को	को
	(₹)	(₹)
एसबीआई में एफडीआर	19,50,000	12,50,000
(ए) अन्य निवेश		
8.15% भारत सरकार एफसीआई विशेष बॉन्ड 2022	-	2,00,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बॉन्ड 2024	6,25,000	6,25,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बॉन्ड 2024	2,50,000	2,50,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बॉन्ड 2024	3,75,000	3,75,000
8.26% भारत सरकार 2027	10,00,000	10,00,000
9.56% एसबीआई प्रेप.बॉन्ड	70,00,000	70,00,000
कुल (ए)	1,12,00,000	1,07,00,000
(बी) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान आदि बॉन्ड		
(40% श्रेणी)		
9.45% एसबीआई लोअर II 2026	9,60,000	9,60,000
8.92% यूको बैंक 2020	-	-
कुल (बी)	9,60,000	9,60,000
कुल (ए+बी)	1,21,60,000	1,16,60,000



IIPA PUBLICATIONS



FOR PURCHASE OF BOOKS KINDLY CONTACT:-

Assistant Publication Officer, Indian Institute of Public Administration,
Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi – 110002

Phone +91-11-23468300 | Fax +91-11-23702440
Email: helpdesk.iipa@gmail.com | iipa.org.in

Editorial Board

Editor in Chief

Surendra Nath Tripathi

Editor

Amitabh Ranjan

Joint Editor

Mithun Barua

Asstt. Editor

Meghna Chukkath



भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002
iipa.org.in